

Samyak

An Institute For Civil Services

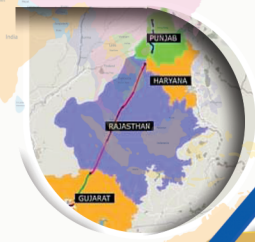
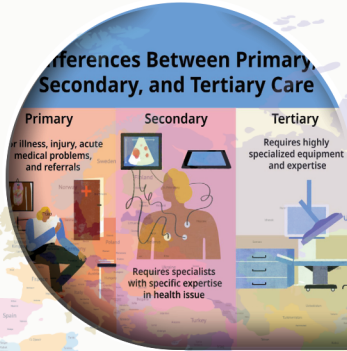
फरेंट अफेयर्स

मासिक समसामयिकी

मार्च - 2024

विशेष आकर्षण

- अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र
- राष्ट्रीय घटनाचक्र
- राजस्थान घटनाचक्र
- रक्षा/विज्ञान प्रौद्योगिकी
- आर्थिक घटनाचक्र
- खेल जगत



सभी प्रतियोगी परीक्षाओ के लिए उपयोगी

CURRENT AFFAIRS



INDEX

		पेज नं.
1	राजस्थान परिदृश्य	1 – 21
2	राष्ट्रीय परिदृश्य	22 – 26
3	आर्थिक परिदृश्य	27 – 28
4	अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य	29 – 34
5	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	35 – 41
6	खेल	42 – 44
7	पुरस्कार एवं सम्मान	45 – 49
8	चर्चित व्यक्तित्व	50 – 54
9	चर्चित स्थल	55 – 59
10	महत्त्वपूर्ण तथ्य	60 – 65
11	रिपोर्ट्स एवं इंडेक्स	66 – 68
12	प्रमुख दिवस एवं सप्ताह	69 – 71
13	सार : योजना - कुरुक्षेत्र	72 – 84
14	आलेख	85 – 92
15	टर्म इन न्यूज	93 – 95
	मॉडल प्रश्न	96 - 98

मासिक करेंट अफेयर्स

मार्च : 2024



Near Riddhi-Siddhi Circle, Gopalpura Bypass, Jaipur

1

राजस्थान परिदृश्य

नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान में 'रीति (RITI)' का गठन

- पूरा नाम: Rajasthan Institute for Transformation & Innovation (राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड इनोवेशन)
- गठन: 13 मार्च 2024 को (राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश से)
- पूर्ववर्ती संस्था: 'मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद्'
- अध्यक्ष: मुख्यमंत्री।
- उपाध्यक्ष: मुख्यमंत्री द्वारा मनोनयन।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी: आयोजना विभाग के प्रशासनिक सचिव।
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी: आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी।
- पूर्णकालिक सदस्य: मुख्यमंत्री द्वारा मनोनयन।
- योग्यता: ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, लोकसेवक, समाज सेवक अथवा उद्यमी होंगे।
- विशेष आमंत्रित सदस्य: विभिन्न विषयों से संबंधित प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ।
- विशेष आमंत्रित मंत्री: मुख्यमंत्री द्वारा नामित।

कार्य

- विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के विकास के लिए नीति तैयार कर सुझाव देना।
- विकसित राजस्थान 2047 का निर्माण तथा नीति निर्धारण
- राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की क्रियान्विति की समीक्षा कर उनमें सुधार के लिए सुझाव देना
- देश- विदेश में सफल नीतियों का अध्ययन कर राज्य में लागू किये जाने के संबंध में सुझाव देना।

राजस्थान में नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति

- राजस्थान द्वारा नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन लागू करने की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है।
- नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन में पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन कार्य किया जाएगा।

- इसके तहत 17.52 करोड़ रुपए व्यय होंगे तथा केन्द्र तथा राज्यों के वित्त पोषण का अनुपात 60:40 होगा।
- इस पूर्ण कम्प्यूटराइजेशन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, राजस्थान सरकार तथा राजस्थान विधानसभा सचिवालय के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (NeVA)

- यह भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है।
- इसका उद्देश्य सभी राज्य विधानसभाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल रूप में बदलकर पेपरलेस बनाना है।
- NeVA में एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप शामिल है।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में NeVA के कार्यान्वयन के लिये संसदीय कार्य मंत्रालय, 'नोडल मंत्रालय' है।

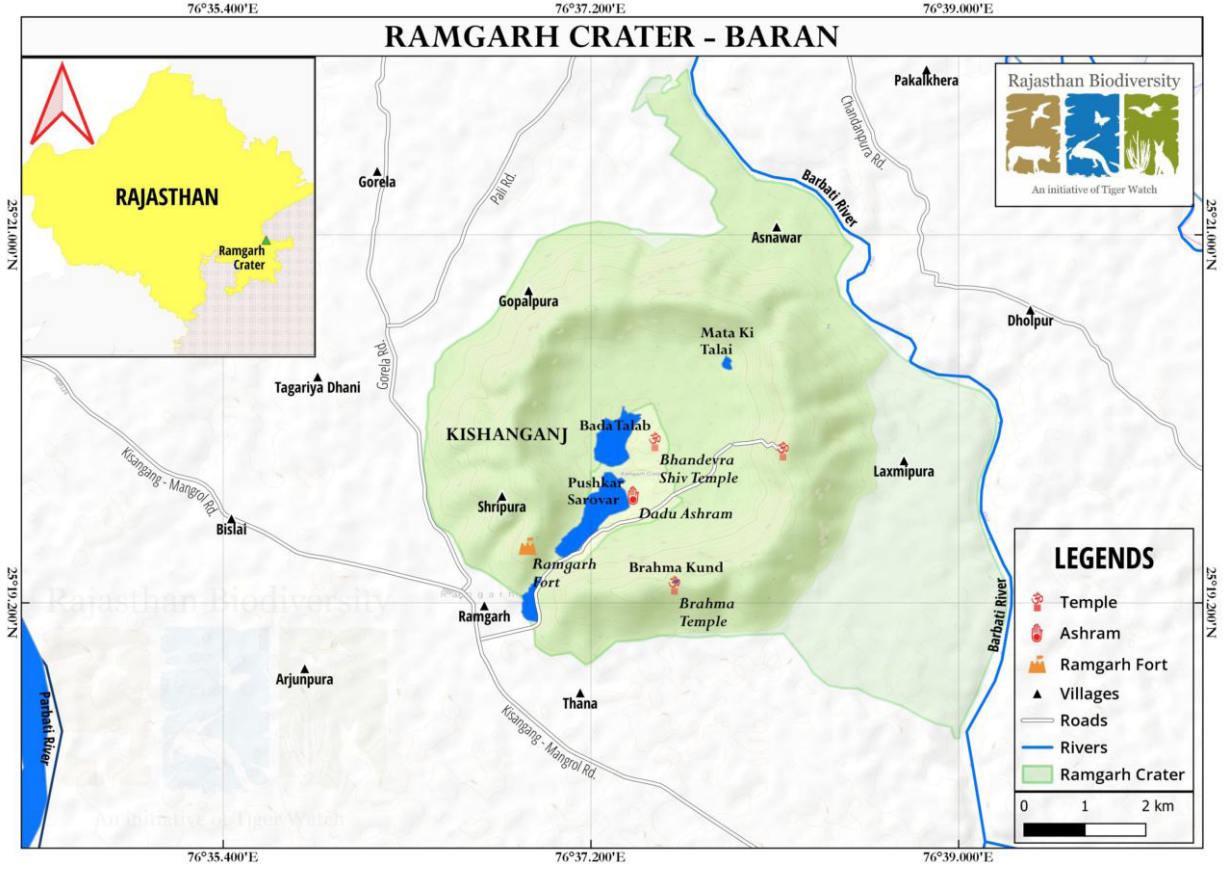
16वीं विधानसभा के प्रथम अधिवेशन का सत्रावसान

- 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम अधिवेशन का 7 मार्च 2024 को सत्रावसान किया गया।
- राजस्थान विधानसभा में अब प्रत्येक विधायक प्रत्येक सप्ताह में एक अंतःसत्र कालीन अतारकित प्रश्न पूछ सकते हैं।
- ऐसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सरकार को 30 दिवस की अवधि में सीधा सदस्य को अवश्य भेजना होगा और उत्तर की एक प्रति विधानसभा को भेजनी होगी।
- इसके अलावा राज्य के बजट सत्र में प्रत्येक विधायक निर्धारित 40 तारकित और 60 अतारकित प्रश्न पूछ सकते हैं।

रामगढ़ क्रेटर देश का पहला अधिसूचित भू-विरासत स्थल घोषित

- बारां का रामगढ़ क्रेटर को राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत की पहली जियो हैरिटेज साइट (अधिसूचित भू-विरासत स्थल घोषित किया है।
- रामगढ़ क्रेटर बारां जिला मुख्यालय से 40 किमी दूर स्थित है।

- इससे बारां को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी और इको टूरिज्म व वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर बढ़ावा मिलेगा।
- वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के अनुसार करीब 650 करोड़ साल पहले रामगढ़ क्षेत्र में एक उल्कापिंड गिरा था, जिससे यहां एक इंपैक्ट क्रेटर का निर्माण हुआ।



बारां के प्रमुख पर्यटन स्थल

- शाहाबाद किला
- बारां के धार्मिक स्थल भांड देवरा मंदिर
- शेरगढ़ किला
- शाहाबाद शाही जामा मस्जिद
- शेरगढ़ अभयारण्य
- सीताबाड़ी
- तपस्वियों की बगीची
- काकुनी मंदिर
- सोरसन वन्यजीव अभयारण्य
- सुरज कुंड
- ब्राह्मणी माता मंदिर
- नाहरगढ़ फोर्ट
- गुगोर किला

केन्द्र सरकार की सिटीज 2.0 योजना में राजस्थान के दो शहरों का चयन

- इसके तहत देश के कुल 18 शहरों का चयन हुआ, जिनमें राजस्थान के **जयपुर व उदयपुर** शहर शामिल हैं।

- इसका उद्देश्य शहरों को गारबेज फ्री (कचरा मुक्त) करने और कचरे का बेहतर ट्रांसपोर्टेशन करना है।
- इस प्रोजेक्ट के तहत दोनों शहरों को फ्रांस की A.F.D., जर्मनी की kfw, यूरोपियन यूनियन और NIUA से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के लिए ऋण मिलेगा।
- इस ऋण की राशि से अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सफाई में काम आने वाले उपकरण की खरीद, कचरा ट्रांसफर स्टेशनों के निर्माण में करवाया जाएगा।
- दोनों शहरों को कचरे के बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 300 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा।
- इस प्रोजेक्ट में 80% राशि राज्य और केन्द्र सरकार वहन करेगी, जबकि 20% राशि स्थानीय निकाय के द्वारा वहन की जाएगी।

सिटीज 2.0 (CITIIS 2.0) योजना

- पूरा नाम: City Investments to Innovate, Integrate and Sustain 2.0
- केन्द्र सरकार ने वर्ष 2023 में इस कार्यक्रम की घोषणा की थी।
- यह स्मार्ट सिटीज मिशन का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु-उन्मुख सुधार कार्यों को बढ़ावा देना है।
- CITIIS में निम्नलिखित 4 घटकों को शामिल किया गया है:
 - सतत गतिशीलता
 - सार्वजनिक खुले स्थान
 - शहरी ई-गवर्नेंस और ICT
 - कम आय वाली बस्तियों के लिए सामाजिक और संगठनात्मक नवाचार।
- यह कार्यक्रम चार साल की अवधि यानी 2023 से 2027 के लिए है।
- इसमें देश की 100 स्मार्ट सिटीज आवेदन कर सकती थी जिसमें से 84 शहरों ने आवेदन किया था।
- इनमें से केंद्र सरकार 18 स्मार्ट सिटी का चयन किया है।

मा (MAA) वाउचर योजना

- इसका पूरा नाम **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) - वाउचर योजना** है।
- यह राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजना है।
- इसे राज्य सरकार द्वारा **बारां, भरतपुर एवं फलौदी में पायलट प्रोजेक्ट** के रूप में शुरू किया गया था।
- यह योजना अप्रैल से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी।
- इसके तहत राजस्थान में गर्भवती महिलाएं अब प्राइवेट सेंटर्स में भी निःशुल्क सोनोग्राफी करा सकेंगी।
- इससे शिशु मृत्यु दर में भी कमी लाई जा सकेगी।
- इसमें गर्भवती महिलाओं को क्यू-आर कोड आधारित ई- वाउचर मिलेगा। इस वाउचर को देकर किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी कराई जा सकेगी।
- इससे राज्य में 3 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल सकेगा।
- राजस्थान में जिन सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर दूसरी या तीसरी तिमाही में कम से कम एक जांच निःशुल्क करवाई जा सकेगी।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदला गया

- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर **मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना** कर दिया गया है।
- इससे संबंधित नियमों में भी परिवर्तन किया गया है।
- इस योजना में बिजली व कृषि कार्य में दुर्घटना को भी शामिल किया है।
- इस योजना के तहत बीमा कवर **10 लाख रुपये (पूर्ववर्ती)** रखा गया है।
- प्राकृतिक घटना व ऑपरेशन से संबंधित मामलों, युद्ध, हत्या, आत्महत्या, शराब पीने व प्रसव के दौरान मौत के मामलों में इस योजना के तहत लाभ नहीं मिल सकेगा।
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना व राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल परिवारों के साथ ही पांचों विद्युत कंपनियों के विद्युतकर्मियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022 को शुरू की गई थी।

'नमो ड्रोन दीदी' योजना

- राजस्थान में 11 मार्च, 2024 को कोटा जिले से 'नमो ड्रोन दीदी' योजना की शुरुआत की गई।
- यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है।
- इसका उद्देश्य महिला सशक्तीकरण, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है।
- इस योजना के तहत महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन दिए जायेंगे तथा प्रशिक्षित भी किया जाएगा।
- इस योजना के तहत हाड़ौती की 104 महिलाओं को ड्रोन सौंपे गए।
- इस योजना के तहत राजस्थान को 5 जोन में बाँटकर 5 कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है।
- इनमें इफको, चम्बल फर्टिलाइजर, NFCL शामिल है।
- यह ड्रोन फसलों की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव व बीज बुवाई में सहायक होंगे।

नमो ड्रोन दीदी योजना

- यह योजना 30 नवंबर 2023 को शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत देश में स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं में से 15,000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ही दिया जाएगा।
- इसके तहत चयनित महिला को 15 दिनों तक ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राजस्थान पंचायती राज विभाग में कार्यों का विभाजन

- राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान के अनुच्छेद 166 के तहत 16 मार्च, 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सलाह पर पंचायती राज विभाग का कार्यभार अलग-अलग मंत्रियों में आवंटित किया।
- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य की सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे तथा राज्यपाल मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
- पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ महिला एवं बाल विकास विभाग- दीया कुमारी
- पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ - कृषि विभाग - किरोड़ीलाल मीणा
- पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग- गजेन्द्र सिंह खींवरसर
- पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ शिक्षा विभाग - मदन दिलावर
- पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ सामाजिक न्याय विभाग - अविनाश गहलोत
- **नोट:** राजस्थान में 5 विभाग (कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, महिला बाल, सामाजिक न्याय) पंचायती राज के अधीन रहते थे।
- वर्तमान पंचायती राज विभाग के कार्यबोझ को ध्यान में रखकर राज्यपाल ने मूल विभागों के कार्यों की देखरेख का जिम्मा संबंधित मंत्रियों के अधीन कर दिया है।

राज ऋषि गोकुल ग्राम परियोजना कार्यक्रम

- इसका आयोजन 05 मार्च 2024 को कृषि अनुसंधान केन्द्र दुर्गापुरा (जयपुर) में किया गया।
- इसके तहत कृषि के नवाचारों हेतु एक कृषक दल को ब्रह्मकुमारी में राजऋषि गोकुल ग्राम (माउण्ट आबू) भेजा जायेगा, और वहाँ पर यौगिक खेती के संदर्भ में सीखेंगे।

- यह कृषि विभाग और ब्रह्मकुमारी का संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।
- यौगिक खेती में प्राकृतिक खेती के सभी नियमों का पालन किया जाता है और कम लागत में अधिक व शुद्ध पैदावार होती है।

माउंट आबू: भारत का पहला एग्रो ईको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर

- राजस्थान के माउंट आबू (सिरोही) में देश का पहला एग्रो ईको टूरिज्म व इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनेगा।
- इस हेतु माउंट आबू में सनसेट प्वाइंट के पास 12 बीघा जमीन 10 करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया है।
- इसमें विदेशी प्रजातियों के कट फ्लावर पर रिसर्च होगा।
- माउंट आबू का मौसम फूलों की प्रजातियों के अनुकूल है। ऐसे में ओरकिड, ट्यूलिप, रजनी गंधा समेत अन्य विदेशी प्रजातियाँ इस क्षेत्र में विकसित की जा सकेंगी।

जाहोता गाँव (जयपुर ग्रामीण)

- राजस्थान की पहली ओ.डी.एफ. प्लस पंचायत है और यहां पर 101 कृषकों के खेतों में 25,000 व्यवसायिक पेड़ लगाये गये हैं।
- भारत सरकार द्वारा इस गाँव को अटल भू-जल योजना के तहत मॉडल गाँव के रूप में चुना गया है।

'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज' जयपुर में स्थापित होगा

- बच्चों में होने वाले दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए राजस्थान के जयपुर (जेके लोन अस्पताल में) में "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज" स्थापित किया जाएगा।
- इस हेतु एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

पीएम श्री योजना के द्वितीय चरण में राजस्थान के 237 विद्यालयों का चयन

- पीएम श्री विद्यालय योजना के द्वितीय चरण में 7 मार्च 2024 को राजस्थान के 237 पीएम श्री विद्यालयों का चयन किया गया है।
- **नोट:** केन्द्र प्रवर्तित पीएमश्री विद्यालय योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन किया गया था।

- इस योजना में अब तक राजस्थान के कुल 639 विद्यालयों का चयन किया जा चुका है।
- इस योजना के द्वितीय चरण में नागौर, पाली और अलवर से सर्वाधिक 12-12 विद्यालयों का चयन किया गया है जबकि सवाईमाधोपुर और जैसलमेर से न्यूनतम 3-3 विद्यालयों का चयन किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण समान व समावेशी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित कर विद्यालयों का सम्पूर्ण रूपान्तरण करना है।

School at Home (24X7 शैक्षणिक हेल्पलाइन) लॉन्च

- विशेष योग्यजन निदेशालय के अधीन विशेष विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए यह हेल्पलाइन 13 मार्च 2024 को लॉन्च की गई।
- यह हेल्पलाइन 'हैल्पिंग हैण्ड इण्डिया' NGO की सहायता से शुरू की गई है।
- इस NGO द्वारा विशेष योग्यजन बच्चों को नियमित निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
- 'स्कूल एट होम' कार्यक्रम एक समावेशी शैक्षिक पहल है, जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इन्टरनेट और बिना स्मार्ट फोन के पहुँचाता है।
- यह कक्षा-1 से 12 वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के साथ सह-पाठ्यक्रम शैक्षिक कार्यक्रमों और ऑनलाइन कक्षाओं के साथ उपलब्ध है।
- यह शिक्षा घर पर 24x7 उपलब्ध है।
- इसमें देश भर के दिव्यांगजन/गरीब छात्रों से आसानी से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा भी शामिल है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार की घोषणाएँ

- राजस्थान सरकार ने महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2024 को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 100 करोड़ रु. के ऋण वितरण समेत महिलाओं हेतु कई पहल शुरू की गई।
- इसमें राजीविका के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का प्रावधान किया गया है।
- महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण राशि के बैंक वितरण किया गया।
- महिला निधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई।
- फलौदी, भिवाड़ी एवं आमेर में वन स्टॉप सेन्टर का लोकार्पण किया गया।
- प्रधानमंत्री मातृ वन्दन योजना की लाभार्थियों को सहायता राशि के बैंक वितरित किए गए।

- महिला सुरक्षा के लिए डायल 112 तथा 1090 सेवा के तहत नए वाहन उपलब्ध कराए गए।
- राज्य सरकार ने महिला दिवस से एक दिन पहले पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण का कोटा 30% बढ़ाकर 33% कर दिया है।

मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि में वृद्धि को मंजूरी

- राजस्थान सरकार द्वारा 9 मार्च 2024 को 'मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना' के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई।
- इसके तहत दी जाने वाली राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य समाज में लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना के तहत पहली व दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने पर यह राशि दी जाएगी।

आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% की वृद्धि को मंजूरी

- यह मानदेय वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ।
- जिसमें आशा सहयोगिनियों को 4,098 के स्थान पर 4,508 रुपए की राशि दी जाएगी।

आशा सहयोगिनी

- आशा (ASHA) सहयोगिनी का पूरा नाम Accredited Social Health Activist (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) है।
- यह स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करने वाली कार्यकर्ता है।
- यह आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व स्कूली शिक्षा और सेवाओं की योजना संबंधी कार्य करती है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की राज्य शाखा जयपुर में स्थापित होगी

- इस संदर्भ में भारत सरकार और राजस्थान के चिकित्सा विभाग के बीच 6 मार्च 2024 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
- इससे राजस्थान में रोग निदान के लिए राष्ट्रीय स्तर की जाँच सुविधा उपलब्ध होगी।
- इस एमओयू के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनीपार्क (जयपुर) में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की राज्य शाखा का निर्माण होगा।
- नोट: संक्रामक रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
- यह केन्द्र सर्विलेंस, जाँच, डेटा एनालिसिस, फीडबैक, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, प्रशिक्षण आदि

के माध्यम से संक्रामक रोग से बचाव व नियंत्रण करता है।

- इसकी पहले से 8 शाखाएँ अलवर (राजस्थान), बेंगलुरु (कर्नाटक), कोजीकोड (केरल), कुन्नूर (तमिलनाडु), जगदलपुर (छत्तीसगढ़), पटना (बिहार), राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।
- नोट: सभी राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 'राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की 30 शाखाओं (8 मौजूदा शाखाओं सहित) की स्थापना' प्रस्तावित है।

राजस्थान में 365 आदर्श आंगनबाड़ी बनाने को मंजूरी

- राजस्थान के समेकित बाल विकास विभाग द्वारा राज्य के 365 सामान्य आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाने की स्वीकृति दी गई है।
- राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक परियोजना/ब्लॉक में से एक आंगनबाड़ी को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इसके लिए एक आंगनबाड़ी केंद्र को आदर्श केंद्र बनाने पर लगभग 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।
- इसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण एवं बच्चों के स्वस्थ व शिक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना है।
- इसके तहत आंगनबाड़ियों के बच्चों को प्ले स्कूल जैसा माहौल उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके लिए सामान्य मरम्मत एवं सुदृढीकरण, वॉल पेंटिंग, सौर ऊर्जा, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, बच्चों के लिए खिलौने, खेलकूद के सामान, रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, शौचालय में आधुनिक सुविधा, आरओ, एलईडी, सीसीटीवी, वाईफाई, पेनड्राइव, पोषाहार कंटेनर, लाइब्रेरी कॉर्नर इत्यादि सभी प्रकार के कार्य सम्पादित कराए जाएंगे। साथ ही न्यूट्री गार्डन (पोषण वाटिका) को भी विकसित किया जाएगा।
- नोट: वर्ष 2024- 25 के राज्य के लेखानुदान बजट में इसकी घोषणा की गई थी।

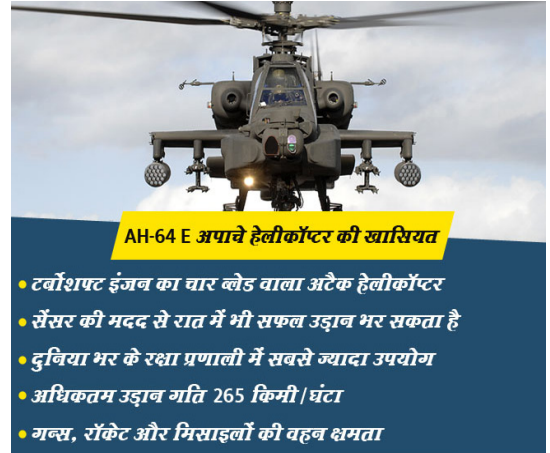
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2024 को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से देशभर की 58 विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
- इसमें स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत राजस्थान के 3 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के विकास कार्य भी शामिल है, जो कि-
 1. सांवलिया सेठ मंदिर, मंडफिया (चित्तौड़गढ़)
 2. करणी माता मंदिर, देशनोक (बीकानेर)
 3. केशोरायपाटन (बूंदी) हैं।

- केंद्र सरकार ने देश में 40 से अधिक ऐसे स्थानों की पहचान की है जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने देखो अपना देश पीपुल्स च्वाइस अभियान का 7 मार्च 2024 को शुभारंभ किया।
- इस अभियान का उद्देश्य विदेश में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित करना है।

जोधपुर में अपाचे हेलिकॉप्टर की पहली स्ववाड़न बनेगी

- हेलिकॉप्टर AH-64 E अपाचे की स्ववाड़न जोधपुर मिलट्री स्टेशन पर तैनाती होगी।
- इस स्ववाड़न में 6 हेलिकॉप्टर मिलेंगे, इनमें से 2 हेलिकॉप्टर की तैनाती मई में होगी।
- इसमें अपाचे के साथ जमीनी लड़ाई का सबसे घातक माने जाने वाला स्वदेशी रूद्र अटैक हेलिकॉप्टर भी होगा।
- ये दोनों एयर कैवलरी यानी टैंक व तोप के साथ जमीनी अटैक में पाकिस्तान से सटे वेस्टर्न फ्रंट को मजबूती प्रदान करेंगे।
- वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर हैं, जो पाकिस्तान और चीन के मोर्चे पर तैनात हैं।



AH-64 E अपाचे

- अपाचे हेलिकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है।
- अपाचे हेलिकॉप्टर्स द्वारा अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हिंदुकुश पहाड़ियों में छिपे तालिबान और अलकायदा के आतंकियों के विरुद्ध सफल अभियान चलाया गया था।
- इन हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना की मांग के अनुरूप बनाया गया है।
- इनमें हवा से जमीन पर मार करने वाले हेलफायर मिसाइल (Hellfire Missiles), 17 मिमी. हाइड्रा रॉकेट (Hydra Rockets) और हवा-से-हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल (Stinger Missiles) शामिल है।

भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर तेजस की पहली स्क्वाड्रन

- राजस्थान से सटे पश्चिमी बॉर्डर पर HAL (Hindustan Aeronautics Limited) द्वारा निर्मित तेजस मार्क 1A की पहली स्क्वाड्रन बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात की गई है।
- यह स्क्वाड्रन वायुसेना से रिटायर हो चुके मिग 21 और मिग 27 की जगह लेगी।
- अगले 5 वर्षों में पश्चिमी फ्रंट पर तेजस की दो और स्क्वाड्रन की तैनाती होगी।
- दूसरी स्क्वाड्रन कच्छ के नलिया एयरबेस पर और तीसरी स्क्वाड्रन वेस्टर्न फ्रंट पर ही कश्मीर के फॉरवर्ड बेस पर तैनात होगी।

राजस्थान में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में पहली बार बया पक्षी की गणना हुई

- वन्यजीव विभाग ने अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क (कोटा) में बया पक्षी की गणना की है।
- इस पार्क में बया के 40 से अधिक घोंसले हैं।
- राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार इस पक्षी की आधिकारिक गणना की गई है।
- अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में इनके लिए हेबीटाट विकसित हो गया है तथा ग्रासलैंड और इको सिस्टम भी अनुकूल है।


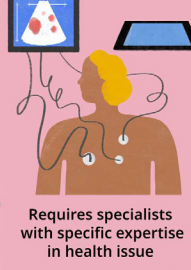
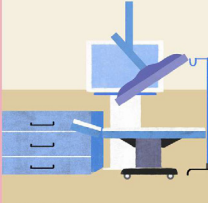
राजस्थान का पहला टर्सरी कैंसर केयर सेंटर (TCCC)

- इसका नाम आचार्य तुलसी टर्सरी कैंसर केयर सेंटर है तथा यह बीकानेर जिले में शुरू किया जाएगा।
- इसके लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण का अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है।
- आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर को 2015 में अपग्रेड करते हुए यहां प्रदेश का पहला टर्सरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने के लिए 45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे।
- आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर को 'सेंटर फॉर एक्सिलेंस' बनाने की भी घोषणा की गई है।

टर्सरी केयर सेंटर

- यदि कोई रोगी अस्पताल में भर्ती हैं और उसे उच्च स्तर की विशेष देखभाल की आवश्यकता है, तो उसे टर्सरी केयर सेंटर हेतु रेफर कर सकता है।
- टर्सरी केयर सेंटर विशिष्ट, जटिल स्वास्थ्य स्थितियों के इलाज के लक्ष्य के साथ अत्यधिक विशिष्ट उपकरण और विशेषज्ञता से संबंधित है।
- इसमें डायलिसिस, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट (CABG), या जलने का उपचार संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं।

Differences Between Primary, Secondary, and Tertiary Care

Primary	Secondary	Tertiary
For illness, injury, acute medical problems, and referrals	Requires specialists with specific expertise in health issue	Requires highly specialized equipment and expertise
		

दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड टनल

- यह रेवाड़ी - दादरी सेक्शन पर स्थित है।
- इसे डबल स्टेक कंटेनर गुड्स ट्रेन के लिए स्थापित किया गया है।
- यह वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है।
- वर्तमान में रेलवे का ईस्टर्न कॉरिडोर का 100% और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का 95% कार्य पूरा हो चुका है।
- फ्रेट कॉरिडोर के पूरी तरह शुरू होने के बाद रेलवे की करीब 75% गुड्स ट्रेन (मालगाड़ी) इस पर शिफ्ट हो जाएंगी।
- DFC में ट्रेनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार ई-कॉमर्स कंपनियों और रेलवे के बीच समझौता हुआ है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC)

- यह उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीक युक्त एक रेल मार्ग होता है। इसे विशेष रूप से माल एवं वस्तुओं के परिवहन हेतु बनाया जाता है।
- इसमें बेहतर बुनियादी ढाँचे और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेशन होता है।
- केंद्र सरकार द्वारा दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं -
 - ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)
 - वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)

ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)

- यह पंजाब के साहनेवाल (लुधियाना) से पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक है।
- इसके रूट में कोयला खदानें, थर्मल पावर प्लांट और औद्योगिक शहर मौजूद हैं।
- इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं।
- यह विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है।

वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)

- यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल (महाराष्ट्र) से दादरी (उत्तर प्रदेश) तक है।
- यह देश के प्रमुख बंदरगाहों से होकर गुजरता है।
- इसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है।
- इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- यह जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा वित्तपोषित है।
- **नोट:** ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आपस में जोड़ने के लिये दादरी और खुर्जा के बीच एक खंड बनाया जा रहा है।

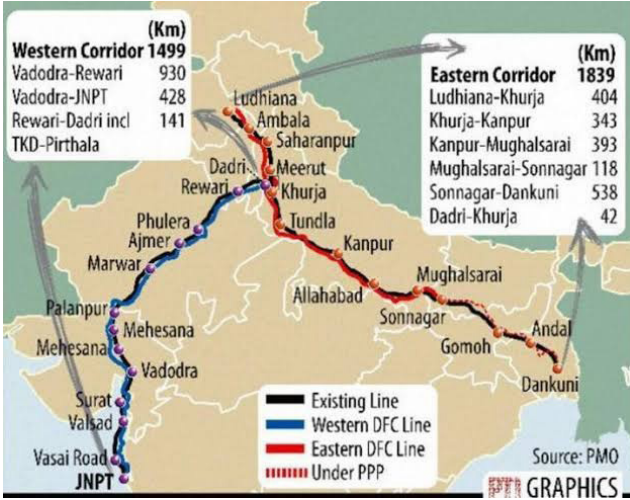
- इन वार्डों में 10 फाउलर बैड होंगे। इनमें 5 महिला एवं 5 बैड पुरुषों के लिए आरक्षित किए हैं।
- बैड के पास नर्सिंग अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में वृद्धजन तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बुला सकें।

एशिया की पहली बैक्टीरिया फ्री लॉन्डी

- जयपुर एसएमएस अस्पताल में एशिया की पहली ऐसी लॉन्डी शुरू की गई है, जिसमें बेडशीट-यूनिफॉर्म बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे।
- इसमें कपड़े डालने पर धुलने के साथ ही प्रेस होकर निकलेंगे।
- इससे मरीजों की बेडशीट से लेकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म पूरी तरह बैक्टीरिया रहित होगी और व्यवस्थित रूप से मिलेगी।
- इससे काम जल्दी और सुव्यवस्थित होने के साथ ही संक्रमण रहित कपड़े मरीजों, स्टाफ को मिलेंगे।

राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग

- राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग दौसा-गंगापुरसिटी रेलवे लाइन पर बनाई गई है।
- यह डीडवाना के पास स्थित है। इस सुरंग (2.3 किलोमीटर) रेल सुरंग का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- यह पहली रेल सुरंग है, जिसमें जर्मन तकनीक से गिट्टी रहित ट्रैक बनाया गया है।
- इस सुरंग की ऊंचाई 6.15 मीटर तथा सुरंग की चौड़ाई 5.20 मीटर है।



देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड

- यह किशनगढ़ के 535 बीघा क्षेत्र में विकसित हो रहा है।
- इसमें 2,000 फैक्ट्रियों की निकलने वाली मार्बल स्लरी से भरने में इसे 20 साल लगेंगे।
- इस यार्ड में फिल्मों की शूटिंग व प्री-वेडिंग शूट होते हैं।
- देश में अभी दूसरा बड़ा डंपिंग यार्ड 506 बीघा क्षेत्र में महाराष्ट्र के देवनगर में है।

प्रदेश की रेल सुरंगें

- **देबारी:** चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच 750 मीटर लंबी।
- **कामली घाट:** मावली-मारवाड़ मीटर गेज लाइन पर 500 मीटर लंबी।
- **कामली घाट:** मावली-मारवाड़ मीटर गेज पर 300 मीटर लंबी।
- **नोट:** देश की सबसे लंबी 11 किमी रेल सुरंग जम्मू-कश्मीर के पीर पंजाल में।

जिला अस्पतालों में जिरिएट्रिक वार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य

- राजस्थान हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इन्हें 'रामाश्रय' के नाम से जाना जाएगा।
- इस जिरिएट्रिक वार्ड से वृद्धजनों की सेवा-सुश्रुषा एवं उपचार और बेहतर हो सकेगा।
- राजस्थान के 49 जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा प्रारम्भ कर दी है।

कानून की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय

- केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में पहली बार एल.एल.बी. का कोर्स शुरू किया जाएगा।
- इस विश्वविद्यालय में प्राचीन ऋषियों के हिन्दू विधि के मूल ग्रंथों, धर्मशास्त्र और नए कानूनों का अध्ययन कराने के लिए एल.एल.बी की पढ़ाई होगी।

- इस विश्वविद्यालय में भारतीय पुरातन विधि और नए कानूनों का मिश्रण होगा।
- नए सत्र 2024- 25 से इसमें 60 सीटों पर टेस्ट के द्वारा प्रवेश मिलेगा।
- धर्मशास्त्र में याज्ञवल्क्य, नारद और मनुस्मृति, कौटिल्य अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाएगा।
- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में भी इस तरह का डिग्री कोर्स संचालित करना प्रस्तावित है। देश में यह नवाचार पहली बार जयपुर में किया जा रहा है।

राजस्थान में तेंदुओं की संख्या

- 'भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट' 29 फरवरी, 2024 को जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018-2022 के बीच 476 से बढ़कर 721 हो गई है।
- इस रिपोर्ट में राजस्थान के चार टाइगर रिजर्व मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, रणथम्भौर और सरिस्का को शामिल किया गया है।
- सरिस्का और रणथम्भौर टाइगर रिजर्व लेपर्ड की सर्वाधिक संख्या के संदर्भ में देश में टॉप-15 में शामिल हैं।
- देश में लेपर्ड की सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व की श्रेणी में सरिस्का तीसरे स्थान पर है।
- सरिस्का में 269 तेंदुए हैं। वर्ष 2018-2022 के मध्य यहाँ 102 तेंदुए बढ़े हैं।
- सरिस्का के हर 100 वर्ग किमी में 21.43 तेंदुए हैं (देश के कैमरा-ट्रैप साइटों में सर्वाधिक घनत्व)

राजस्थान में नए पेनोरमा की घोषणा

- राजस्थान की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से नए पेनोरमा, स्मारक, संग्रहालय निर्माण एवं विकास कार्यों की घोषणा की गई है।
- ये निम्नलिखित हैं-
 - » महावीर जी पेनोरमा-करौली जिले के महावीर जी में
 - » जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज पेनोरमा - अजमेर में
 - » भक्त शिरोमणि करमा बाई पेनोरमा - डीडवाना - कुचामन के कालवा में
 - » श्री जसनाथ जी पेनोरमा- बीकानेर के कतरियासर में
 - » श्री खेमा बाबा पेनोरमा - बालोतरा के बायतू में
 - » श्री भामाशाह पेनोरमा - चित्तौड़गढ़ में

- » राव चन्द्रसेन पेनोरमा - जोधपुर में
- » गोकुला जाट पेनोरमा - भरतपुर में
- » जैसलमेर पेनोरमा - जैसलमेर में
- इन पेनोरमा का निर्माण राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा।
- इसके अलावा श्रीबृज चौरासी कोस परिक्रमा मार्ग (कामां, डीग), जयपुर जिले में **स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय** और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में **'स्वातंत्र्य गांव'** स्मारक का निर्माण कराया जाएगा।

मेट्रो फेज 1D का शिलान्यास

- जयपुर में 15 मार्च 2024 को मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड चौराहा को मेट्रो से जोड़ने के लिए मेट्रो फेज 1D का शिलान्यास किया गया।
- जयपुर मेट्रो के द्वितीय चरण की डीपीआर तैयार कराने के लिए दिल्ली मेट्रो को कंसल्टेंसी नियुक्त किया है।
- मेट्रो का फेज-1D 204 करोड़ की लागत से बनेगा तथा इसका काम मार्च 2026 तक पूरा होगा।
- जयपुर में मेट्रो के फेज-1C और 1D पूरा होने के बाद मेट्रो का विस्तार 16 किमी का हो जाएगा।
- इसके साथ ही जयपुर मेट्रो में 16 मेट्रो स्टेशन हो जाएंगे।

सभी संभागों में MSME सुविधा व विकास केंद्र

- राजस्थान में उद्यमियों की सहायता के लिए **सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग** द्वारा सभी संभाग मुख्यालयों पर MSME सुविधा एवं विकास केंद्र शुरू किए गए हैं।
- इन केंद्रों का उद्देश्य एकल संपर्क बिंदु के रूप में वैधानिक अनुपालन और विभिन्न योजनाओं में मार्गदर्शन करना है।
- इसके तहत राज्य में आर्थिक विकास व रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

III जोधपुर ने समुद्र में तेल रिसाव का पता लगाने हेतु हाइब्रिड ड्रोन बनाया

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने जमीन, हवा और पानी में कार्य करने वाला हाइब्रिड ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाया है।
- यह हाइब्रिड ड्रोन जमीन और पानी दोनों पर चल सकता है।
- यह मुख्य रूप से समुद्र, नदियों में तेल रिसाव होने पर उसे रोकने में सहायक होगा।
- यह पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण फैलाव को रोकने में भी कारगर साबित हो सकता है।

- यह प्रणाली अहिंसा प्रजाति के पक्षी से प्रेरणा लेकर विकसित की गई है।
- यह पक्षी जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम होता है।
- यह प्रोटोटाइप एक जहाज की तरह चल सकता है व हवा में उड़ सकता है और पानी में डूबे होने पर भी नेविगेट कर सकता है।
- यह 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है और इसकी उड़ान का समय 15 मिनट है।

आरसीडीएफ ने ऊँटनी का दूध लॉन्च किया

- राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सरस ब्रांड का ऊँटनी का दूध लॉन्च किया है।
- यह शुरुआत में बीकानेर में सरस डेयरी बूथों पर उपलब्ध होगा।
- इसे बाद में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
- उपभोक्ताओं को 200 ग्राम दूध 20 रुपए में मिलेगा।

राजस्थान के 65,000 स्कूलों की GIS मैपिंग होगी

- राजस्थान के 65 हजार सरकारी स्कूलों की जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) की मैपिंग होगी।
- इसके तहत स्कूलों के अक्षांश और देशांतर बिंदु को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा।
- इससे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लाभ मिलेगा।

अजमेर-दिल्ली कैंट वन्दे भारत ट्रेन अब चंडीगढ़ तक जाएगी

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को रेलवे की लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास - लोकार्पण किया।

राजस्थान को सौगातें

- अजमेर-दिल्ली-कैंट वन्दे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का चण्डीगढ़ तक विस्तार किया गया।
- कुचामन सिटी-नावां सिटी व फुलेरा गोविंदी मारवाड़ रेल खण्डों का दोहरीकरण का लोकार्पण हुआ।
- जोधपुर कारखाने के आधुनिकीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया।
- जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण डिपो निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया।

राष्ट्रीय 'संजीवनी' कला महोत्सव

- यह ओरियन ग्रीन्स संस्था द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पर्यावरण आधारित कला महोत्सव है।

- इसका आयोजन 10 मार्च, 13 मार्च और 20 मार्च को क्रमशः अजमेर, जयपुर व औरंगाबाद में किया गया।
- इसमें पर्यावरण विषय पर कथक नृत्य, ध्रुवपद गायन, सितार वादन और नाटकों का मंचन देश के विख्यात कलाकारों की ओर से किया गया।
- यह एक पर्यावरण आधारित महोत्सव था जिसे इस बार ध्रुवपद मार्तंड स्व. पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग को समर्पित किया गया।

'धर्मा गार्डियन' अभ्यास

- यह भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित होने वाला युद्धाभ्यास है।
- इसका आयोजन बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया।

फुल ब्राइट शिक्षण उत्कृष्टता और उपलब्धता कार्यक्रम

- इसके तहत राजस्थान के सरकारी शिक्षक अब संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की कला सीखेंगे।
- इसे यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन (USIEF) द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत जो भी शिक्षक अमरीकी प्रशिक्षण लेगा, उसे फ़ैलोशिप भी दी जाएगी।
- भारत-अमेरिका के बीच हुए सांस्कृतिक एग्रीमेंट के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन फुल ब्राइट फ़ैलोशिप संचालित करता है और यह फाउंडेशन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर इनोवेशन का काम करता है।

देवास परियोजना: तृतीय व चतुर्थ बांध एवं टनल निर्माण कार्य का शिलान्यास

- मुख्यमंत्री द्वारा 01 मार्च 2024 को उदयपुर के गोगुंदा में देवास परियोजना: तृतीय व चतुर्थ बांध एवं टनल निर्माण कार्य के शिलान्यास किया गया।
- इस परियोजना की लागत 1,690 करोड़ की है।
- यह परियोजना उदयपुर में वर्ष पर्यन्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है।

आकाशीय बिजली से प्रभावितों को आर्थिक सहायता

- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 01 मार्च 2024 को राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें 4 लाख रुपये की सहायता आपदा

प्रबंधन एवं राहत विभाग की ओर से तथा 1 लाख रुपये की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा प्रदान की जाएगी।

53वाँ राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस

- राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन 04 मार्च 2024 को जयपुर में किया गया।
- इस वर्ष की थीम-‘E.S.G. (Environmental, Social and Governance) उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दें’ है।
- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का मुख्य उद्देश्य उद्योगों, कार्यस्थलों और समुदायों सहित सभी क्षेत्रों में सुरक्षित प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना है।

सतत विकास लक्ष्यों हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन

- यह सम्मेलन 4 एवं 5 मार्च को राजस्थान इंटरनेशनल सेन्टर, जयपुर में आयोजित किया गया।
- यह राजस्थान सरकार तथा यूएनडीपी और यूएन की साझेदारी में नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

- इस सम्मेलन का उद्देश्य SDG स्थानीयकरण पर जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर SDG को संस्थागत बनाना, अनुभवों का आदान-प्रदान करना, वित्त परिदृश्य का पता लगाना और प्रगति में तेजी लाना है।
- यह सम्मेलन देश भर से एसडीजी पर सीख और अच्छी प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच के रूप कार्य करता है।
- इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने UNDP SDG नॉलेज हब पोर्टल, राज्य सरकार द्वारा तैयार SDG-2 डेशबोर्ड तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण डेशबोर्ड का लोकार्पण किया।

रूडसिको अमृत 2.0 मिशन के तहत राजस्थान में जल आपूर्ति कार्यों हेतु कार्यकारी एजेंसी नियुक्त

- राजस्थान के स्वायत्त शासन विभाग की एजेंसी रूडसिको को अमृत 2.0 मिशन के तहत 183 नगर पालिकाओं में जल आपूर्ति कार्यों के लिये कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- रूडसिको द्वारा नगर पालिकाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु मैसर्स वेपकोस को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है।

अमृत मिशन	जल जीवन मिशन
<ul style="list-style-type: none"> शुरुआत: 25 जून 2015 को। पूरा नाम: अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Mission) (AMRUT) मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय अमृत मिशन के तहत लगभग 500 शहरों को चुना गया था। चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल की निकासी, हरित स्थान और पार्क, और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर, 2021 को योजना के दूसरे चरण अमृत 2.0 का शुभारंभ किया। इसके तहत स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) के तहत कार्य करवाये जाएंगे। 	<ul style="list-style-type: none"> शुरुआत: अगस्त 2019 से। मंत्रालय: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उद्देश्य भारत में हर घर के लिये नल से जल की पहुँच सुनिश्चित करना है। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिये की गई है। जल जीवन मिशन जल के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है। मिशन में प्रमुख घटकों के रूप में सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है। इसके अलावा, हर घर नल से जल कार्यक्रम की घोषणा बजट 2019-20 में की गई। यह जल जीवन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

राजस्थान के 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी

- राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने को 5 मार्च 2024 को मंजूरी दी गई।

- लेखानुदान बजट 2024-25 घोषणा के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर शहरों में नगरीय बस सेवा के लिए इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इससे आमजन को प्रदूषणरहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलने से त्वरित एवं बेहतर परिवहन सुविधा का लाभ मिलेगा।
- इन बसों का संचालन एवं संधारण स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कंवर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के द्वारा किया जाएगा।
- इसके तहत जयपुर में 300, जोधपुर में 70, कोटा में 50, उदयपुर में 35, अजमेर में 30 तथा बीकानेर एवं भरतपुर में 15 ई-बसों का संचालन किया जाएगा।

गंगनहर में ऑटोमेशन एवं स्काडा की स्थापना को मंजूरी मिली

- गंगनहर प्रणाली में अत्याधुनिक ऑटोमेशन एवं स्काडा स्थापित किया जाएगा।
- इसके लिए 8 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा परियोजना (लागत: 695 करोड़ रुपये) स्वीकृत की गई है।
- इससे अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलेगा और प्रथम चरण में मुख्य नहर एवं चार वितरिकाओं के 1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा।
- इसका उद्देश्य गंगनहर प्रणाली में 1.09 लाख हेक्टेयर के लिए अत्याधुनिक स्काडा आधारित ऑटोमेशन को लागू करना है।
- इसके तहत गंगनहर प्रणाली की विभिन्न नहरों की सिंचाई क्षमता को 79% से बढ़ाकर 86.5% हो जाएगी।

स्काडा (SCADA) सिस्टम

- **पूरा नाम:** Supervisory Control And Data Acquisition.
- यह एक रिमोट कंट्रोल आधारित स्वचलित केंद्रीयकृत व्यवस्था है।
- इसका पूरा सिस्टम आनलाइन केंद्रीयकृत होता है। इससे जल आपूर्ति में फाल्ट के बारे में जानकारी मिलेगी।
- यह अलर्ट जारी करेगा तथा फाल्ट लोकेशन की सही स्थिति की जानकारी से समय की बचत वोल्टेज नियंत्रण होगा।
- इसके द्वारा सिस्टम ही से लाइन में आने वाली समस्याओं के बारे में अभियंताओं को ऑनलाइन दिशानिर्देश भी दिए जा सकेंगे।

बादशाह मेला

- यह प्रतिवर्ष ब्यावर में आयोजित किया जाता है।
- ब्यावर में धुलंडी के दूसरे दिन ऐतिहासिक बादशाह की सवारी निकली जाती है।
- यह मेला हिन्दू-मुस्लिम एकता के रूप में भाईचारे और सदभावना का संदेश देता है।
- यह मेला वर्ष 1851 से आयोजित किया जा रहा है।
- इस मेले में बादशाह की भूमिका अग्रवाल और बीरबल की भूमिका ब्राह्मण निभाता है।
- पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दिन टोडरमल ने जादुई करिश्मे से बादशाह अकबर को आखेट के वक्त जंगल में उपकरण व मुद्रा उपलब्ध कराए, जिससे खुश होकर बादशाह ने टोडरमल को तीन घंटे की बादशाहत प्रदान की थी।
- अकबर की इसी याद को ताजा रखने के लिए मुगलकाल से ब्यावर में होली के त्यौहार पर धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह मेला आयोजित हो रहा है।

राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला-2024

- यह 8-18 मार्च तक सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया।
- यह मेला सवाई माधोपुर प्रशासन, राजस्थान, ग्रामीण विकास विभाग के एक स्वायत्त निकाय - राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।
- इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह मेला परंपरा, कला, शिल्प और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करता है।
- यह सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उद्यमियों के रूप में स्थापित करने के अवसर भी प्रदान करता है।

रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण

- बूंदी में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 76.69 करोड़ रूपए की लागत से 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना (विस्तार चंबल भीलवाड़ा परियोजना) का लोकार्पण किया गया।

- इससे बूंदी और भीलवाड़ा में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
- इसके तहत 9,227 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। इस परियोजना से 97,000 से अधिक आबादी लाभान्वित होगी।

बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल

- यह पोर्टल जयपुर में लॉन्च किया गया।
- यह पोर्टल राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में बांधों और जलाशयों में जल स्तर की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा।
- यह राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में नहरों में उपलब्ध पानी की मात्रा की वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान करेगा।
- यह पोर्टल जल के कुशल प्रबंधन में मदद करेगा। इससे बाढ़ और सूखे की भविष्यवाणी करने में भी आसानी होगी।
- राजस्थान पहला राज्य था जिसने पानी की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक डोमेन तक लाने के लिए एक प्रणाली विकसित की।
- इस प्रणाली को जल संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत विकसित किया गया है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में संविधान पार्क का लोकार्पण

- राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने 11 मार्च 2024 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में निर्मित संविधान पार्क का वर्चुअली लोकार्पण किया।
- RTU, कोटा में 65 हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में संविधान पार्क निर्मित हुआ है।
- राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय में बनने वाला यह पहला संविधान पार्क है।
- इस पार्क में 75 फीट ऊँचा संविधान स्तंभ बनाया गया है।
- **नोट:** राज्यपाल के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाये जा रहे हैं।
- राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अलावा उदयपुर और बीकानेर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क स्थापित किए जा चुके हैं।

रोडवेज में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में 50% की छूट मिलेगी

- राजस्थान सरकार द्वार रोडवेज की साधारण एवं द्रुतगामी श्रेणी की बसों में 60 से 80 वर्ष के

वरिष्ठ नागरिकों को अब 50% प्रतिशत की छूट को मंजूरी दे दी गई है। (पहले यह 30% थी।)

पोस्टल बड्डी (Postal Buddy)

- यह राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया एप है।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा 21 मार्च, 2024 को इसे लॉन्च किया गया।
- इस एप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) श्रीगंगानगर द्वारा विकसित किया गया है।
- **नोट:** श्रीगंगानगर जिले के तात्कालीन जिला कलेक्टर अंशदीप के निर्देशन में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान 'इलेक्शन बड्डी' बनाया गया था।
- इसे चुनाव आयोग के 'राष्ट्रीय पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।

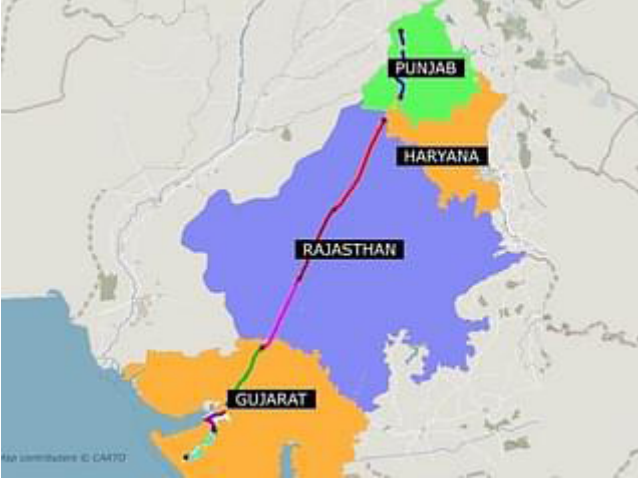
माइनिंग सेक्टर में राजस्थान का एक वर्ष में 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी का रिकॉर्ड

- राजस्थान ने 13 मार्च 2024 को 31 मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
- राजस्थान के माइंस एवं भूविज्ञान विभाग ने भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से मिनरल्स ब्लॉकों का सफल ऑक्शन किया है।
- राजस्थान में कुल 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हुई, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।
- इससे पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश में सर्वाधिक 29 ब्लॉकों की नीलामी हुई थी।

अमृतसर-जामनगर इकॉनॉमिक कॉरिडोर के 2 खण्डों का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को हरियाणा के गुरुग्राम में अमृतसर-जामनगर इकॉनॉमिक कॉरिडोर के दो खण्डों का उद्घाटन किया।
- इस परियोजना के लगभग 53 किलोमीटर लम्बाई के 1799 करोड़ की लागत के 2 पैकेज डबवाली (सिरसा)-पीलीबंगा (हनुमानगढ़) का उद्घाटन किया गया।
- अमृतसर-जामनगर इकॉनॉमिक कॉरिडोर के विकास से राजस्थान और विशेषकर सीमावर्ती जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर तथा जालौर जिलों की पंजाब और गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहरों एवं बंदरगाह से सीधी कनेक्टिविटी स्थापित होगी।

- इस कॉरिडोर के विकास से औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन एवं निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।



अमृतसर-जामनगर इकनोमिक कॉरिडोर

- अमृतसर जामनगर इकनोमिक कॉरिडोर 917 किलोमीटर लम्बा 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हैं जो लगभग 22,500 करोड़ की लागत से बनेगा।
- यह अमृतसर (पंजाब) को बंदरगाह शहर जामनगर (गुजरात) से जोड़ेगा।
- इसका लगभग 637 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर जिलों से होकर गुजर रहा है।
- राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली गाँव से जालौर जिले के खेतलावास गाँव तक विस्तृत है।
- इस परियोजना के 637 किलोमीटर के 23 पैकेज राजस्थान में हैं। जिनमें से 502 किलोमीटर लम्बाई के 18 पैकेज अभी तक राष्ट्र को समर्पित किये जा चुके हैं।

राजस्थान के विद्युत निगमों एवं केन्द्रीय उपक्रमों के मध्य एमओयू-पीपीए हुए

- इसके तहत राजस्थान में केन्द्रीय उपक्रम अगले 2-3 वर्षों में 1.60 लाख करोड़ लागत से 31,825 मेगावाट क्षमता के रिन्यूएबल व थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे और ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित किया जाएगा।
- इसके तहत 10 मार्च 2024 को राजस्थान के 3 विद्युत निगमों व 6 केन्द्रीय उपक्रमों के बीच 5 एमओयू व 1 पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) पर हस्ताक्षर हुए।

- इससे राजस्थान विद्युत उत्पादन में सरप्लस श्रेणी में आ सकेगा और राज्य की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होंगी।
- **नोट:** देश में पहली बार पोटाश खनन की शुरुआत राजस्थान से की गई है।
- पोटाश खनन हेतु राज्य के हनुमानगढ़ और बीकानेर स्थित दो खान ब्लॉक्स को नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
- ये नई परियोजनाएं संयुक्त उद्यम के जरिए विकसित की जाएगी।

MoUs और PPA का विस्तृत विवरण निम्नलिखित एमओयू एवं पीपीए के तहत संयुक्त उपक्रम विकसित किए जाएंगे-

- छबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम (RVUN) तथा NTPC के मध्य समझौता।
- 25,000 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए RVUN एवं NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बीच एमओयू।
- 1600 मेगावाट कोयला आधारित एवं 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए RVUN एवं कोल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौता।
- 125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित परियोजनाएं एवं 1000 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने के लिए RVUN तथा NLC इंडिया लिमिटेड के मध्य एमओयू।
- राजस्थान में बिजली प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए RVPN एवं पावर ग्रिड के मध्य समझौता।
- 600 मेगावाट सौर बिजली राज्य की वितरण कम्पनियों को देने के लिए RUVITL (Rajasthan Urja Vikas and IT Services Limited) एवं SJVN (Satluj Jal Vidyut Nigam) के मध्य पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA)।
- राजस्थान के विभिन्न विभागों, उपक्रमों, संस्थाओं तथा योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग राजस्थान सरकार तथा REC लिमिटेड के बीच एमओयू।

कोटा एयरपोर्ट के एमओयू के ड्राफ्ट को राज्य सरकार की मंजूरी

- कोटा के शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा।
- कोटा में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए पावरग्रिड और यूआईटी के बीच हाइड्रेशन लाइनों की शिफ्टिंग को लेकर एमओयू हुआ था।
- एयरपोर्ट को लेकर कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी (KDA), राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच प्रस्तावित एमओयू का ड्राफ्ट राज्य सरकार ने मंजूर कर दिया है।

नेशनल सिक्वोरिटी मॉड्यूल प्रशिक्षण

- यह भारत राजस्व सेवा (IRS) के 77वें बैच का प्रशिक्षण है।
- इसका आयोजन 4-6 मार्च 2024 को केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI) जयपुर में आयोजित किया गया।
- इसमें केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान (CDTI) और IIT, जोधपुर के मध्य 06 मार्च 2024 प्रौद्योगिकी मिशन पर एमओयू हुआ।
- इस एमओयू से पुलिस को साइबर चुनौतियों को हल करने में मदद मिलेगी।
- इसके तहत दोनों संस्थाओं के मध्य टैक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, शोध, परामर्श एवं शैक्षणिक योग्यताओं के आदान-प्रदान के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्वोरिटी, वैश्विक प्रौद्योगिकी सूचना तंत्र इत्यादि के बारे में जानकारियों का आदान-प्रदान किया जायेगा।

उच्च शिक्षा विभाग और क्रिस्प के बीच एमओयू

- राजस्थान में 4 मार्च 2024 को उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग और सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीस (क्रिस्प) के बीच एक समझौता पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर हुए।
- इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वस्तरीय कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है।
- इस एमओयू में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, उद्योगों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय रोजगारोन्मुखी कौशल शिक्षा को जोड़ा गया है।
- इस एमओयू के जरिये टूरिज्म, बैंकिंग एंड फाइनेंस, हेल्थकेयर एंड हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लाइफ साइंस, लोजिस्टिक्स आदि क्षेत्रों के कोर्स और प्रशिक्षण को राज्य के महाविद्यालयों में डिग्री पाठ्यक्रमों के साथ समेकित किया जायेगा।

- सभी पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चिन्हित विभिन्न महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीस (क्रिस्प)

- यह एक गैर-सरकारी संस्था है जो भारत सरकार में सचिव पद पर रहें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई है।
- यह संस्था राज्य सरकारों के साथ कौशल विकास क्षेत्र में मिलकर कार्य करती है।

नेशनल पैरा पावरलिफ्टिंग चैम्पियनशिप-2024 में सुनीता ने जीता रजत पदक

- यह नई दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में आयोजित की गई।
- इसमें सुनीता धोबी ने 79kg. वेट कैटेगरी में रजत पदक जीता है।
- सुनीता धोबी खेलो इंडिया पैरा गेम्स- 2023 में भी स्वर्ण पदक विजेता रही थी।
- सुनीता धोबी पीथावास हाथोज (जयपुर) निवासी दिव्यांग खिलाड़ी हैं।

24वीं डैफ राष्ट्रीय शतरंज चैम्पियनशिप

- यह चैम्पियनशिप पटना (बिहार) में आयोजित हुई।
- इस चैम्पियनशिप में राजस्थान का तीसरा स्थान रहा।
- इसमें राजस्थान की महिला और पुरुष टीम ने भाग लिया था।
- इसमें महिला कैटेगरी में सुमन भामू ने पहला स्थान प्राप्त किया।

मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता

- यह प्रतियोगिता पंचकूला (हरियाणा) में आयोजित हुई।
- इसमें जयपुर की हिमानी पूनिया (40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में) दूसरी बार विजेता बनी।
- हिमानी ने फाइनल में महाराष्ट्र की अदिति रोड को पराजित किया।

52वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता

- यह हाथरस (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की गई।
- राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता।
- इंडियन रेलवे ने फाइनल मुकाबले में राजस्थान को हराकर स्वर्ण पदक जीता।
- उत्तर प्रदेश व हरियाणा ने संयुक्त तीसरे स्थान पर रहते हुए कांस्य पदक जीता।

22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता

- यह लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित की गई।
- इसमें 200 मीटर रेस में राजस्थान की **मिस्टी काजला** ने कांस्य पदक जीता है।
- मिस्टी ने दुबई में आयोजित होने वाली एशियाई चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया।
- मिस्टी काजला राजस्थान में 200 और 400 मीटर रेस की पिछले 2 वर्षों से लगातार चैंपियन रही है।

पहली खेलो इंडिया ताइक्वांडो नेशनल वीमेन लीग

- यह ओडिशा के कटक शहर में आयोजित की गई।
- इसमें राजस्थान के जयपुर की **ट्यूलिप ओझा** ने जूनियर वर्ग में 46 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

पहला शूटिंगबॉल वर्ल्डकप

- यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- इसे शूटिंगबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की मेजबानी में आयोजित किया गया।
- इसमें **भारत ने दोनों वर्गों में महिला व पुरुष में स्वर्ण पदक जीता।**

पैरा वर्ल्ड कप-2024

- इसका आयोजन दिल्ली में किया गया।
- इसमें **राजस्थान की निशानेबाज मोना अग्रवाल** ने 10 मीटर एयर राइफल SH-1 कैटेगरी में **स्वर्ण पदक जीता।**
- मोना ने चीन की स्टार शूटर झेंग को फाइनल में हराया।
- इसके अलावा 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स टीम इवेंट में मोना ने रजत मेडल जीता।
- मोना ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही पेरिस ओलंपिक (2024) में कोटा भी हासिल किया है।

खेलो इंडिया इंटर जोनल सब जूनियर व जूनियर महिला खो-खो लीग

- यह जयपुर के चौगान स्टेडियम में आयोजित हुई।
- यह राजस्थान खो-खो संघ, अजमेर व जयपुर जिला खो-खो संघ के तत्वावधान में आयोजित की गई।
- इसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु व राजस्थान की टीमों ने भाग लिया।
- सब जूनियर टीम में **राजस्थान की टीम ने प्रथम स्थान** व महाराष्ट्र की टीम में दूसरा स्थान प्राप्त किया।

खेलो इंडिया नेशनल वीमेन लीग

- यह लीग 27 फरवरी, 2024 को झारखण्ड में आयोजित की गई
- इसमें राजस्थान ने **ऑल ओवर टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी** जीती।
- राजस्थान वुशू महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 1 रजत व 4 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। (रनर अप ट्रॉफी)
- राजस्थान की नीलम चौधरी ने स्वर्ण, अभिनव शर्मा ने रजत और मेघा जोशी, दिव्या यादव, प्राची व दिव्या ने कांस्य पदक जीता।

नेशनल पॉवरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024

- इसका आयोजन इंडियन पॉवरलिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा 23-25 फरवरी, 2024 को गुजरात के सूरत में किया गया।
- इसमें सब जूनियर के 80 किग्रा भार वर्ग में दीपक ने दो रजत पदक, सौरभ ने 56 किग्रा भारवर्ग में स्वर्ण पदक तथा शिवम ने 56 किग्रा भार वर्ग में दो कांस्य पदक जीते।
- जूनियर वर्ग में विनीत ने 65 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक, ललित ने 72 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक, साहबसिंह ने 60 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक तथा भूरा पहलवान ने 90 किग्रा भार वर्ग में दो स्वर्ण व कांस्य पदक जीते।

पीएम कुसुम C योजना में जोधपुर डिस्कॉम टॉप पर

- देश में जोधपुर डिस्कॉम बिजली वितरण करने वाली ऐसी पहली कंपनी है, जिसने एक माह में 3 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने हेतु 1.56 लाख किसानों से समझौता किया है।
- केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ जोधपुर डिस्कॉम ने 3,000 मेगावाट से ज्यादा के प्लांट लगाने के लिए टेंडर जारी किए।
- जोधपुर डिस्कॉम के अधीन 14 जिलों में 1,134 प्लांट लगाए जाएंगे। इससे 12 हजार करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश होगा।
- ये प्लांट स्थापित होकर ऑपरेशनल होने में एक साल समय लगेगा। इसके बाद आगामी रबी की सीजन में किसानों को बिजली मिलनी शुरू होगी।

पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना

- **पूरा नाम:** प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान ('Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha Evem Utthan Mahabhiyan')

- इस योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा फरवरी 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिये शुरू किया गया था।

पीएम कुसुम योजना के घटक:

- पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं और इन घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था।
- घटक A: भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।
- घटक B: 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
- घटक C: ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarisation)।

व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट का 12वाँ स्थान

- यात्रीभार की व्यस्तता के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 15 एयरपोर्ट में शामिल (वर्तमान में 12वाँ स्थान) है।
- इस संदर्भ में दिल्ली एयरपोर्ट देश में पहले स्थान (62.74 लाख यात्री) पर है।
- इस सूची में मुंबई (45.51 लाख), बेंगलुरु (30.46 लाख), हैदराबाद (20.77 लाख) और चेन्नई (17.51 लाख) का क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवाँ स्थान है।

हर घर जल में प्रदेश के 11 जिले टॉप परफॉर्मर रहे जबकि 24 जिले अति पिछड़े रहे

- इसके तहत पहली बार राजस्थान के जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तय की गई है।
- इसमें राजस्थान के 48 जिलों की रैंकिंग जारी की गई है।
- इसके लिए तीन फोकस एरिया (व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार) में 14 मानक या गोल्स तय किए गए थे।
- जल जीवन मिशन (JJM) हर घर नल से पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल है।
- इनमें जोधपुर और जयपुर शहरी क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है।
- जल जीवन मिशन के तहत 48 जिलों में से 11 जिले टॉप परफॉर्मर रहे।

- इसमें **डीडवाना- कुचामन** (100 में 75.95 अंक) (पहला स्थान) और खैरथल-तिजारा (70.47 अंक) जिले टॉप परफॉर्मर ('A' श्रेणी में) हैं।
- इसके अलावा श्रीगंगानगर, सलूमबर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नीम का थाना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर को 'B' श्रेणी में रखा गया है।
- राजस्थान के 13 जिलों में कामकाज औसत श्रेणी ('C' श्रेणी) का है।
- राज्य के 24 जिले की परफॉर्मेंस सबसे खराब हैं। इन जिलों को 'D' श्रेणी में शामिल किया गया है।

मनरेगा में 100 दिन का रोजगार देने संबंधी रैंकिंग

- राजस्थान में सीकर जिला मनरेगा में तय 100 दिन का रोजगार दिलाने में 87 अंकों के साथ राजस्थान में पहले स्थान पर रहा।
- इस रैंकिंग में बूँदी जिला 33वें स्थान पर रहा।

आनंद चौधरी को दूसरी बार रामनाथ गोयनका अवॉर्ड

- वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी को दूसरी बार देश का प्रतिष्ठित 'रामनाथ गोयनका' एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवॉर्ड प्रदान किया गया है।
- चौधरी को यह अवार्ड राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं को लेकर की गई रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है।
- हिंदी प्रिंट श्रेणी में वर्ष 2022 के लिए आनंद चौधरी की रिपोर्ट 'गरीब अपात्र, कोठियों वाले पात्र' का चयन किया गया।

सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 2024

- यह पुरस्कार राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर्स के लिए दिया जाता है।
- इस वर्ष यह पुरस्कार सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी और सब जूनियर वर्ग में वृंदा शर्मा को दिया जाएगा।
- इस वर्ष राजस्थान की क्रिकेट में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला खिलाड़ी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है।
- लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 70 के दशक में भारतीय टीम में खेले राजस्थान की सीता भार्गव को दिया गया है।
- सीनियर वर्ग में विकेटकीपर बल्लेबाज ज्योति चौधरी ने इस वर्ष बीसीसीआई के टूर्नामेंटों में कुल 369 रन बनाए और विकेटकीपर के रूप में 41 कैच भी लिए।
- सब जूनियर वर्ग में पुरस्कार के लिए चुनी गई वृंदा शर्मा ने 209 रन के साथ चार विकेट हासिल किए।

- जूनियर वर्ग में इस बार यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है।
- जूनियर वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सिद्धि शर्मा का रहा लेकिन उन्हें पिछली बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है।

राजस्थान के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022-23

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2024 को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के लिए वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए।
- संगीत, नृत्य, नाटक, लोक व जनजातीय कलाएं, कठपुतली और संबद्ध रंगमंच कला के क्षेत्र में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों (दो संयुक्त पुरस्कार) को वर्ष 2022 और 2023 के लिए पुरस्कार प्रदान किए।
- राजस्थान से 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया -
 1. **वसंत काबरा** (सरोद वादक) वर्ष 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
 2. **दौलतराम वेध** (अलाइड थिएटर आर्ट्स (लाइटिंग)) वर्ष 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
 3. **गफरुद्दीन मेवाती जोगी** (भपंग वादक) वर्ष 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार
 4. **मोड़नुद्दीन खान** (सारंगी वादक) वर्ष 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार

- अकादमी पुरस्कार साल 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं।
- अकादमी पुरस्कार के तहत ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम् के अलावा 1,00,000/- रुपये की नकद धनराशि दी जाती है।
- अकादमी फेलोशिप के तहत 3,00,000/- रुपये की नकद धनराशि प्रदान की जाती है।

डॉ. गजेसिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार

- राजस्थानी भाषा के प्रतिष्ठित कवि-आलोचक डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित को उनकी राजस्थानी काव्यकृति 'पळकती प्रीत' के लिए साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत डॉ. राजपुरोहित को 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, ताम्र फलक एवं श्रीफल प्रदान कर पुरस्कृत किया गया।

डीग कलेक्टर श्रुति भारद्वाज को ई-केवाई में प्रथम स्थान

- डीग कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने राज्य में आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
- श्रुति भारद्वाज ने नीमकाथाना कलेक्टर रहते जिले में आयुष्मान भारत कार्ड ई-केवाईसी में श्रेष्ठ कार्य किया।

ई-केवाईसी (e-KYC)

- e-KYC: Electronic Know Your Customer
- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपकी पहचान की पुष्टि और पर्सनल जानकारी की प्राप्ति डिजिटल रूप में की जाती है।
- यह भारत सरकार द्वारा आधार कार्ड प्रमाणीकरण के लिए व नागरिकों को अधिकारिक कार्यों और सेवाओं के लिए पात्र बनाती है।
- इसका उपयोग विभिन्न सेक्टर, जैसे वित्तीय सेवाएँ, मोबाइल सिम कार्ड की प्राप्ति और अन्य ऑनलाइन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है।
- इस की प्रक्रिया सुरक्षित और सुगम होती है और यह लोगों की पहचान प्रमाणित करने में मदद करती है।

राजस्थान रोडवेज का डीजल श्रेणी में देश में दूसरा स्थान

- राज्य सड़क परिवहन उपक्रम संघ (ASRTU) द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता पुरस्कार अवॉर्ड के लिए सम्मानित किया है।
- रोडवेज को यह अवॉर्ड ईंधन दक्षता श्रेणी और कर्मचारियों की उत्पादकता श्रेणी में दिया गया।

दीया कुमारी

- 'राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन' की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं।
- दीया कुमारी वर्तमान में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं।
- संदीप वर्मा (सार्वजनिक निर्माण के अतिरिक्त मुख्य सचिव) को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड (RSRDC)

- यह 1979 में RSBCC के रूप में स्थापित किया गया था, 2001 में नाम बदलकर RSRDC कर दिया गया ।
- यह राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाला उद्यम है।
- इसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित किया गया।

महाराजा हुकुम सिंह

- यह जैसलमेर के राजपरिवार के सदस्य तथा जैसलमेर के पूर्व विधायक रहे हैं।
- इनका 97 वर्ष की आयु में 17 मार्च, 2024 को निधन हो गया।
- यह जैसलमेर के पहले जिला प्रमुख (1959-1967) रहे। इसके अलावा वह वर्ष 1957 और 1962 में लगातार 2 बार जैसलमेर से विधायक भी चुने गए।

अंकित खंडेलवाल

- यह देश के विख्यात एंकर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं।
- इन्हें जयपुर में 'स्वच्छ भारत अभियान' का ब्रांड एंबेसेडर नियुक्त किया है।

ओंकार सिंह लखावत

- इन्हें 'राजस्थान विरासत संरक्षण एवं संवर्धन प्राधिकरण' (Rajasthan Heritage Conservation and Promotion Authority - RHCPA) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
- ओंकार सिंह इस प्राधिकरण के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं।
- **नोट:** 'राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण' का गठन 19 अगस्त, 2006 में किया गया।

धनंजय सिंह खींवर

- राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

सैनिक कल्याण और देव नारायण बोर्ड सहित 7 बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए

- राजस्थान सरकार ने 7 निगम और बोर्ड में नियुक्तियों की हैं-
- 1. किसान आयोग के अध्यक्ष - छोटूराम (C.R.) चौधरी (पूर्व सांसद, नागौर)
- 2. जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष - जसवंत विश्नोई
- 3. सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष - प्रेम सिंह बाजौर
- 4. विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष - रामगोपाल
- 5. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष - राजेंद्र नायक
- 6. माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष - प्रहलाद टांक
- 7. देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष - ओमप्रकाश भड़ाना

राजस्थान सरकार ने 6 नए अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किए

- राजस्थान सरकार द्वारा 12 मार्च 2024 को निम्न लिखित 6 नए महाधिवक्ताओं की नियुक्ति की-
- 1. श्री सन्दीप तनेजा (राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर)
- 2. श्री विज्ञान शाह (राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर)
- 3. श्री राजेश पंवार (राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर)
- 4. श्री महावीर विश्नोई (राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर)
- 5. श्री मनीष (राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर)
- 6. श्री शिवमंगल शर्मा (उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली)

प्रो. निष्ठा जसवाल

- इन्हें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र द्वारा 4 मार्च 2024 को डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया, जो कि जयपुर में स्थित है।
- प्रो. निष्ठा जसवाल के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो, तक पद पर रहेगी।

रोजी बारोलिया बनी प्रदेश की पहली पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर

- ट्रांसवुमन रोजी बारोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनवाने वाली ट्रांसजेंडर बन गई हैं।
- रोजी जयपुर निवासी हैं और पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट और ट्रांस राइट एक्टिविस्ट भी हैं।

राजस्थान में पहली बार गोल्ड माइंस की नीलामी

- राजस्थान में पहली सोने की खदान की नीलामी 2 व 3 मई को होगी।
- ये खानें बांसवाड़ा के भूकिया-जगपुरा और कांकरिया-गारा में हैं।
- इनमें भूकिया-जगपुरा की माइनिंग लीज और कांकरिया-गारा की कंपोजिट लाइसेंस (खोज व खनन) के लिए ई- नीलामी होगी।
- इनकी नीलामी भारत सरकार के MSTC पोर्टल द्वारा होगी।
- बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के भूकिया-जगपुरा के 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोने के विपुल भण्डार हैं।
- इस क्षेत्र में व्यापक एक्सप्लोरेशन के बाद 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आर्सेनिक आकलन किया गया है जिसमें सोने के धातु की मात्रा 222.39 टन आंकी गई है।
- भूकिया जगपुरा में गोल्ड की इन खानों से सोने के साथ ही प्रचुर मात्रा में कॉपर, निकल और कोबाल्ट खनिज प्राप्त होगा।

- **नोट:** मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा खान व भूविज्ञान विभाग के मंत्री भी हैं।
- देश में **सर्वाधिक स्वर्ण भण्डार बिहार में हैं**, जबकि राजस्थान में देश के करीब 25% स्वर्ण भण्डार अनुमानित हैं।

राजस्थान के स्वर्ण भण्डार वाले जिले

- बाँसवाड़ा: भूकिया- जगपुरा
- दौसा: ढाणी बसेड़ी
- डूंगरपुर: भारकुंडी अरावली क्षेत्र
- उदयपुर: डेगोचा

राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में पहले स्थान पर रहा

- केन्द्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट (दिसम्बर, 2023) के अनुसार राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन राजस्थान (24,120 मेगावाट) में देश में शीर्ष राज्य है।
- राजस्थान में सौर एवं पवन ऊर्जा की 426 गीगावाट की सर्वाधिक उपलब्धता है।
- राजस्थान में अब तक 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिसमें 19 गीगावाट सौर ऊर्जा एवं 5 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है।
- विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला (फलोदी) (2245 मेगावाट) में स्थापित है।

लोकसभा चुनावों में मतदाताओं हेतु 'एप' सुविधा

- राजस्थान में 18वें लोकसभा चुनाव हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की सहायता हेतु विभिन्न एप द्वारा विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- इसके तहत राज्य के लगभग 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को नाम जुड़वाने से लेकर बूथ व उम्मीदवार की जानकारी एप पर मिल सकेगी।
- इसके तहत ऑनलाइन सिस्टम के तहत आवेदन जमा करना होगा। आयोग की तरफ से एप के जरिए ही स्वीकृति मिलेगी।
- वोटों की गिनती व चुनाव नतीजों की हर लोकसभा सीट की घर बैठे जानकारी मिल सकेगी।
- इसमें पोस्टल बड्डी पोर्टल के माध्यम से डाक मतपत्रों के लिए आवेदन से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी।

राजस्थान में मतदाता संबंधी जानकारी

- वर्तमान में राजस्थान में 5.32 करोड़ मतदाता है। (2019 की तुलना में 9.48% बढ़े)

- पुरुष मतदाता: 2.77 करोड़
- महिला मतदाता: 2.55 करोड़
- थर्ड जेंडर मतदाता: 616
- राजस्थान में मतदाताओं के लैंगिक अनुपात में सुधार हुआ है यह वर्तमान में प्रति हजार पुरुषों पर 920 की तुलना में बढ़कर 923 हो गया है।

लोकसभा चुनावों हेतु विभिन्न एप

- **सक्षम:** भारतीय निर्वाचन आयोग के इस एप के द्वारा दिव्यांग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदान के व्हील चेयर के लिए पहले से अनुरोध कर बुक करा सकते हैं।
- **वोटर हेल्पलाइन:** सूची में नाम शामिल से लेकर चुनाव से संबंधित सभी सेवाओं के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से लोग मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। नाम शामिल नहीं होने या कट जाने पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने के ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- **नो योर कैंडिडेट:** कोई भी व्यक्ति या मतदाता अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम, शिक्षा, उनके आपराधिक रिकॉर्ड आदि की जानकारी उपलब्ध है।
- **ई-लर्निंग:** यह मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान बढ़ाने के लिए है।
- **सी-विजिल एप:** इसके तहत कोई भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में चुनाव आयोग को शिकायत देकर सूचित कर सकते हैं। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला उसका वीडियो या फोटो भी अपलोड किया जा सकता है।
- **वोटर टर्न आउट:** इसके तहत मतगणना के समय यह सक्रिय होने पर मतगणना से संबंधित जानकारी मिल सकेगी।
- **सुविधा कैंडिडेट:** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अब किसी चुनावी कार्यक्रम की मंजूरी के लिए चुनाव अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी।
- **इनकोर:** इस एप के जरिए चुनाव प्रबंधन की कोर टीम से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही की जानकारी अपडेट रहेगी।

होम वोटिंग

- लोकसभा चुनाव में देश में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 80 वर्ष की आयु के लोगों को होम वोटिंग सुविधा दी गई थी। लोकसभा में यह समयसीमा बढ़ाकर 85 वर्ष की गई है।
- देश में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की पहल की गई है।
- विशेष टीम राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों की मौजूदगी में होम वोटिंग वाले मतदाता के घर पहुंचकर पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कराएंगे।
- राजस्थान के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता है।

‘ऑपरेशन निर्भय’

- यह ऑपरेशन भरतपुर रेंज के सभी जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग और गंगापुर सिटी में शुरू किया गया है।
- इसे आगामी लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और भय मुक्त चुनाव कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- इसके तहत वांछित अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई।

2

राष्ट्रीय परिदृश्य

राजव्यवस्था एवं शासन

नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित

- नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship (Amendment) Act) 11 मार्च 2024 को देश में लागू हो गया।
- इस अधिनियम के तहत नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया था।
- इस अधिनियम में 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।
- यह भारत के तीन पड़ोसी देशों से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का कानून है।
- CAA 2019 से पहले किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए यह समय अवधि 5 साल कर दी गई है।

प्रमुख प्रावधान

- अधिसूचित नियम के अनुसार आवेदकों को छह प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे और भारत में 'प्रवेश की तारीख' बतानी होगी।
- स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में जन्म प्रमाण पत्र, कास्तकारी रिकॉर्ड, पहचान पत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस, स्कूल या शैक्षिक प्रमाण पत्र शामिल हैं।
- आवेदकों को "स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान" द्वारा जारी "पात्रता प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा जो पुष्टि करता है कि वह "हिंदू / सिख / बौद्ध / जैन / पारसी / ईसाई समुदाय से संबंधित है और उपर्युक्त समुदाय का सदस्य बना हुआ है।
- नागरिकता के लिए याचिका ऑनलाइन दायर करनी होगी और एक जिला-स्तरीय समिति के माध्यम से एक अधिकार प्राप्त समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी।

- जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ डाक अधीक्षक करेंगे।
- नोट: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 को 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर, 2019 को विधेयक को मंजूरी दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों की मतदान के लिए रिश्वत (Note for Vote) मामलों की विशेषाधिकार छूट समाप्त की

- सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2024 को फैसला दिया कि सांसदों और विधायकों को वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर अभियोजन से कोई छूट नहीं मिल सकती है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम भारत राज्य मामले में अपने 1998 के फैसले को खारिज कर दिया।
- कोर्ट ने एजेंसियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम) के तहत रिश्वत के मामलों में सांसदों/विधायकों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की अनुमति दे दी है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने दो-स्तरीय परीक्षण में खरे उतरने वाले विशेषाधिकारों को ही न्यायिक कार्रवाई से छूट मिल सकती है :-
 - ◆ वह सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा होना चाहिए।
 - ◆ वह विशेषाधिकार एक सांसद या विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित होना चाहिए।
- न्यायालय ने कहा कि सांसदों या विधायकों को मिले विशेषाधिकारों के संबंध में यह निर्णय राज्यसभा के चुनावों और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए होने वाले चुनावों पर भी समान रूप से लागू होंगे।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत सांसदों को संसद या किसी संसदीय समिति में कहे गए किसी भी वक्तव्य या दिए गए वोट के संबंध में कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करता है।

- इसी तरह, अनुच्छेद 194(2) विधायकों को विधानमंडल या किसी समिति में कहे गए किसी भी वक्तव्य या दिए गए वोट के संबंध में कानूनी कार्रवाई से छूट प्रदान करता है।
- इस निर्णय ने कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006) के निर्णय को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि राज्यसभा के चुनाव विधायिका की कार्यवाही नहीं हैं, बल्कि मताधिकार का एक मात्र अभ्यास हैं।

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर कोविंद समिति की सिफारिशें

- पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली “वन नेशन वन इलेक्शन” पर उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- इस रिपोर्ट में 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है।

मुख्य सिफारिशें

- इस रिपोर्ट के अनुसार 2029 से देश में पहले चरण लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं।
- इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव कराए जाएं।
- समिति ने भारत के संविधान में 15 संशोधनों का सुझाव दिया है। ये दो संविधान संशोधन विधेयकों के माध्यम से किए जा सकते हैं।

पहला विधेयक

- पहला विधेयक एक साथ चुनाव प्रणाली में परिवर्तन और लोकसभा या राज्य विधानसभा के लिए उनके निर्धारित पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान के लिए होगा।
- इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद-82A-सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
- इस विधेयक को राज्य सरकारों से परामर्श या राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता के बिना संसद द्वारा पारित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 82A उस प्रक्रिया को स्थापित करेगा जिसके द्वारा देश लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव की प्रणाली की ओर बढ़ेगा।
- अनुच्छेद 82A(2) के प्रस्तावित प्रावधान के तहत नियत तारीख के बाद होने वाले किसी भी आम चुनाव में गठित सभी विधानसभाएँ लोक सभा के कार्यकाल पूरा होने पर भंग हो जाएंगी।

- प्रस्तावित विधेयक अनुच्छेद 327 में संशोधन की भी सिफारिश करता है, जो संसद को लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और निर्वाचन क्षेत्रों का परिशीमन भी शामिल है।
- यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है, तो अनुच्छेद 83(3) और 172(3) में सुझाए गए संशोधनों के अनुसार, शेष अवधि को “असमाप्त कार्यकाल” (Unexpired Term) के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

दूसरा विधेयक

- दूसरा विधेयक नगरपालिका और पंचायत चुनावों के साथ-साथ भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक मतदाता सूची के निर्माण से संबंधित होगा, जिसमें प्रत्येक मतदाता और उस सीट का विवरण होगा जिसके लिए वे मतदान करने के पात्र हैं।
- यह विधेयक उन विषयों से संबंधित है जिन पर राज्यों के पास कानून बनाने की प्राथमिक शक्ति है – और इसलिए, इसे लागू करने से पहले भारत के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन या अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- अनुच्छेद 368(2) के तहत, राज्य सूची के विषयों से संबंधित किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित होने से पहले देश के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा।
- यह विधेयक नगरपालिका और पंचायत चुनावों से संबंधित है, जो “स्थानीय सरकार” शीर्षक वाली राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, उन्हें राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।
- समिति ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 324A शामिल करने का सुझाव दिया है। यह नया अनुच्छेद संसद को यह सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देगा कि नगर पालिका और पंचायत चुनाव आम चुनाव (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं) के साथ ही आयोजित किए जाएं।
- समिति द्वारा प्रस्तावित नया अनुच्छेद 325(2) ‘लोक सभा, राज्य के विधानमंडल या नगर पालिका या पंचायत में चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एकल मतदाता सूची’ बनाएगा।

एक देश- एक चुनाव (One Nation, One Election) हेतु समिति

- एक देश- एक चुनाव (One Nation, One Election) हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 में एक समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति के सदस्यों में गुलाम नबी आजाद, अमित शाह, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी और हरीश साल्वे शामिल हैं।
- कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ. नितेन चंद्रा समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य थे।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हुआ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 मार्च 2024 को उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024' विधेयक को मंजूरी दी।
- यह मंजूरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत दी गई।
- संविधान के अनुच्छेद 201 में उल्लेख है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखा जाता है तब राष्ट्रपति ही उस विधेयक के संदर्भ में सहमति या असहमति का निर्धारण करेगा।
- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC) अधिनियम की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है।
- नोट:** गोवा में भी समान नागरिक संहिता लागू है लेकिन वहां यह 1870 के दशक से लागू है जब राज्य पुर्तगालियों के अधीन था।
- उत्तराखंड राज्य विधानसभा ने 07 फरवरी, 2024 को विधेयक पारित किया गया था।
- सेवानिवृत्त न्यायाधीश **रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता** वाली समिति ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप पेश किया था।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता

- इस कानून को चार खंडों- विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार, सहवासी संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) और विविध में विभाजित किया गया है।
- आदिवासियों को** उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा गया है।
- इस कानून में हलाला, इद्दत और तलाक (मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह और तलाक से संबंधित रीति-रिवाज) जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- यदि कोई व्यक्ति हलाला का दोषी साबित होता है तो इस अधिनियम के तहत 3 साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
- इसके तहत विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच ही किया जा सकता है। विवाह की आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
- UCC कानून में विवाह और तलाक का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा न करने पर संबंधित दम्पति को सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
- यह महिलाओं को संपत्ति और विरासत अधिकारों से संबंधित मामलों में समान अधिकार सुनिश्चित करता है।
- इस अधिनियम में जायज व नाजायज बच्चे में कोई भेद नहीं किया गया है। लिव इन रिलेशन का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

समान नागरिक संहिता

- समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत संविधान के भाग IV के अनुच्छेद 44 में उल्लेख है।
- यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) का भाग है जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ाया गया

- असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ जिलों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) को अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
- गृह मंत्रालय से इसकी अधिसूचना हाल ही में जारी की थी जो 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी हुई।
- असम के चार जिलों से AFSPA को 1 अप्रैल से छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। ये जिले हैं - तिनसुकिया, डिब्रुगढ़, चराइदेव और शिवसागर।
- अरुणाचल प्रदेश में AFSPA को तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले सहित एक अन्य जिले के तीन पुलिस थाना क्षेत्र में छह महीने के लिए बढ़ाया गया है।
- नागालैंड में दीमापुर, न्यूलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक और परेन सहित पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्र में छह महीने के लिए AFSPA बढ़ाया गया है।
- गृह विभाग ने अधिसूचना में कहा है कि इन जिलों को कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अशांत क्षेत्र माना गया है, इसलिए अधिनियम की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।

AFSPA

- AFSPA का पूरा नाम The Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 है।
- यह अधिनियम 11 सितंबर 1958 को लागू हुआ था।
- केंद्र सरकार या राज्यपाल पूरे राज्य या उसके किसी हिस्से में AFSPA लागू कर सकते हैं।
- AFSPA के तहत सुरक्षा बलों को कानून के खिलाफ जाने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने, सर्च और गिरफ्तारी का अधिकार है।
- इसके तहत किसी तरह की कार्रवाई करने पर सैनिकों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दो गुटों पर प्रतिबंध

- केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है।
- यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हुआ और 5 साल तक चलेगा।
- दोनों गुटों को भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी ठहराया गया।
- सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (भट गुट) जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी आंदोलनों को सहायता करने और बढ़ावा देने में शामिल था।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA):

- इसे वर्ष 2019 में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019 के रूप में संशोधित किया गया था।
- इसे 'आतंकवाद विरोधी कानून' के नाम से भी जाना जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों और इससे जुड़े संगठनों पर रोक लगाना है।

भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ

- केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और टिपरा मोथा तथा अन्य हितधारकों के बीच 2 मार्च 2024 को त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।

- यह समझौता राज्य के स्थानीय लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान लाने हेतु किया गया है।

मुख्य बिन्दु

- टिपरा (TIPRA) मोथा को टिपराहा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और पहले त्रिपुरा में एक सामाजिक संगठन था।
- TIPRA (द इंडीजिनियस प्रोग्रेसिव रिजनल एलायंस) का नेतृत्व प्रद्योत देबबर्मा कर रहे हैं। यह वर्तमान में त्रिपुरा विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है।
- समझौते के तहत त्रिपुरा के मूल निवासियों के इतिहास, भूमि और राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने पर सहमति बनी।
- सभी पक्षों के बीच विवादों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए, पारस्परिक सहमति वाले बिंदुओं पर निर्धारित समयसीमा में अमल के लिए एक संयुक्त कार्य समूह के गठन पर भी सहमति बनी।

18वीं लोकसभा हेतु चुनावों की घोषणा

- चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को, 2024 के आम चुनावों के साथ-साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई।
- देश में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे, जबकि मतगणना 4 जून को होगी।
- इसके अलावा, चुनाव आयोग द्वारा सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की गई।
- भारत में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं और 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र 1.5 करोड़ कर्मियों द्वारा संचालित हैं। इस चुनाव में 1.82 करोड़ पहली बार मतदाता होंगे।
- वर्तमान 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है।
- देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 84 संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
- चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू हो गई।

आदर्श आचार संहिता (MCC)

- आदर्श आचार संहिता (MCC) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए जारी दिशानिर्देशों का एक समूह है।
- MCC चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की तारीख तक लागू रहता है।
- जैसे ही संहिता लागू होती है, सत्ता में रहने वाली पार्टी, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में, को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह प्रचार के लिए अपनी सरकारी स्थिति का दुरुपयोग न करे।
- अतः केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसी किसी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर सके।
- इस संहिता के तहत मंत्री आधिकारिक दौरों को चुनाव कार्य के साथ नहीं जोड़ सकते हैं तथा इसके लिए आधिकारिक मशीनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
- निर्वाचन आयोग MCC को लागू करने के लिए शायद ही कभी दंडात्मक कार्रवाई का सहारा लेता है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, कुछ नेताओं को उनके भाषणों से चुनावी माहौल को खराब करने से रोकने के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

3

आर्थिक परिदृश्य

पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) को मंजूरी दी है।
- इस योजना हेतु केंद्र सरकार ने 75,021 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी है।
- यह योजना 13 फरवरी, 2024 को शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने (Rooftop Solar) और 1 करोड़ घरों के लिए प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
- केंद्र सरकार 2 किलोवाट सिस्टम स्थापित करने की लागत का 60% और 2-3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम की लागत का 40% पैसा वहन करेगी।
- इसके तहत 1 किलोवाट क्षमता वाली सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक वाली प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- इस योजना के तहत 3 किलोवाट तक के रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 7 प्रतिशत के कोलेटरल मुक्त कम-ब्याज दर वाले ऋण का लाभ मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर अपनाने के रोल मॉडल के रूप में देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित किया जाएगा।
- इस योजना के तहत आवासीय क्षेत्र में छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावॉट की सौर क्षमता की वृद्धि होगी।

भारत में 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2024 को 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
- ये परियोजनाएँ गुजरात के धोलेरा, साणंद, और असम के मोरीगांव में स्थापित की जाएंगी।
- ये सेमीकंडक्टर परियोजनाएँ भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत आती हैं।
- इन परियोजनाओं की लागत करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये है।

- इनका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब में बदलने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश में नवाचार को बढ़ावा देना है।

धोलेरा

- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (DSIR) में भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट (fabrication plant) स्थापित होगा।
- यह परियोजना टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा ताइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन (PSMC) के साथ साझेदारी में स्थापित किया जाएगा।
- इस परियोजना पर 91,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा।

मोरीगांव

- सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (ATMP) के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) द्वारा असम के मोरीगांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा स्थापित की जाएगी।
- इस पर कुल निवेश लगभग 27,000 करोड़ रुपये का होगा।

साणंद

- सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा गुजरात के साणंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) सुविधा स्थापित की जाएगी।
- इस पर कुल निवेश लगभग 7,500 करोड़ रुपये होगा।

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन

- यह मिशन वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में कुल 76,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ लॉन्च किया गया।
- यह देश में स्थायी अर्द्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिये व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य अर्द्धचालक, डिस्प्ले मैनुफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
- इस मिशन का लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

केंद्र सरकार द्वारा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी

- केंद्र सरकार ने 15 मार्च को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी दी है।
- इस नीति का उद्देश्य घरेलू ईवी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना और वैश्विक ईवी निर्माताओं को भारत में निवेश हेतु आकर्षित करना है।
- इस नीति के तहत एक कंपनी को न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- इसके तहत कंपनी को अपना प्लांट 3 साल में शुरू करना होगा।
- कंपनी को 5 साल के भीतर 50% घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) तक भी पहुंचना होगा।
- विनिर्माण के दौरान घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) बढ़ाने के लिए, सरकार का लक्ष्य तीसरे वर्ष तक 25% और पांचवें वर्ष तक 50% का स्थानीयकरण स्तर हासिल करना है।
- कुल 5 वर्षों की अवधि के लिए 35,000 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक के न्यूनतम Cost, Insurance, and Freight (CIF) मूल्य वाले वाहनों पर 15% सीमा शुल्क लागू होगा।
- इसके लिए निर्माता को 3 साल की अवधि के भीतर भारत में विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
- घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) 50% पहुंचने पर कंपनियों की बैंक गारंटी वापस कर दी जाएगी।

ग्रिड-इंडिया को मिनीरत्न कंपनी का दर्जा मिला

- ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड -इंडिया) ने मिनीरत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) का दर्जा हासिल किया है।
- ग्रिड-इंडिया पर भारतीय बिजली प्रणाली के दोषरहित और निर्बाध संचालन की देखरेख करने, विद्युत के कुशल हस्तांतरण को सुनिश्चित करती है।
- यह किफायती और कुशल थोक बिजली बाजारों की सुविधा प्रदान करता है और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करती है।
- मिनीरत्न श्रेणी-I दर्जा उन केंद्रीय उद्यमों को दिया जाता है, जो बीते तीन वर्षों में लगातार लाभ में रहे हों, जिनका पूर्व-कर लाभ तीन वर्षों में से कम-से-कम किसी एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक रहा हो और शुद्ध लाभ भी हुआ हो, उन्हें मिनीरत्न-I का दर्जा दिया जाता है।

ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया):

- इसकी स्थापना मार्च 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की एक कंपनी है।
- इसे पहले पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (POSOCO) के नाम से जाना जाता था।
- इसका नाम 09 नवंबर, 2022 को बदलकर ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (GRID-इंडिया) कर दिया गया।

4

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश

- फ्रांस ने संविधान में संशोधन करते हुए महिलाओं को गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार दिया है।
- फ्रांस ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश है।

फ्रांस में गर्भपात संबंधी कानून की पृष्ठभूमि

- फ्रांस में वर्ष 1975 में एक कानून बनाकर गर्भपात को वैधानिक अधिकार दिया गया था।
- इस कानून में दस सप्ताह तक गर्भपात की इजाजत थी।
- वर्ष 2001 में इसे बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया गया और 2022 में इसे बढ़ाकर 14 सप्ताह कर दिया गया।
- यह प्रावधान आधुनिक फ्रांस की स्थापना के बाद 25वें संविधान संशोधन और 2008 के बाद पहला संशोधन है।

स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वाँ सदस्य बना

- स्वीडन आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) का 32वाँ सदस्य बन गया है।
- इस संदर्भ में 7 मार्च 2024 को वाशिंगटन में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की गयी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में फिनलैंड 31वें सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ था।

स्वीडन

- स्वीडन 1995 से यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य है।
- स्वीडन पश्चिम में नॉर्वे और उत्तर पूर्व में फिनलैंड के साथ भूमि सीमा साझा करता है।
- नॉर्डिक देश स्वीडन के आर्कटिक नॉर्थ को 'मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि' (land of the midnight sun) कहा जाता है।

उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO):

- यह उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक अंतरसरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है।
- इसका गठन 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत किया गया था।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में स्थित है।

सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु भारत ने 'G4 मॉडल' पेश किया

- ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत द्वारा संवाद और बातचीत के लिए सुरक्षा परिषद सुधारों के लिए 'G4 मॉडल' प्रस्तुत किया है।
- यह मॉडल 7 मार्च 2024 को सुरक्षा परिषद सुधार (IGN) पर अंतर-सरकारी वार्ता में प्रस्तावित किया गया।

G4 मॉडल

- इसके तहत 6 नए स्थायी और चार या पांच अस्थायी सदस्य जोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता 15 से बढ़कर 25-26 हो जायेगी।
- 6 नए स्थायी सदस्यों में से अफ्रीकी महाद्वीप से 2, एशिया प्रशांत देशों से 2, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों से 1 तथा पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से 1 सदस्य का प्रस्ताव किया गया है।
- G4 मॉडल के तहत कौनसे सदस्य देश नई स्थायी सदस्य बनेंगे, यह निर्धारित नहीं करता है।
- इसके तहत यह निर्णय लोकतांत्रिक और समावेशी चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाएगा।
- नए स्थायी सदस्यों के पास, एक सिद्धांत के रूप में, वर्तमान स्थायी सदस्यों के समान ही जिम्मेदारियां और दायित्व होंगे, लेकिन वे तब तक वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे जब तक कि समीक्षा के दौरान मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है।

सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता

- इसकी स्थापना से अब तक वैश्विक स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं जो इसमें सुधार और सभी के लिए समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है।
- वर्तमान परिषद में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका सहित ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व नहीं मिला है जो विकासशील देशों के साथ अन्याय है।
- वर्तमान व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में परिषद की अक्षमता सुधार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।

- वर्तमान में, केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्तियाँ हैं जो यूक्रेन और गाजा जैसी वैश्विक चुनौतियों और संघर्षों को रोकने में बाधा उत्पन्न करती है।

‘व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA)’

- भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) ने 10 मार्च 2024 को एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए।

TEPA

- Full Form:** Trade and Economic Partnership Agreement (व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता)
- भारत और चार विकसित देशों के बीच व्यापार समझौता, जिसे TEPA के नाम से जाना जाता है।
- पहली बार भारत ने यूरोप के किसी प्रमुख आर्थिक संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते में अगले 15 वर्षों के भीतर 100 अरब डॉलर के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की **बाध्यकारी प्रतिबद्धता** है।
- इस FTA के साथ, भारतीय निर्यातकों के पास बड़े यूरोपीय और वैश्विक बाजारों तक पहुंच होगी, जिससे विकास की आशाजनक संभावनाएं पैदा होंगी।

समझौते के मुख्य प्रावधान

- EFTA ने भारत में निवेश को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसका उद्देश्य अगले 15 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भंडार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। निवेश से भारत में दस लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ पैदा होंगी।
- EFTA अपनी 92.2% टैरिफ लाइनों की पेशकश कर रहा है, जो भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है।
- इसमें बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100% गैर-कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (PAP) पर टैरिफ रियायत शामिल है।
- भारत ने डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों को बाहर रखा है।
- TEPA आईटी, व्यवसाय, शिक्षा, खेल और ऑडियो-विजुअल सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देगा।
- यह सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी, व्यावसायिक उपस्थिति और प्रमुख कर्मियों के बेहतर प्रवेश और अस्थायी प्रवास के माध्यम से बेहतर पहुंच प्रदान करता है।

- TEPA भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड के माध्यम से यूरोपीय संघ तक अपनी बाजार पहुंच का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है।
- यह समझौता भारत के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा।

EFTA

- Full Form: European Free Trade Association** (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ)
- EFTA एक अंतरसरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी।
- इसमें यूरोप के स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन देश शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य सदस्य देशों को लाभ पहुंचाने के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।
- EFTA यूरोप में तीन (अन्य दो ईयू एवं ब्रिटेन) में से एक महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक है।
- EFTA देशों में से **स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार** है जिसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है।

WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

- यह सम्मेलन 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में आयोजित किया गया।
- सम्मेलन की अध्यक्षता UAE के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल जायद ने की।

WTO के ‘सेवा व्यापार के लिए अच्छे रेगुलेटरी प्रैक्टिसेज पर नए डिसिप्लिन’ लागू हुए

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने 27 फरवरी को सेवाओं के घरेलू विनियमन पर नए दायित्वों (New Disciplines on Services Domestic Regulation) को अपनाया।
- इसका लक्ष्य व्यापार लागत को प्रति वर्ष लगभग \$150 बिलियन तक कम करना है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), कनाडा, जापान, चीन, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं सहित 72 देश इस प्लुरिलेटरल समझौते (Plurilateral Agreement) का हिस्सा हैं।
- नोट:** भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है।
- भारत, सैद्धांतिक रूप से, WTO जैसे प्लेटफार्मों पर प्लुरिलेटरल समझौते के खिलाफ रहा है क्योंकि उसका मानना है कि यह उसके मल्टिलेटरल व्यापार फ्रेमवर्क को कमजोर कर सकता है।

- बता दें कि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट WTO के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं और इन्हें WTO समझौते के साथ समग्र रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- इसके विपरीत प्लुरिलेटरल एग्रीमेंट वैकल्पिक होते हैं और केवल उन सदस्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं जो उन्हें अनुमोदित करते हैं।
- सेवाओं के घरेलू विनियमन पर नए दायित्व, WTO समझौते में सेवाओं की आपूर्ति के लिए परमिट मांगने पर पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव खत्म करने की यह पहली प्रतिबद्धता है।
- नए समझौते का उद्देश्य लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं, योग्यता आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं और तकनीकी मानकों से संबंधित उपायों के अनपेक्षित व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रभावों को कम करना है।
- इससे विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और महिला उद्यमियों को मदद मिलेगी।
- ये डिजिटल "मोस्ट फेवर्ड नेशन" सिद्धांत पर लागू किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि ये दायित्व WTO के सभी सदस्यों को लाभान्वित करेंगे।

कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नए सदस्य बने

- कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नए सदस्य बने हैं। अबू धाबी में WTO की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में इन देशों को औपचारिक सदस्यता प्रदान की गयी।
- इसके साथ ही WTO के सदस्यों की कुल संख्या 166 हो गयी है। कोमोरोस WTO के 165वें तथा तिमोर-लेस्ते 166वें सदस्य बने हैं।

प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा, सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बने

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21-22 मार्च 2024 को भूटान की राजकीय यात्रा पर रहे।
- भारत ने भूटान की सहायता को 2019-2024 में ₹ 5,000 करोड़ से दोगुना करके 2029 तक ₹10,000 करोड़ करने का निर्णय लिया है।
- भारत और भूटान ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, खेल, अंतरिक्ष और अनुसंधान में सहयोग पर सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- बानरहाट (पश्चिम बंगाल) और समत्से (भूटान) तथा कोकराझार (असम) और गेलेफू (भूटान) के बीच नई रेल कनेक्टिविटी स्थापित करने की भी घोषणा की गयी।
- थिम्पू में भारत सरकार की सहायता से अत्याधुनिक

अस्पताल ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मद्र एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने किया।

प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान

- प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो" (Order of the Druk Gyalpo) से सम्मानित किया गया।
- भारत भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। भारत ने भूटान के कुल विदेशी अनुदान में 73% का योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मार्च 2024 को सर्वसम्मति से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर पहला वैश्विक प्रस्ताव पारित किया।
- यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रायोजित और रूस, चीन और क्यूबा सहित 123 देशों द्वारा सहप्रायोजित किया गया।
- इसका उद्देश्य शक्तिशाली नई तकनीक से सभी देशों को लाभान्वित करना, मानवाधिकारों का संरक्षण तथा सुरक्षित और भरोसेमंद सुनिश्चित करना है।
- इस प्रस्ताव में विकसित और विकासशील देशों के बीच डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के महत्व पर जोर दिया गया।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

- यह कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है।
- जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है।
- भारत में राष्ट्रीय स्तर पर AI कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च

- भारत ने यह ऑपरेशन 21 मार्च 2024 को हैती से डोमिनिकन गणराज्य तक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया।
- हैती में सशस्त्र समूहों और सरकार के बीच गंभीर संघर्ष की स्थिति है।
- हैती कैरेबियन सागर में हिस्पानियोला द्वीप पर एक देश है। इसकी राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस है।

ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (GOF)

- भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स (Group of Friends: GOF) ने 26 मार्च 2024 को अपनी दूसरी बैठक आयोजित की गई।
- इस दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में प्रगति की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक नया डेटाबेस भी लॉन्च किया।
- GOF को भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान 2022 में लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य ब्लू हेलमेट (संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों) के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल GOF के सह-अध्यक्ष हैं। इसके 40 सदस्य हैं।

SSN-AUKUS पनडुब्बियों के निर्माण के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर किए

- यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया।
- ऑस्ट्रेलिया की ASC और यूके स्थित BAE सिस्टम्स नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के तहत रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के लिए SSN-AUKUS पनडुब्बियों का निर्माण करेंगी।
- ये पनडुब्बियां खुफिया जानकारी, निगरानी, युद्ध और स्ट्राइक मिशन के लिए सक्षम होंगी।
- यह AUKUS भागीदारों के बीच अधिकतम अंतरसंचालनीयता प्रदान करेगा।

SSN-AUKUS

- AUKUS इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है।
- यह सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगा और इंडो-पैसिफिक में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
- इसे एक मजबूत, अधिक लचीला त्रिपक्षीय पनडुब्बी औद्योगिक आधार बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो तीनों देशों में पनडुब्बी उत्पादन और रखरखाव का समर्थन करेगा।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (IGFA) को मंजूरी

- यह समझौता भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग पर है।

- इस अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (IGFA) पर 13 फरवरी 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे।
- IGFA का उद्देश्य बंदरगाहों, समुद्री और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाना और मजबूत करना है।
- IGFA में, IMEC के विकास हेतु भारत और यूएई के बीच सहयोग किया जाएगा।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC):

- यह भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस के माध्यम से यूरोप तक प्रस्तावित आर्थिक गलियारा है।
- इसमें दो अलग-अलग गलियारे, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा होंगे।
- पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारा खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा।
- 9 सितंबर 2023 को, भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं ने G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के मौके पर एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
- IBCA का मुख्यालय भारत में होगा।
- इसे 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये के सहयोग से स्थापित किया जाएगा।
- पीएम मोदी ने 9 अप्रैल, 2023 को औपचारिक रूप से भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के शुभारंभ की घोषणा की।
- इसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता सहित बिग कैट का भविष्य सुरक्षित करना है।
- बिग कैट्स में 7 कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता आते हैं।
- भारत में प्यूमा और जगुआर को छोड़कर अन्य सभी बिग कैट्स प्रजातियाँ हैं।
- नोट: वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था।
- यह गठबंधन प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करेगा और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को कम करेगा।

- IBCA ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण, नेटवर्किंग, वित्त और संसाधन सहायता, अनुसंधान और तकनीकी सहायता में मदद करेगा।
- ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया सहित 16 देश औपचारिक रूप से बिग कैट एलायंस में शामिल हो गए हैं।

एलायंस फॉर ग्लोबल गुड- जेंडर इक्विटी एंड इक्वैलिटी लॉन्च

- इसे भारत द्वारा दावोस 2024 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।
- हाल ही में इसका लोगो और वेबसाइट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है।
- एलायंस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को मजबूत करना, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमिता में निवेश आकर्षित करना है।

भारत ने मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ 29 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरीशस के अगालेगा द्वीप (Agalga Island) में छह सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ-साथ नई हवाई पट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
- ये परियोजनाएँ मॉरीशस के मुख्य क्षेत्र और अगालेगा द्वीप के बीच बेहतर संपर्क की आवश्यकता को पूरा करेंगी।
- अगालेगा पश्चिमी हिंद महासागर में है। मॉरीशस के अगालेगा में दो द्वीप शामिल हैं - मुख्य उत्तरी द्वीप, और छोटा दक्षिण द्वीप।
- अगालेगा से संचालित होकर, भारतीय नौसेना के लंबी दूरी के विमान पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर और अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी तट पर नजर रखने में सक्षम होंगे।

राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू की मॉरीशस यात्रा

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11-13 मार्च तक मॉरीशस की राजकीय यात्रा पर रहीं।
- वे 12 मार्च को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थीं।
- मॉरीशस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि (Honoris Causa Degree) से सम्मानित किया।

- राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के लिए प्रवासी भारतीय नागरिकता की पात्रता के विस्तार की घोषणा की, जिसका उद्देश्य युवा भारतीय मूल के लोगों को पुनःभारत से जोड़ना है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) स्टार्टअप फोरम

- इसके चौथे संस्करण का 19 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया।
- यह पहल SCO सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- SCO सदस्य देशों में स्थानीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत द्वारा स्टार्टअप गतिविधियों के संदर्भ में सदस्य देशों के साथ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है।
- **नोट:** 16 सितंबर 2022 को समरकंद (उज्बेकिस्तान) में SCO राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देश स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए एक विशेष कार्य समूह (SWG) बनाने पर सहमत हुए तथा भारत को इस समूह का स्थायी अध्यक्ष बनाया बनाया गया था।

थाईलैंड समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया देश बना

- थाईलैंड की संसद ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने के लिए एक विधेयक पारित किया है।
- यह विधेयक थाईलैंड के नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन करेगा और 'पति और पत्नी' जैसे लिंग संबंधी शब्दों को 'पति/पत्नी' और 'व्यक्ति' जैसी लिंग-तटस्थ भाषा से बदल देगा।
- **नोट:** ताइवान 2019 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश था।
- **नोट:** नवंबर 2023 में, नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बना।

दुनिया की पहली 3D-प्रिंटेड मस्जिद

- सऊदी अरब के में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया की पहली मस्जिद बनाई गई है।
- यह जेद्दा के अल-जवाहरा उपनगर में स्थित है।
- इस मस्जिद का नाम दिवंगत अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबतली के नाम पर रखा गया है।

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना

- इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार, यह क्षेत्र 2014 में 78% आयात-निर्भर से 97% आत्मनिर्भरता में बदल गया है।
- वर्तमान में, भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फोन में आयात का योगदान केवल 3% है।
- भारत का मोबाइल फोन विनिर्माण लगभग 20 लाख करोड़ रुपये का है।
- दस वर्षों (2014-2024) में, भारत ने 2.5 बिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 2.45 बिलियन मोबाइल फोन का उत्पादन किया।

नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया

- प्रधानमंत्री पुष्पा कमला दहल ने पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया।
- चीन ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था। इसे जनवरी 2022 में वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार किया गया था।

लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन

- इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के सियोल में 18-20 मार्च, 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप में किया गया।
- शिखर सम्मेलन का उद्घाटन दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन की उपस्थिति में किया।
- इस शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 मार्च, 2024 को वर्चुअल सम्बोधित किया।
- इस सम्मेलन की शुरुआत 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा सत्तावाद से लोकतंत्र के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने और मानवाधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
- **नोट:** लोकतंत्र के लिए पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका द्वारा 9-10 दिसम्बर, 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया।

5

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मिशन दिव्यास्त्र

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 11 मार्च को मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि -5 (Agni-5) मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया।
- इसके तहत अग्नि-5 मिसाइल कई वॉरहेड को ले जाने और कई ठिकानों पर निशाना लगाने में सक्षम है।
- इस परीक्षण को मिशन दिव्यास्त्र (Mission Divyastra) नाम दिया गया।
- यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया।
- MIRV क्षमता का विकास भारत की मिसाइल सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन है और इसके परमाणु विकल्पों का विस्तार करता है।
- पारंपरिक मिसाइलें एक ही वारहेड या हथियार ले जाती हैं, जो तय टारगेट पर जाकर हमला करती हैं।
- MIRV से युक्त मिसाइलें कई हथियार रख सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक अलग लक्ष्य पर हमला करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इन सभी को एक के बाद एक, एक ही स्थान पर हमला करने के लिए भी बनाया जा सकता है।
- यह तकनीक 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ द्वारा विकसित की गई। फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन के पास भी यह तकनीक है।

अग्नि-5 मिसाइल

- अग्नि-5 मिसाइल (रेंज: 5000 किमी) भारत की पहली और एकमात्र इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है।
- इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया।
- यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के तहत विकसित सतह-से-सतह पर मार करने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
- यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) टेक्नोलॉजी से लैस है। अर्थात् इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है।

- यह 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 (आवाज की स्पीड से 24 गुना अधिक) है।

पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV) 'पुष्पक' का सफल परीक्षण

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 22 मार्च 2024 को पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV: Reusable Launch Vehicle) की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया।
- इस पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (RLV) का नाम 'पुष्पक' रखा गया है।
- यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में चालाकरे एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में किया गया।
- पुष्पक इसरो की RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट की दूसरी सीरीज है और इस बार, RLV ने ऑटोनोमस लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया।
- इससे पहले 4 अप्रैल 2023 को इसरो ने Reusable Launch Vehicle-Technology Demonstration- RLV-TD) के साथ परीक्षण किया था।
- यह अंतरिक्ष में कम लागत में उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए पूरी तरह से री-यूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के प्रयासों का हिस्सा है।
- पुष्पक खास तरह का स्पेस शटल है। इसे जटिल युद्धाभ्यास करने, त्रुटियों को ठीक करने और पूरी तरह से स्वायत्त रूप से रनवे पर उतरने के लिए डिजाइन किया गया है।
- पुष्पक परियोजना की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये (लगभग 13.5 मिलियन डॉलर) है।
- पुष्पक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान (Reusable Launch Vehicle) के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है ताकि प्रक्षेपण लागत कम हो सके।
- इस परीक्षण में पुष्पक RLV को भारतीय वायु सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा उठाया गया और फिर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया।
- यह रनवे लैंड किया और ब्रेक पैराशूट, लैंडिंग गियर ब्रेक और नोज व्हील स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग करके रुक गया।

- रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का अगला चरण संभावित रूप से कक्षा में मौजूद उपग्रहों में ईंधन भरने या नवीनीकरण के लिए उपग्रहों को वापस लाने में सक्षम हो सकता है।



ISRO के सैटेलाइट PSLV ने शून्य कक्षीय मलबा मिशन पूरा किया

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के रॉकेट PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) ने 21 मार्च को शून्य कक्षीय मलबा मिशन (ISRO Achieves Zero Orbital Debris Mission) पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
- इसमें PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल-3 (POEM-3) ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश किया और मिशन को पूरा किया।
- किसी भी सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित करने के बाद पीएसएलवी तीन हिस्सों में बंट जाता है। इसे POEM-3 कहा जाता है।
- इससे इसरो नए मिशन के लिए जो भी रॉकेट लॉन्च करेगा, उसका मलबा अंतरिक्ष में नहीं बिखरेगा।
- इस परीक्षण में PSLV-C58/(X-ray Polarimeter Satellite- XPoSat) मिशन ने व्यावहारिक रूप से कक्षा में शून्य मलबा छोड़ा है।
- इस परीक्षण में PSLV को पहले 650 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा से 350 किलोमीटर वाली कक्षा में लाया गया।
- इस मिशन की सफलता से कक्षा (Orbit) बदलने के दौरान किसी भी सैटेलाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा कम हो जाएगा।
- PSLV-C58 मिशन 1 जनवरी 2024 को पूरा हुआ था।

भारत के निजी स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस का पहला रॉकेट लॉन्च

- तमिलनाडु की अंतरिक्ष स्टार्ट-अप अग्निकुल कॉसमॉस प्राइवेट लिमिटेड ने 22 मार्च को अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया।
- अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (SOrTeD) रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया।
- स्काईरूट के बाद अग्निकुल कॉसमॉस भारत की दूसरी निजी कंपनी है जिसने अपने लॉन्च वाहन को विकसित किया है।
- अग्निबाण तीन चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले चरण में सात इग्नाइट इंजन लगे हैं।
- अग्निबाण SOr TeD के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य:
 - यह किसी निजी लॉन्चपैड से भारत का पहला रॉकेट लॉन्च है।
 - यह भारत का पहला अर्द्ध-क्रायोजेनिक इंजन-संचालित रॉकेट प्रक्षेपण होगा।
 - यह दुनिया का पहला सिंगल-पीस 3D-प्रिंटेड इंजन है, जिसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।

अग्निकुल कॉसमॉस

- यह 2017 में स्थापित निजी अंतरिक्ष स्टार्ट-अप है जिसका मुख्यालय चेन्नई (तमिलनाडु) में है।
- दिसंबर 2020 में अग्निबाण इसरो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली देश की पहली कंपनी बनी थी। (अंतरिक्ष एजेंसी की विशेषज्ञता और इसकी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने हेतु)

- **नोट:** 2022 में, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट, विक्रम-S श्रीहरिकोटा में इसरो लॉन्चपैड से लॉन्च किया गया था।
- इसे हैदराबाद स्थित स्टार्ट-अप स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। इस मिशन को 'प्रारंभ' नाम दिया गया था।

चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट के नाम "स्टेटियो शिव शक्ति" (Statio Shiv Shakti) को IAU द्वारा मंजूरी मिली

- चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट के नाम "स्टेटियो शिव शक्ति" (Statio Shiv Shakti) को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) से मंजूरी मिली है।
- 'स्टेटियो शिव शक्ति' (Statio Shiv Shakti) चंद्रयान -3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट है।

चंद्रयान-3 मिशन

- इसरो का चंद्रयान-3 मिशन 14 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया गया।
- चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी।
- भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा (अमेरिका, रूस, चीन के बाद) और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना है।
- 26 अगस्त, 2023 पीएम मोदी ने चंद्रयान -3 के विक्रम लैंडर ने जिस स्थान को छुआ, उसे 'शिव शक्ति' के नाम की घोषणा की थी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान-2 के इम्पैक्ट पॉइंट को 'तिरंगा' नाम दिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में यहीं पर चंद्रयान-2 का लैंडर क्रैश हो गया था।
- 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर पहुंचा अतः इसे 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की गई।

शिव- शक्ति: मिल्की-वे आकाशगंगा के सबसे पुराने बिल्डिंग ब्लॉक्स

- जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के खगोलविदों ने गैया (Gaia) अंतरिक्ष दूरबीन का उपयोग करते हुए, आकाशगंगा के सबसे पुराने "बिल्डिंग ब्लॉक्स" की पहचान की है, जो 12-13 अरब वर्ष पुराने हैं।
- 'शक्ति' और 'शिव' नाम के ये तारकीय समूह, आकाशगंगा के निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

- ये प्राचीन तारकीय समूह संभवतः एक साथ आकर मिल्की-वे आकाशगंगा की बुनियाद है।
- 'शक्ति' और 'शिव' के सितारों में आकाशगंगा के केंद्र की तुलना में अधिक कोणीय गति है।
- यह खोज आकाशगंगा के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालती है।

आईएनएस जटायु (INS Jatayu)

- यह लक्षद्वीप में भारत का अत्याधुनिक नौसैनिक अड्डा है।
- आईएनएस जटायु को 6 मार्च 2024 को शुरू किया गया।
- भारत के पास 1980 के दशक से लक्षद्वीप द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी एटोल मिनिकाय में एक नौसैनिक टुकड़ी है।
- INS जटायु लक्षद्वीप में देश का दूसरा नौसैनिक अड्डा है।
- द्वीपों पर नौसेना का पहला बेस, कावारत्ती में INS द्वीपरक्षक, 2012 में शुरू किया गया था।
- यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के भारतीय नौसेना के संकल्प में एक महत्वपूर्ण है।
- INS जटायु के चालू होने से भारतीय नौसेना पश्चिमी समुद्री तट पर अपनी ताकत बढ़ाएगी।

मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए उपग्रह लॉन्च

- वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु **मीथेनसैट (MethaneSAT)** नामक उपग्रह को 4 मार्च 2024 को कैलिफोर्निया (USA) से SpaceX फाल्कन-9 रॉकेट से लॉन्च किया गया।
- इसे अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी पर्यावरण संगठन "एनवायरनमेंट डिफेंस फंड कोष (EDF) द्वारा लॉन्च किया गया है।
- उपग्रह विकसित करने के लिए, EDF ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी और न्यूजीलैंड अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है।
- मीथेनसैट का उद्देश्य तेल और गैस क्षेत्रों से लीक हुई मीथेन पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ मीथेन निगरानी का एक स्वतंत्र स्रोत प्रदान करके मदद करना है।
- यह बड़ी मात्रा में डेटा संग्रह करेगा और मीथेन के उत्सर्जन, जिम्मेदारों और मात्रा का विश्लेषण करेगा।

मीथेन

- मीथेन विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैस है, जो पृथ्वी पर अब तक हुई लगभग 30% वार्मिंग का कारण बनती है।
- यह वायुमंडल में केवल 12 वर्षों में विघटित हो जाती है, जो कि CO2 से विघटित होने वाले सैकड़ों वर्षों की तुलना में बहुत कम है।

भारतीय नौसेना ने अपने पहले MH60R स्क्वाड्रन

- भारतीय नौसेना ने 6 मार्च, 2024 को बहुउद्देशीय MH60R Seahawk मल्टी-रोल हेलिकॉप्टरों को अपने बेड़े में शामिल किया।
- भारतीय नौसेना ने इस स्क्वाड्रन को 'भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 334' (INAS 334) नाम दिया है।
- इसका नेतृत्व कैप्टन एम अभिषेक राम द्वारा किया जाएगा।

MH60R Seahawk हेलिकॉप्टर

- इसे 'रोमियो' के नाम से भी जाना जाता है।
- यह अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित है।
- MH60R Seahawk ब्लैकहॉक हेलिकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है।
- यह पनडुब्बीरोधी युद्ध, सतहरोधी युद्ध, खोज, बचाव तथा चिकित्सा अभियान सहित अन्य अभियानों हेतु उपयुक्त है।

INS अग्रे और INS अक्षय भारतीय नौसेना में शामिल

- भारतीय नौसेना में दो नए जहाज **INS अग्रे और INS अक्षय** 13 मार्च, 2024 को शामिल किए गए।
- इन्हें गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा निर्मित किया गया है।
- ये 8x एएसडब्ल्यू शैलो वॉटर क्राफ्ट (8x ASW Shallow Water Craft- SWC) GRSE परियोजना के 5वें और 6वें जहाज हैं।
- इन जहाजों को पनडुब्बी रोधी युद्ध, कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन और तटीय जल में सुरंग बिछाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ये जहाज 77.6 मीटर लम्बे और 105 मीटर चौड़े हैं।
- ये 900 टन विस्थापन क्षमता के जहाज हैं।

ड्रैगनफायर का सफल परीक्षण

- ब्रिटेन ने 19 मार्च, 2024 को हाई पॉवर लेजर हथियार ड्रैगनफायर (Dragon Fire) का सफल परीक्षण किया है।

- यह एक एंटी-ड्रोन लेजर तकनीक है।
- इस हथियार का पूरा नाम 'ड्रैगनफायर लेजर डाइरेक्टेड एनर्जी वेपन' (Laser Directed-Energy Weapon- LDEW) है।
- यह ड्रोन जैसे एरियल टारगेट को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है।
- इसे ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने MBDA, Leonardo और QinetiQ कंपनियों के संयुक्त प्रयास से तैयार किया है।
- लेजर बीम से एक किलोमीटर दूर रखे छोटे लक्ष्य को भी टारगेट कर सकता है।
- नोट:** अमेरिका, जर्मनी, इजराइल और तुर्की भी ब्रिटेन की तरह लेजर आधारित हथियार विकसित कर चुके हैं।

बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) का सफल उड़ान परीक्षण

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा 28 और 29 फरवरी को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली (VSHORADS) मिसाइल के दो सफल उड़ान परीक्षण किए गए।
- ये परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर में ओडिशा के तट से दूर एक ग्राउंड-आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से किए गए।
- इन्हें विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानवरहित हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से पूरा किया गया।

VSHORADS

- यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPAD) है।
- इसे अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद ने अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित और डिजाइन किया है।
- VSHORADS मिसाइल एक दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर द्वारा संचालित होती है, जिसे कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।

सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड अडॉप्शन ग्रुप (STEAG)

- भारतीय सेना ने 21 सिग्नल समूह को सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड अडॉप्शन ग्रुप (STEAG) में परिवर्तित कर दिया है।

STEAG

- यह सैन्य अनुप्रयोगों के लिए 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की संचार प्रौद्योगिकियों पर शोध और मूल्यांकन के लिए समर्पित इकाई है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सेना के संचार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है।
- यह समूह सिग्नल निदेशालय के तहत काम करेगा।

LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान का पहला सफल परीक्षण

- भारत में निर्मित स्वदेशी तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान (Mark 1A fighter aircraft) ने 28 मार्च को अपनी सफलतापूर्ण पहली उड़ान भरी।

LCA तेजस

- LCA (Light Combat Aircraft) तेजस एकल इंजन वाला, बहुउद्देश्यीय हल्का लड़ाकू विमान है। इसकी स्पीड 2200 किमी प्रति घंटे है।
- यह अधिकतम 50 हजार फीट की ऊँचाई तक जा सकता है। इसको 9 रॉकेट, बम और मिसाइल से लैस किया जा सकता है।
- इसे एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है।
- तेजस को हवा-से-हवा, हवा-से-सतह, सटीक-निर्देशित और स्टैंडऑफ हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 3,500 किलोग्राम है।

तेजस मार्क 1A

- तेजस मार्क 1A, मार्क 1 का उन्नत संस्करण है। यह 4th जेनेरेशन का फाइटर एयरक्रॉफ्ट है।
- इसमें हवा में फ्यूल भरा जा सकता है।
- यह रडार और आत्म-सुरक्षा जैमर से सुसज्जित है।
- भारतीय वायु सेना ने अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए 83 तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर दिया है।

भारत का सबसे तेज राउटर लॉन्च

- भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया IP/MPLS (Multiprotocol Label Switching) राउटर 9 मार्च 2024 को बंगलुरु में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किया गया।

- इस राउटर को सरकार के दूरसंचार विभाग, CDOT और निवेट्टी (Nivetti) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इसकी स्पीड 2.4 टेराबाइट्स प्रति सेकंड (tdps) है।
- यह रेलवे संचार नेटवर्क, पावर ग्रिड, दूरसंचार और टेलीविजन मीडिया सहित कई क्षेत्रों के विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है।

MPLS तकनीक

- मल्टीप्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (MPLS) दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग की जाने वाली एक रूटिंग तकनीक है जो डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक निर्देशित करती है।
- MPLS तकनीक पहली बार 1990 के दशक में विकसित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व निर्धारित नेटवर्क पथों पर पैकेट भेजकर नेटवर्क कनेक्शन को गति देना है।

डेफकनेक्ट 2024 (Def Connect 2024)

- स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए डेफकनेक्ट 2024 का 4 मार्च 2024 को उद्घाटन किया गया।
- यह सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग के नेताओं, स्टार्ट-अप, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है।
- इसका उद्देश्य सार्थक जुड़ाव को बढ़ावा देना और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना है।
- यह भारत के प्रमुख रक्षा क्षेत्र उद्योगों के नवप्रवर्तकों और निवेशकों को आकर्षित करेगा।
- इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार- रक्षा नवाचार संगठन (iDEX-DIO) द्वारा किया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा 2018 में iDEX लॉन्च किया था। यह रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

कुलसेकरपट्टिनम प्रक्षेपण केंद्र

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी, 2024 को तमिलनाडु में कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट (Kulasekarapattinam spaceport) की आधारशिला रखी गई।
- यह SSLVs (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान) लॉन्च करने के लिए श्री हरिकोटा (आंध्र प्रदेश) के बाद इसरो का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है।

महत्व

- जब आंध्र प्रदेश में इसरो के श्रीहरिकोटा से किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, तो

रॉकेट पहले पूर्व दिशा की ओर जाता है, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। चूंकि श्रीलंका श्रीहरिकोटा के दक्षिण में स्थित है, इसलिए पड़ोसी देश के हवाई क्षेत्र से बचने के लिए यह मार्ग परिवर्तन किया गया है।

- कुलसेकरपट्टिनम के अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इस मोड़ की आवश्यकता नहीं है और रॉकेट अब सीधे दक्षिणी दिशा में जा सकते हैं।

लाभ

- रॉकेट को अधिक दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी।
- ईंधन की बचत होगी।
- कुलसेकरपट्टिनम श्रीहरिकोटा की तुलना में भूमध्य रेखा के अधिक निकट है।

SSLV (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान)

- इसरो ने कम लागत पर हल्के वजन वाले उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए SSLV (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान) डिजाइन किया है।
- इन SSLV का उपयोग 500 किलोग्राम से कम वजन वाले उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) में 'कोर लोडिंग' की शुरुआत

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 मार्च 2024 को तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Prototype Fast Breeder Reactor: PFBR) में 'कोर लोडिंग' की शुरुआत की।
- यह 500 मेगावाट क्षमता का रिएक्टर है।
- यह भारत के तीन चरणों वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम के दूसरे चरण में प्रवेश से संबंधित है।
- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) ऊर्जा का एक सुरक्षित, दक्ष और स्वच्छ स्रोत प्रदान करेगा और नेट जीरो के लक्ष्य में योगदान देगा।
- PFBR को भाविनी (BHAVINI) द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है।
 - भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम है।
- इसके पूर्ण रूप से संचालन के बाद भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेट करने वाला दूसरा देश होगा।

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)

- भारत का तीन चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है।
- प्रथम चरण में, भारत में विखंडनीय सामग्री (fissile material) के रूप में प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों (PHWRs) और प्राकृतिक यूरेनियम-238(U-238) का उपयोग किया जाता है।
- PHWR विखंडनीय सामग्री के रूप में प्राकृतिक या कम एनरिचड U-238 का उपयोग करते हैं और बायप्रोडक्ट के रूप में Pu-239 का उत्पादन करते हैं।
- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दूसरे चरण का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है।
- ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है।
- FBR कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह जितना न्युक्लियर फ्यूल का खपत करती है, उससे अधिक न्युक्लियर फ्यूल का उत्पादन करती है।
- यह एक एडवांस तीसरी पीढ़ी का रिएक्टर है जिसमें इन्हेरेंट सेफ्टी फीचर हैं जो आपात स्थिति की स्थिति में रिएक्टर को तुरंत और सुरक्षित रूप से बंद करना सुनिश्चित करती हैं।

नोक्टिस ज्वालामुखी (Noctis volcano)

- यह हाल ही में मंगल ग्रह पर मिला सबसे बड़ा ज्वालामुखी है।
- इसकी ऊंचाई 29,600 फीट है और चौड़ाई 450 किलोमीटर है।
- यह पूर्वी नोक्टिस लेबिरिथस क्षेत्र के भीतर मंगल के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है।
- नासा के मेरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 और 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर और अन्य सहित कई मिशनों के डेटा का उपयोग करते हुए यह उपलब्धि हासिल हुई।

भारत शक्ति (Bharat Shakti) अभ्यास 2024

- यह राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में त्रि-सेवा (तीनों सेनाओं) का अभ्यास है।
- इसकी थीम 'स्वदेशीकरण से सशक्तीकरण' थी।
- इसके तहत स्वदेशी हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई।

समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण

- यह भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेनाओं के बीच हुआ।
- यह 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया।
- इस अभ्यास के तीसरे संस्करण में भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर ने भाग लिया।
- अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना और आपसी समझ को बढ़ाना है।

कटलैस एक्सप्रेस -24 (CE - 24) अभ्यास

- यह एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना ने 16 मित्र देशों के साथ भाग लिया।
- यह 26 फरवरी से 08 मार्च 24 तक पोर्ट विक्टोरिया, सेशेल्स में आयोजित किया गया।

लमितिये-2024"(LAMITIYE-2024)

- यह भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- यह 18-27 मार्च 2024 तक सेशेल्स में आयोजित किया गया।
- क्रियोल भाषा में 'लमितिये' का अर्थ है 'मित्रता'।

टाइगर ट्राइफ-24 अभ्यास

- यह भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रि-सेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत (HDR) अभ्यास है।
- 18 से 31 मार्च 2024 तक अमेरिका में पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित किया गया।

6

खेल

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता।

- इस टूर्नामेंट का आयोजन पेरिस (फ्रांस) में किया गया।
- भारतीय जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने अपना दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता।
- भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के ली ज़े हुई और यांग पो ह्वान को सीधे गेम में हराकर पुरुष युगल का खिताब जीता।
- सात्विक और चिराग ने इससे पहले 2022 में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में युगल खिताब खिताब जीता था, जबकि 2019 में फ्रेंच ओपन में उपविजेता रही थी।

चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) 2023

- इसके चौथे संस्करण का आयोजन 17 से 29 फरवरी 2024 तक पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में किया गया।
- चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खिताब जीता।
- खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, 2024 की पदक तालिका :-
 1. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी-32 स्वर्ण, 18 रजत और 21 कांस्य सहित कुल 71 पदक।
 2. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी-20 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य।
 3. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी-12 स्वर्ण, 20 रजत और 19 कांस्य।

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG)

- KIUG विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-खेल प्रतियोगिता है।
- यह भारत सरकार द्वारा युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत आयोजित की जाती है।
- इन खेलों को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था।
- यह गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है।

कीर्ति (KIRTI) कार्यक्रम लॉन्च

- पूरा नाम: Khelo India Rising Talent

Identification (KIRTI) Programme.

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में कीर्ति नामक एक अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम लॉन्च किया।
- यह खेलो इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच के प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है, जो वर्तमान में देश भर के स्कूलों में नामांकित हैं।

मुंबई ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता

- मुंबई ने 14 मार्च को विदर्भ को 169 रनों से हराकर रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता।
- यह मुंबई का 42वाँ खिताब है।
- इससे पहले मुंबई ने वर्ष 2015-16 में खिताब जीता था।
- मुशीर खान को फाइनल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया और तनुश कोटियन को टूर्नामेंट के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।
- नोट: 2023 में सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था।

रणजी ट्रॉफी:

- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) प्रतिवर्ष रणजी ट्रॉफी का आयोजन करता है।
- यह देश के राज्य और क्षेत्रीय क्रिकेट संघों के बीच एक घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है।
- इस टूर्नामेंट का नाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले क्रिकेटर रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है।
- मुंबई ने इस ट्रॉफी का पहला संस्करण और सबसे अधिक रणजी ट्रॉफियां भी जीते हैं।

WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट 2024

- WTT (World Table Tennis) फीडर बेरूत टूर्नामेंट लेबनान में आयोजित किया गया।
- इस टूर्नामेंट में भारत के साथियान ज्ञानसेकरन ने पुरुष एकल का खिताब जीता।
- साथियान ने फाइनल में भारत के ही मानव विकास ठक्कर को हराया।

- इस टूर्नामेंट में साथियान और मानुष उत्पल शाह पुरुष युगल में उपविजेता रहे।
- मिश्रित युगल फाइनल में, दीया चितले और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी विजेता रही।

WTT फीडर बेरूत II टूर्नामेंट 2024

- यह लेबनान में आयोजित किया गया।
- इसमें टेबल टेनिस में महिला एकल का खिताब श्रीजा अकुला ने जीता।
- यह अकुला का दूसरा WTT एकल खिताब है।
- इस टूर्नामेंट में पुरुष युगल का खिताब मानुष शाह और मानव ठक्कर ने जीता।
- इसमें मिश्रित युगल का खिताब पोयमंती बैस्या और आकाश पाल ने जीता।

पेरिस 2024 ओलंपिक में शरथ कमल भारत के ध्वजवाहक होंगे

- भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी शरथ कमल आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे।
- इसके अलावा, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एमसी मैरीकॉम को ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए शेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है।
- शरथ कमल ने रिकॉर्ड 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है।
- एमसी मैरीकॉम 6 विश्व खिताब जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज हैं।
- गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक के लिए शूटिंग ग्राम संचालन का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
- नारंग 2012 लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता हैं।
- नोट: पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होगा।

19वीं विश्व इनडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024

- इसका आयोजन 1-3 मार्च, 2024 को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में अन्तर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (IAAF) द्वारा किया गया।
- इसमें कुल 26 स्पर्धाएँ शामिल थीं।
- इस चैंपियनशिप में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर (6 स्वर्ण, 9 रजत व 5 कांस्य सहित कुल 20 पदक) रहा, जबकि बेल्जियम दूसरे स्थान पर रहा।
- भारत के दो एथलीट ट्रिपल जम्पर प्रवीण चित्रवेल और लॉना जम्पर जेसविन एल्ड्रिन ने इस मीट में भाग लिया।

- अमेरिका के क्रिश्चियन कोलमैन व सेंट लूसिया की जूलियन अल्फ्रेड क्रमशः पुरुष व महिला वर्ग में सबसे तेज धावक रहे।
- कोलमैन ने 60 मी. दौड़ 6.41 सैकेण्ड में तथा जूलियन ने 6.98 सैकेण्ड में पूरी की।
- कोलमैन का इंडौर चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण और कुल तीसरा पदक है।

BNP परिबास ओपन (इंडियन वेल्स मास्टर्स) 2024

- इसका आयोजन 6-17 मार्च, 2024 को इंडियन वेल्स, कैलिफोर्निया (USA) में किया गया।
- इसे इंडियन वेल्स (मास्टर्स) टूर्नामेंट नाम से भी जाना जाता है।
- इस टूर्नामेंट के पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः कार्लोस अल्कारेज और इगा स्वातेक ने जीते।

ATP Tour Masters 1000 (Men)

- स्पेन के अल्कारेज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर पुरुषों का एकल खिताब जीता।
- अल्कारेज का विंबलडन के बाद यह पहला खिताब है।

WTA 1000 (Women)

- महिला वर्ग के एकल खिताब में पोलैण्ड की इगा स्वातेक ने ग्रीस की मारिया सेक्कारी को हराया।
- स्वातेक ने वर्ष 2022 में यह खिताब जीता था।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पहला महिला प्रीमियर लीग खिताब जीता

- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 17 मार्च को, दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग 2024 जीता।
- सोफी मोलिनक्स को फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

पुरस्कार श्रेणी

विजेता

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड	श्रेयंका पाटिल (RCB)
मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर	दीप्ति शर्मा (UPW)
ऑरेंज कैप	एलिसा पेरी (RCB)
पर्पल कैप	श्रेयंका पाटिल (RCB)
फेयर प्ले अवार्ड	रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर

- नोट: 2023 में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहली महिला प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीती थी।

महिला प्रीमियर लीग (WPL):

- यह एक महिला ट्वेंटी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट है।
- इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा कराया जाता है।
- अब तक इसके 2 संस्करण आयोजित हो चुके हैं।

पुणेरी पलटन ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब जीता

- पुणेरी पलटन ने 1 मार्च को हरियाणा स्टीलर्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब जीता।
- यह पुणे की टीम का पहला खिताब है।
- मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर : असलम इनामदार (पुणेरी पलटन के कप्तान)
- सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर: मोहम्मद रेजा चियानेह (पुणेरी पलटन के उप-कप्तान)
- सर्वश्रेष्ठ रेडर: आशु मलिक (दबंग दिल्ली)

बी साई प्रणीत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया

- बी साई प्रणीत भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।

उपलब्धियाँ

- विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक (2019)
- टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व
- सिंगापुर ओपन का खिताब (2017)
- वर्ष 2019 में, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- **नोट:** 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद, वह 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक अर्जित करने वाले दूसरे पुरुष भारतीय शटलर बने।

पंकज आडवाणी 'बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम' में शामिल

- भारत के महान क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी चीन के शांगराओ सिटी में 'वर्ल्ड बिलियर्ड्स संग्रहालय' में 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल किया गया है।
- नवंबर 2023 में आडवाणी ने भारत के ही सौरव कोठारी को हराकर 26वाँ अन्तर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर महासंघ (IBSF) खिताब जीता था।
- पंकज आडवाणी कुल 26 वर्ल्ड टाइटल जीत चुके हैं, जिसमें 18 बिलियर्ड्स और 8 स्नूकर के वर्ल्ड टाइटल शामिल हैं।
- भारत सरकार ने पंकज आडवाणी को पद्म भूषण (2018) पद्म श्री (2009), मेजर ध्यानचंद खेल रत्न (2006) और अर्जुन पुरस्कार (2004) से सम्मानित किया है।

खेलो इंडिया के एथलीट सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और खेल मंत्रालय के द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले एथलीटों के लिए पात्रता मानदंड में संशोधन किए गए।
- इसके तहत खेलो इंडिया गेम्स के यूथ, यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स के पदक विजेताओं को सरकारी नौकरियों के लिए पात्र बनाया गया है।
- इसके अलावा विभिन्न खेलों में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए खेलों और आयोजनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में उपलब्धि हासिल करने वालों की भी इन पदों के लिए पात्रता बनी रहेगी।
- जिन लोगों ने जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की है या अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने देश या राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, वे रोजगार के लिए योग्य होंगे।

7

पुरस्कार एवं सम्मान

प्रभा वर्मा को 2023 का सरस्वती सम्मान साहित्यिक सम्मान

- के के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास 'रौद्र सात्विकम' के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया।
- 'रौद्र सात्विकम' मलयालम भाषा में काव्यात्मक छंद में लिखित है।
- यह उपन्यास सत्ता और राजनीति, व्यक्ति और राज्य, तथा कला और सत्ता के बीच के संघर्ष के बारे में बताता है।
- सरस्वती सम्मान पुरस्कार विजेता का चयन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अर्जुन कुमार सीकरी की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया गया।

प्रभा वर्मा

- प्रभा वर्मा तिरुवल्लुर, केरल से हैं।
- यह अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषा में अपनी रचनाएँ लिखते हैं।
- प्रमुख कृतियाँ: सौपर्णिका, अर्कपूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी, आर्द्रम, और कनाल चिलम्बु हैं।
- वर्मा को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र सरकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार और वायलार पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
- प्रभा वर्मा वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मीडिया सलाहकार हैं।

सरस्वती सम्मान

- इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी।
- ये के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है।
- यह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक में गद्य या कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है।
- इसमें एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और ₹15 लाख का नकद पुरस्कार शामिल है। यह पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित कृतियों के लिए दिया जाता है।
- पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को 1991 में मिला था।
- 32वाँ सरस्वती सम्मान शिवशंकरि को तमिल भाषा में रचित उनकी कृति 'सूर्या वामसम' के लिए दिया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत रत्न अलंकरण प्रदान किए

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 शिखसयतों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न (Bharat Ratna) से सम्मानित किया।
- यह सम्मान 30 मार्च 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और श्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत दिया गया।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 मार्च को पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण प्रदान किया गया।

भारत रत्न (Bharat Ratna)

- यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है।
- इस सम्मान की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गई थी।
- भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को पीपल के पत्ते के आकार का पदक और भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाणपत्र) प्रदान किया जाता है।
- भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को कोई राशि नहीं मिलती, लेकिन कैबिनेट मंत्री के समकक्ष अति विशिष्ट दर्जा मिलता है।
- सबसे पहला भारत रत्न सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था।
- सचिन तेन्दुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन को भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं।

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से 24 लेखकों सम्मानित किया गया

- वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार 12 मार्च, 2024 को प्रदान किए गए।
- यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22

भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के लिए दिए गए।

- इस पुरस्कारों में 9 कविता-संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी-संग्रह, 3 निबंध तथा 1 साहित्यिक अध्ययन (आलोचना) शामिल हैं।

प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता:

- हिंदी: **संजीव** को “मुझे पहचानो” उपन्यास हेतु
- अंग्रेजी: **नीलम शरण गौड़** को “रेक्युम इन राग जानकी” उपन्यास (**Requiem in Raag Janaki**) हेतु
- पंजाबी: स्वर्णजीत सवी को ‘मन दी चिप’ कविता-संग्रह हेतु
- उर्दू:सादिका नवाब सहर को “राजदेव की अमराई” उपन्यास हेतु

अन्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता:

- कविता: विजय वर्मा (डोगरी), विनोद जोशी (गुजराती), मंशूर बनिहाली (कश्मीरी), सोरोखबैबम गर्भिनी (मणिपुरी), आशुतोष परिडा (ओड़िया), गजेसिंह राजपुरोहित (राजस्थानी), अरुण रंजन मिश्र (संस्कृत), विनोद आसुदानी (सिंधी)।
- उपन्यास: स्वपनमय चक्रवर्ती (बांग्ला), कृष्णात खोत (मराठी), राजशेखरन (तमिल)।
- कहानी-संग्रह: प्रणवज्योति डेका (असमिया), नंदेश्वर दैमारि (बोडो), प्रकाश एस. पर्येकार (कोंकणी), तारासीन बासकी (संथाली), टी. पतंजलि शास्त्री (तेलुगु)।
- निबंध: लक्ष्मीशा तोल्पडि (कन्नड़), बासुकीनाथ झा (मैथिली), युद्धवीर राणा (नेपाली)।
- साहित्यिक अध्ययन (आलोचना): ई.वी. रामकृष्णन (मलयालम)।

साहित्य अकादमी पुरस्कार:

- यह पुरस्कार साहित्य और भाषा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है।
- यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी सहित **कुल 24 भाषाओं के लिए** दिया जाता है।
- इसकी स्थापना 1954 में की गई थी।
- इसमें पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है।
- इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देना और उसको संरक्षित रखना है।
- साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।

96वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2024

- 96वें ऑस्कर पुरस्कार (96th Academy Awards) 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च 2024 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजेलिस में की गई।
- इस पुरस्कार समारोह में 2023 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया।
- इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अमेरिकी फिल्म **ओपेनहाइमर (Oppenheimer)** को दिया गया।
- यह फिल्म भौतिक वैज्ञानिक और परमाणु बम के आविष्कारक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीवनी पर आधारित है।
- ओपेनहाइमर ने सर्वाधिक 7 पुरस्कार जीते।
- इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (किलियन मर्फी), सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता (रॉबर्ट डाउनी जूनियर), सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार भी जीता।

96वें ऑस्कर अकादमी के मुख्य पुरस्कार

- सर्वश्रेष्ठ फिल्म: ओपेनहाइमर
- सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर: क्रिस्टोफर नोलन (फिल्म ओपेनहाइमर के लिए)
- सर्वश्रेष्ठ एक्टर: सिलियन मर्फी (फिल्म ओपेनहाइमर के लिए)
- सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस: एम्मा स्टोन (फिल्म पुअर थिंग्स के लिए)
- सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर: 20 डेज इन मारियुपोल

ऑस्कर अकादमी पुरस्कार

- ऑस्कर अकादमी पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है।
- ये मनोरंजन क्षेत्र का सबसे बड़ा और सम्मानित पुरस्कार है।
- ये पुरस्कार अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस (AMPAS) द्वारा प्रदान किया जाता है।
- ऑस्कर पुरस्कार विजेताओं को ‘गोल्डन स्टैचू’ प्रदान की जाती है। इस गोल्डन स्टैचू को आधिकारिक तौर पर ‘एकेडमी ऑफ मेरिट’ कहा जाता है।

भारत द्वारा जीते गए ऑस्कर पुरस्कार

- भानु अथैया (1982)
- सत्यजीत रे (1992)
- रेसुल पुकुट्टी (2009)
- गुलजार (2009)
- ए आर रहमान (2009)
- कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा, द एलीफेंट व्हिस्परर्स (2023)
- आरआरआर फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग (2023)

प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार (Pritzker Architecture Prize) 2024

- 2024 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार **जापानी वास्तुकार रिक्केन यामामोटो को** दिया जाएगा।
- यामामोटो नवीन आवास परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाने जाते हैं।
- यह वास्तुकला क्षेत्र में सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जिसे 'आर्किटेक्चर नोबेल' भी कहा जाता है।
- 2023 में, डेविड चिपरफील्ड ने प्रित्जकर पुरस्कार जीता था।
- यह पुरस्कार 1979 में इसकी स्थापना के बाद से हर साल प्रदान किया जाता है।
- रिक्केन यामामोटो जापान से नौवें पुरस्कार विजेता हैं।
- 1979 में, अमेरिकी वास्तुकार फिलिप जॉनसन ने पहला प्रित्जकर पुरस्कार जीता था।
- जापान के आर्किटेक्चर्स ने सबसे अधिक संख्या में प्रित्जकर पुरस्कार जीते हैं।

प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार

- प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार की स्थापना 1979 में हयात होटल चैन के दिवंगत संस्थापक जे ए प्रित्जकर और उनकी पत्नी सिंडी द्वारा की गई थी।
- यह पुरस्कार प्रित्जकर परिवार द्वारा वित्त पोषित और हयात फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है।
- पुरस्कार के साथ \$100,000 की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक कांस्य पदक दिया जाता है।
- यह पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय दिवंगत बालकृष्ण दोशी (2018) हैं।

क्रिस्टीना पिस्जकोवा मिस वर्ल्ड 2023 बनी

- मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता **मुंबई (महाराष्ट्र)** में आयोजित हुई।
- चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्जकोवा 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है।
- वह मिस वर्ल्ड जीतने वाली चेक गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली दूसरी महिला हैं।

- यास्मीना जायतौन (लेबनान) को फर्स्ट रनर-अप रहीं।
- **नोट:** मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब करोलिना बिलावस्का (पोलैंड) ने जीता था।

भारत का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया गया।
- केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के टैलेंट का सम्मान करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरु किया गया है।
- इसका उद्देश्य देश की सोशल मीडिया कंटेंट कम्युनिटी में इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में उठाए गए कदमों को सम्मानित करना है।
- इसमें 3 इंटरनेशनल क्रिएटर्स सहित कुल 23 विजेताओं को सम्मानित किया गया।

टाइगर वुड्स ने बॉब जोन्स पुरस्कार जीता

- टाइगर वुड्स ने पीजीए टूर पर अपने करियर की 82 जीतों में से 15 बड़ी जीत हासिल की हैं।
- बॉब जोन्स पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्फ एसोसिएशन (USGA) का सर्वोच्च सम्मान है।
- 2022 में, उन्हें वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
- 2019 में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिला।

भारत 'खसरा और रूबेला चैंपियन' पुरस्कार से सम्मानित

- भारत को 6 मार्च को, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में रेड क्रॉस मुख्यालय में प्रतिष्ठित 'खसरा और रूबेला चैंपियन' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- भारत को यह पुरस्कार खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए दिया गया।
- भारत में पिछले 12 महीनों में 50 जिलों में लगातार खसरे का कोई मामला नहीं है, जबकि 226 जिलों में रूबेला का कोई मामला नहीं है।

खसरा और रूबेला

- खसरा और रूबेला टीकाकरण-रोकथाम योग्य बीमारियाँ (VPD) हैं।
- खसरा और रूबेला (MR) वैक्सिन 2017 से देश के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है।
- खसरा और रूबेला के लिए संयुक्त टीका दुनिया के कुछ क्षेत्रों में बच्चों के टीकाकरण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

रूबेला

- रूबेला वायरस से होने वाला एक प्रकार का संक्रमण है।
- यह शिशुओं और बच्चों में हल्के बुखार और दाने का कारण बनता है।
- जिन गर्भवती महिलाओं को रूबेला होता है उनमें जन्म दोष वाले विकृत बच्चे पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है।

खसरा (Measles)

- खसरा (Measles) एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है।
- सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की उपलब्धता के बावजूद, यह विश्व स्तर पर छोटे बच्चों की मृत्यु का एक महत्वपूर्ण कारण है।

सुनील भारती मित्तल को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड सम्मान

- सुनील भारती मित्तल यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं।
- भारत और यूके के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध विकसित करने में उनकी उपलब्धियों को इस पुरस्कार से मान्यता मिली है।
- मानद नाइटहुड ब्रिटिश संप्रभु द्वारा नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है।
- विदेशी नागरिक इसे अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सराहना के प्रतीक के रूप में प्राप्त करते हैं।
- सुनील भारती मित्तल भारतीय एंटरप्राइजेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं।

5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024

- राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 6 मार्च को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
- राष्ट्रीय युवा संसद 2024 का आयोजन 'यंग वॉयस: एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन' की थीम पर किया गया था।
- इसका आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के माध्यम से किया गया।
- इसमें हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने पहला पुरस्कार जीता।
- तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई ने दूसरा पुरस्कार और राजस्थान की कनिष्का शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता।
- पहला राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव (NYPF)-12 जनवरी से 27 फरवरी 2019 तक आयोजित किया गया था।

अमिताव घोष को इरास्मस पुरस्कार 2024

- लेखक अमिताव घोष (Amitav Ghosh) को प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार 2024 (Erasmus Prize 2024) से सम्मानित किया गया है।
- उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने के लिए 'अकल्पनीय की कल्पना' थीम पर योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है।
- अमिताव घोष कोलकाता में जन्मे प्रख्यात लेखक हैं।
- यह पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म निर्माता इंगमार बर्गमैन और चार्ल्स चैपलिन को भी दिया गया।
- अमिताव घोष की कृतियों में 'द शैडो लाइन्स', 'द हंग्री टाइड' और 'द इबिस ट्रिलॉजी' जैसे उपन्यास शामिल हैं।
- अमिताव घोष को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

इरास्मस पुरस्कार

- इरास्मस पुरस्कार नीदरलैंड के इरास्मियानम फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
- इरास्मस पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थानों के लिए एक विशिष्ट पुरस्कार है, जिन्होंने यूरोप और उसके बाहर संस्कृति या विद्वता में असाधारण योगदान दिया है।
- पुरस्कार के रूप में 1,50,000 यूरो की राशि और अलंकरण शामिल हैं।
- इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी तथा यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

मिशेल टैलग्रांड ने जीता 2024 का एबेल पुरस्कार

- मिशेल टैलग्रांड (Michel Talagrand) ने 2024 का एबेल पुरस्कार (Abel prize) जीता है।
- उन्हें यह पुरस्कार संभाव्यता सिद्धांत (probability theory) और रैंडमनेस का वर्णन करने पर अपने शोध के लिए प्रदान किया गया।
- एबेल पुरस्कार को 'गणित का नोबेल पुरस्कार' भी कहा जाता है।
- संभाव्यता सिद्धांत का विकास गैबलिंग या जोखिमों के आकलन के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से प्रेरित है।

एबेल पुरस्कार

- एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार गणित में लाइफटाइम उपलब्धि को मान्यता देता है।
- इसके तहत 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर (लगभग £600,000) की राशि प्रदान की जाती है।

इसरो को एविशन वीक लॉरेट्स अवार्ड

- भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन की उपलब्धियों के लिए **एविशन वीक लॉरेट्स अवार्ड** प्रदान किया गया।
- एविशन वीक लॉरेट्स अवार्ड एयरोस्पेस उद्योग के भीतर असाधारण उपलब्धियों को पहचानने के लिए जाना जाता है।
- चंद्रयान-3 मिशन ने केवल 75 मिलियन डॉलर की लागत से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी।
- हाल ही में, इसरो को उसकी अटूट प्रतिबद्धता और चंद्र अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हुसाविक संग्रहालय की ओर से **लीफ एरिकसन लूनर पुरस्कार** दिया गया था।

पहला 'वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार'

- **बीना अग्रवाल और जेम्स बाँयस** को वैश्विक असमानताओं को समझने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहले "वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार" से सम्मानित किया गया है।
- यह पुरस्कार वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब (WIL) और साइंसेज पो के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सोशल इनइक्वलिटीज (CRIS), ग्लोबल इनइक्वलिटी रिसर्च अवार्ड (GiRA) के संयुक्त तत्वावधान में दिया जाता है।
- इसका उद्देश्य उन सभी विषयों के शोधकर्ताओं को सम्मानित करना है जिन्होंने वैश्विक असमानताओं को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

- यह वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार हर दो साल में प्रदान किया जाएगा।
- अर्थशास्त्री **बीना अग्रवाल** (मैनचेस्टर विश्वविद्यालय), लैंगिक असमानताओं, पर्यावरण प्रशासन, पारिस्थितिक नारीवाद और पर्यावरणीय असमानताओं से संबंधित लेखिका हैं।
- अर्थशास्त्री **जेम्स के. बाँयस** (मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय), सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय गिरावट के बीच संबंधों के लेखक हैं।

संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024

- प्रसिद्ध कर्नाटक गायक थोडुर **मदाबुसी (T.M.) कृष्णा** को वर्ष 2024 का 'संगीत कलानिधि पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा।
- टी.एम. कृष्णा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (वर्ष 2016) और राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
- 'संगीत कलानिधि पुरस्कार' कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
- यह मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है।

अन्य पुरस्कार

- संगीतज्ञ पुरस्कार : डॉ. मार्गरेट बास्टिन।
- नृत्य कलानिधि पुरस्कार : डॉ. नीना प्रसाद।
- संगीत कला आचार्य पुरस्कार : मृदंगम वादक परसाला रवि (वी. रवींद्रन नायर) और गायिका गीता राजा।
- टीटीके पुरस्कार : तिरुवैयारु ब्रदर्स एस नरसिम्हन और एस वेंकटेशन और वायलिन वादक एचके नरसिम्हा मूर्ति।

ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू

- ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है।
- इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई।
- ज्ञानेश कुमार साल 1988 बैच के केरल कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वे गृह मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं।
- उत्तराखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू मूल रूप से पंजाब से हैं। वह उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर रह चुके हैं।

भारतीय चुनाव आयोग:

- चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई।
- यह भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु एक स्वतंत्र निकाय है।
- स्थापना के समय आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था।
- इसमें वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक होता है।
- वर्तमान में राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।

चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया

- इनकी नियुक्ति 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम-2023' द्वारा की जाती है।
- इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त चयन प्रक्रिया में दो समितियाँ शामिल होंगीं।
- पहला कानून मंत्री के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय खोज समिति, जिसमें दो सचिव स्तरीय अधिकारी भी शामिल रहेंगे।

- खोज समिति चयन समिति को पांच नामों की सिफारिश करेगी, हालांकि चयन समिति को इस सूची के बाहर से भी आयुक्तों का चयन करने का अधिकार है।
- इसके बाद इनके सुझाए नामों में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय चयन समिति फैसला करेगी।
- इस समिति में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के अलावा एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।
- इसके बाद चयन समिति द्वारा की गई सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी।

सब-इंस्पेक्टर सुमन कुमारी

- सब-इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी हैं।
- उन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपंस एंड टैक्टिक्स (CSWT) में आठ सप्ताह का स्नाइपर प्रशिक्षण पूरा किया।
- स्नाइपर कोर्स में 56 पुरुष साथियों के साथ वह एकमात्र महिला थीं।
- वह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से हैं।

सुधा मूर्ति

- प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी सुधा मूर्ति (Sudha Murty) को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है।
- उन्हें 2006 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार और 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
- वह टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी (TELCO) यानी टाटा मोटर्स की पहली महिला इंजीनियर थीं।

राज्यसभा के मनोनीत सदस्य

- संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 को सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
- भारत के राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र के 12 व्यक्तियों को 6 वर्ष हेतु राज्यसभा में नामांकित करते हैं।
- एक मनोनीत सदस्य को अपनी सीट ग्रहण के पहले छह महीनों के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति होती है।

- संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुसार, किसी सदन का एक मनोनीत सदस्य सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह अपनी सीट ग्रहण की तारीख से छह महीने की समाप्ति के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।
- मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र नहीं हैं, हालांकि, वह उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं।

किशोर मकवाना

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशोर मकवाना को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)

- NCSC एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है।
- यह अनुसूचित जाति और एंग्लो-इंडियन समुदायों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करने और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
- आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- आयोग के पास किसी मुकदमे की सुनवाई करने वाली सिविल अदालत की सभी शक्तियाँ हैं।
- **नोट:** श्री लव कुश कुमार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के सदस्य नियुक्त किए गए।

शीतल देवी

- चुनाव आयोग के राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति (PWD) आइकन घोषित किया गया है।
- चुनाव आयोग द्वारा दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए एक समर्पित मतदाता मार्गदर्शिका भी लॉन्च की गई।
- शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें 9 जनवरी 2024 को अर्जुन पुरस्कार 2023 मिला।
- वह बिना हाथों वाली पहली और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय पैरा-तीरंदाजी चैंपियन हैं।

नायब सिंह सैनी

- नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
- वह हरियाणा राज्य कुरुक्षेत्र से सांसद हैं।
- हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें शपथ दिलाई।

अरविंद केजरीवाल

- अरविंद केजरीवाल पद पर रहते गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया।
- तमिलनाडु की AIADMK प्रमुख जे. जयललिता 1996 में गिरफ्तार होने वाली पहली पूर्व मुख्यमंत्री थीं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002:

- इसे 2002 में अधिनियमित किया गया और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया।
- इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।
- इसमें 2012 में बैंकों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को दायरे में लाने के लिए संशोधन किया गया था।
- PMLA के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। इसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है।
- वर्ष 2018 में धारा 45 के तहत PMLS के तहत जमानत के लिए अधिक सख्त शर्तें जोड़ी गईं।

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी

- ऋतुराज अवस्थी ने 27 मार्च 2024 को भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली।
- भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने शपथ दिलाई।
- श्री पंकज कुमार और श्री अजय तिकी ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली।
- न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं।
- श्री पंकज कुमार गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह गुजरात के मुख्य सचिव रह चुके हैं।
- श्री अजय तिकी 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव रह चुके हैं।

सदानंद वसंत दाते

- सदानंद वसंत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
- वह 1990-बैच के एक वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं।
- वह वर्तमान में महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।

- उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 31 दिसंबर 2026 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है।

राजीव कुमार शर्मा

- राजीव कुमार शर्मा को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- राजीव कुमार शर्मा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी हैं।

पीयूष आनंद

- पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) का महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है।
- वह उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं।

विनय मोहन क्वात्रा

- केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का सेवा कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
- क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं।
- वह 31 अक्टूबर, 2024 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बने रहेंगे।
- उन्हें अप्रैल 2022 में भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में विदेश सचिव नियुक्त किया गया था।
- उन्होंने हर्ष वर्धन श्रृंगला का स्थान लिया।

राहुल सिंह

- राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- वह निधि छिब्रर का स्थान लेंगे, जिन्हें नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया गया है।
- वह बिहार कैडर के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे।

देवेन्द्र झाझड़िया

- देवेन्द्र झाझड़िया भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं।
- देवेन्द्र ने दीपा मलिक का स्थान लिया।
- देवेन्द्र झाझड़िया ने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते।
- उन्होंने अपना पहला पैरालंपिक स्वर्ण 2004 में एथेंस में जीता था। उन्होंने दूसरा स्वर्ण 2016 में रियो में जीता।
- उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीता।

नवनीत कुमार सहगल

- नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं।
- नवनीत कुमार सहगल यूपी कैडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।
- उन्होंने ए. सूर्य प्रकाश का स्थान लिया।

प्रसार भारती

- यह दूरदर्शन और आकाशवाणी के संचालन की निगरानी करता है।
- प्रसार भारती का गठन नवंबर 1997 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

पीआर श्रीजेश और कैमिला कैरम

- पीआर श्रीजेश और कैमिला कैरम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ(FIH) की नई एथलीट समिति के सह-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
- FIH एथलीट समिति एक सलाहकार निकाय है।
- पीआर श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं।
- वह केरल से हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता।
- कैमिला कैरम चिली की फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं।
- फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी (FIH) को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता है।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है।

जयंत मूर्ति

- भारतीय प्रोफेसर और प्रख्यात वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम 'जयंतमूर्ति' रखा गया है।
- उन्हें अंतरिक्ष अभियानों, पराबैंगनी खगोल विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।
- पहले 2005 EX296 के रूप में सूचीबद्ध, क्षुद्रग्रह (215884) को अब जयंतीमूर्ति के रूप में नामित किया गया है।
- यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) के कार्य समूह द्वारा की गई।
- क्षुद्रग्रह (215884) जयंत मूर्ति की खोज 2005 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में एमडब्ल्यू बुई द्वारा की गई थी।
- यह हर 3.3 साल में मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की एक पूरी परिक्रमा पूरी करता है।

एडमिरल लक्ष्मीनारायण रामदास

- इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वह पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख थे। उन्होंने दिसंबर

1990 और सितंबर 1993 के बीच 13वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्य किया।

- उन्हें 2004 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उन्हें दक्षिण एशिया को विसैन्यीकरण और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में उनके प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- उन्हें वीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया।

विनय कुमार

- इन्हें 19 मार्च 2023 को रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है।

व्लादिमीर पुतिन

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पांचवीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं।
- उन्हें लगभग 87 प्रतिशत वोट मिले। पुतिन का कार्यकाल 6 साल का रहेगा।
- 18वीं सदी के दशक में कैथरीन द ग्रेट के बाद व्लादिमीर पुतिन सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले रूसी नेता बन गए हैं।

रूस का राष्ट्रपति:

- रूसी संघ का राष्ट्रपति रूस के राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है।
- रूस के राष्ट्रपति रूसी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर-इन-चीफ होता हैं।
- राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को रूसी संघ का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए।
- 2020 में संवैधानिक बदलावों के बाद राष्ट्रपति दो से अधिक कार्यकाल के बाद भी पद पर रह सकते हैं।

आसिफ अली जरदारी

- आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का 14वाँ राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है।
- आसिफ अली जरदारी दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं।
- इससे पहले साल 2008 से 2013 के बीच पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति बने थे।
- उन्होंने डॉ. आरिफ अल्वी का स्थान लिया।
- श्री जरदारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के संयुक्त उम्मीदवार थे और उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद

खान अचकजई से हुआ।

- राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो जरदारी को देश की प्रथम महिला घोषित किया।

शहबाज शरीफ

- शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं।
- शहबाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के संयुक्त उम्मीदवार हैं।
- शाहबाज को 336 सदस्यीय सदन में 201 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के उमर अयूब खान को 92 वोट मिले।
- इससे पहले, शाहबाज अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे।

मोहम्मद मुस्तफा

- मोहम्मद मुस्तफा फिलिस्तीनी प्राधिकरण के प्रधानमंत्री बने हैं।
- मुस्तफा ने मोहम्मद शतायेह का स्थान लिया।
- फिलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की स्थापना ओस्लो समझौते नामक अंतरिम शांति समझौते के तहत की गई थी।
- यह कब्जे वाले वेस्ट बैंक के सीमित हिस्सों पर शासन करता है।
- यह इजराइल के साथ संघर्ष समाप्त होने के बाद गाजा पर शासन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- चरमपंथी संगठन हमास ने PA से 2007 में गाजा का नियंत्रण छीन लिया था।

बस्सिरौ डियोमाये फे

- बस्सिरौ डियोमाये फे सेनेगल के अगले राष्ट्रपति बने हैं।
- फे अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम उम्र के निर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं।
- सेनेगल की स्वतंत्रता के बाद यह सत्ता का चौथा लोकतांत्रिक हस्तांतरण है।
- सेनेगल 1960 में फ्रांस से आजाद हुआ था।

सेनेगल:

- यह महाद्वीपीय अफ्रीका का सबसे पश्चिमी देश है।
- इसकी राजधानी डकार है।
- इसकी सीमा उत्तर में मॉरिटानिया, पूर्व में माली और दक्षिण-पूर्व में गिनी से लगती है।

साइमन हैरिस

- साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं।
- आयरलैंड की सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी ने 24 मार्च को साइमन हैरिस को अपना नेता चुना था।
- साइमन हैरिस ने लियो वराडकर का स्थान लिया।
- हैरिस आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री (37 वर्षीय) हैं।

क्रिस ब्राउन

- पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिन्दु 'प्वाइंट निमो' तक पहुँचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं।
- प्वाइंट निमो- न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित पृथ्वी का सुदूरतम बिन्दु है।

निधन

लामा लोबजांग

- यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व सदस्य लद्दाख के प्रमुख भिक्षु रहे थे।
- इनका 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली में निधन हुआ।
- यह प्रतिष्ठित आदिवासी नेता थे, जो 19 वर्षों तक आयोग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में सदस्य रहे।

कपिल देव प्रसाद

- यह प्रसिद्ध बुनकर थे।
 - इन्हें बाबन बूटी साड़ी बुनने के लिए 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
-

9

चर्चित स्थल

कोलकाता: भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को कोलकाता में भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया।
- कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान - एस्प्लेनेड मेट्रो खंड में भारत की पहली अंडरवाटर ट्रांसपोर्टेशन टनेल है।
- कोलकाता की अंडरवाटर मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन का निर्माण हुगली नदी के नीचे किया गया है।
- इसमें दो स्टेशनों - हावड़ा मैदान और एस्प्लेनेड के बीच सुरंग की कुल लंबाई 4.8 किलोमीटर है।
- इसमें 1.2 किमी सुरंग हुगली नदी में 30 मीटर नीचे है, जो इसे 'किसी भी नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग' बनाती है।
- हावड़ा मैदान-एस्प्लेनेड खंड ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है।
- हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है।

थूथुकुडी (तमिलनाडु) : भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी

- भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी (Hydrogen Fuel Cell Ferry) का थूथुकुडी (तमिलनाडु) में 28 फरवरी, 2024 को लॉन्च की गई।
- यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित है।
- इस जहाज को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में तैनात किया जाएगा।
- यह जहाज वातानुकूलित युक्त है तथा यह 50 लोगों को ले जा सकता है।
- यह जहाज हाइड्रोजन ईंधन पर चलता है तथा पारम्परिक बैटरियों का उपयोग नहीं करता है।

अहमदाबाद: कोचरब आश्रम

- प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को साबरमती आश्रम का दौरा किया और अहमदाबाद में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया।
- इसके अलावा गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारम्भ भी किया गया।
- कोचरब आश्रम 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला

आश्रम था।

- इसे गुजरात विद्यापीठ द्वारा एक स्मारक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित रखा गया है।
- **नोट:** 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी।

पटना: गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र

- बिहार के पटना में 4 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (National Dolphin Research Centre (NDRC)) का उद्घाटन किया गया।
- यह एंडेंजर्ड गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत का पहला केंद्र है।
- इसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है।

गंगा नदी डॉल्फिन

- गंगा नदी डॉल्फिन (Ganges river dolphin) केवल गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और बांग्लादेश, भारत और नेपाल के निकटवर्ती कर्णफुली-सांगु नदी प्रणालियों में होती है।
- गंगा डॉल्फिन भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची I में सूचीबद्ध है।
- प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है।

छावनी (दिल्ली): नौसेना के नए मुख्यालय का उद्घाटन

- नौसेना के नए मुख्यालय 'नौसेना भवन' का 15 मार्च, 2024 को दिल्ली के छावनी में उद्घाटन किया गया।
- यह नौसेना का अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय है।
- इससे पहले नौसेना का संचालन 13 अलग-अलग स्थानों से किया जाता था।
- यह इमारत आधुनिक सुविधाओं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस है। इस इमारत में श्री लेयर सिक्वोरिटी सिस्टम है।
- इसमें ऑटोमैटेड अंडरबेली स्कैनिंग, फेस रिकॉग्नाइजेशन, इलेक्ट्रिकल कॉर्डॉस, बोलाड, व्हीकल स्टॉपर्स शामिल हैं।

भोपाल: देश का सबसे ऊँचा मौसम टॉवर

- मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊँचे मौसम टॉवर का 13 मार्च, 2024 को उद्घाटन किया गया।
- भोपाल के निकट सीलखेड़ा में लगा 72 मीटर ऊँचा यह टॉवर 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है।
- इस टॉवर से मौसम के पूर्वानुमान में अधिक सटीकता आएगी।
- इससे 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग पता चल जाएगी।
- यह दक्षिण एशिया के एकमात्र और सबसे बड़ा सेंटर है।

तिरुवनंतपुरम: भारत का पहला फ्यूचरलैब्स केंद्र का उद्घाटन

- केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 12 मार्च 2024 को C-DAC तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले FutureLABS केंद्र का उद्घाटन किया है।
- इस सेंटर को 'सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम्स फॉर स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स' नाम दिया गया है।
- यह सेंटर नेक्स्ट जेनरेशन चिप डिजाइन, मैनुफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए रेल मंत्रालय और C-DAC (I) के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुए।
- माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और स्थापना के लिए C-DAC(I) और टाटा पावर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह सेंटर भविष्य में नए अवसरों की खोज में मददगार साबित होगा।
- FutureLABS भारत सरकार के सिस्टम के रूप में C-DAC को इंडस्ट्री, छात्रों, स्टार्टअप और शिक्षा जगत को जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा।

जम्मू-कश्मीर: भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगाफैक्ट्री

- भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगाफैक्ट्री अक्टूबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू कर देगी।
- यह बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री सालाना 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी।
- यह 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करेगा।
- ये परियोजनाएँ भारत के 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने के लक्ष्य के

लिए महत्वपूर्ण हैं।

- ये बैटरी भंडारण पहल सौर और पवन जैसे विभिन्न नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा के भंडारण और उपयोग की सुविधा प्रदान करेगी।

बेंगलुरु : कर्नाटक और विश्व आर्थिक मंच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक केंद्र स्थापित करेंगे

- यह केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा।
- यह भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित विश्व आर्थिक मंच का एकमात्र केंद्र होगा।
- यह चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच केंद्र (C4IR) का हिस्सा है।
- यह केंद्र उद्योग-अकादमिक नेटवर्क स्थापित करने और तकनीकी रुझानों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इसका मुख्य लक्ष्य एआई के नैतिक और व्यावहारिक आयामों पर वैश्विक बातचीत में योगदान देना है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए बेंगलुरु को विश्व स्तर पर शीर्ष पांच शहरों में से एक माना जाता है।

हिसार: स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट

- इसका उद्घाटन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में किया गया है।
- यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा।
- यह छत और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा।
- इससे प्रति वर्ष लगभग 2,700 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी।
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में शुरू किया गया था।
- इसे ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।

लोअर दिबांग घाटी: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) आधारित पहली तेल मिल

- प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम (NMEO-OP) के तहत पहली तेल मिल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया।
- यह मिल अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी में स्थित है।
- यह 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट है।

राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP)

- भारत सरकार ने अगस्त 2021 में खाद्य तेलों के लिए राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम (NMEO-OP) लॉन्च किया था।
- इस मिशन का लक्ष्य देश के लिए तिलहन और पाम तेल को बढ़ावा देने के माध्यम से खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।
- यह मिशन ऑयल पाम की खेती को बढ़ाने और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के लिए शुरू किया गया।
- NMEO-OP ने ऑयल पाम के प्रसार के लिए 11,040 रुपये के कुल राष्ट्रीय बजट में से विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5,870 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जहां 90% योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- ऑयल पाम मिशन को रणनीतिक रूप से नए भौगोलिक क्षेत्रों में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- भारत वर्तमान में खाद्य तेल का शुद्ध आयातक है, कुल खाद्य तेल का 57% विभिन्न देशों से आयात किया जाता है।

कश्मीर घाटी: एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन

- यह गार्डन कश्मीर घाटी में स्थित है, जिसका उद्घाटन 23 मार्च 2024 को किया गया है।

मुंद्रा: दुनिया का सबसे बड़ा एकल-स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र

- अडानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल-स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र का पहला चरण शुरू किया।
- अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी, कच्छ कॉपर, ने 1.2 बिलियन डॉलर की 'ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी' के पहले चरण को शुरू किया है।
- इस सुविधा के पहले चरण में 0.5 मिलियन मीट्रिक टन परिष्कृत तांबे का उत्पादन किया जाएगा।
- यह संयंत्र वित्त वर्ष 2029 तक अपनी पूर्ण क्षमता 1 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा।

नई दिल्ली: आयुष-ICMR उन्नत केंद्र

- एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष-ICMR उन्नत केंद्र एम्स, नई दिल्ली में लॉन्च किया गया।
- इसका लक्ष्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा का एक साथ उपयोग करके, रोगियों को

समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है।

- ये केंद्र एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश में स्थापित किए जाएंगे।
- यह व्यापक उपचार योजनाएँ और दिशानिर्देश विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

जोरहाट: असम में लचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को पूर्वी असम के जोरहाट जिले में अहोम जनरल लचित बोरफुकन (Lachit Borphukan) की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया।
- लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य (1228-1826) के एक प्रसिद्ध सेना कमांडर थे, जिन्हें 1671 के 'सरायघाट की लड़ाई' में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता था।
- उन्होंने इस युद्ध में मुगल सेना को हराया और असम को वापस लेने के मुगलों के प्रयास को विफल कर दिया।
- बोरफुकन की 49 साल की उम्र में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई और उन्हें हॉलोंगापार में 'मैदाम'-अहोम राजघरानों और रईसों के कब्रिस्तान में दफनाया गया, इसी स्थान पर स्मारक बनाया जा रहा है।

पनामा: ISA का अनुमोदन करने वाला 97वाँ सदस्य बना

- यह मध्य अमेरिका का दक्षिणतम देश है।
- पनामा हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance -ISA) का अनुमोदन करने वाला 97वाँ सदस्य बना है।
- पनामा ने अनुमोदन सम्बन्धी दस्तावेज नई दिल्ली में 7 मार्च, 2024 को सौंपे।
- नोट: माल्टा अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वाँ देश बना था।

टोंकिन की खाड़ी

- चीन ने हाल ही में वियतनाम के साथ साझा की जाने वाली टोंकिन की खाड़ी (Gulf of Tonkin) के उत्तरी भाग में अपने क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए एक नई आधार रेखा की घोषणा की है।
- चीन द्वारा इस क्षेत्र में नई आधार रेखा चित्रण किए जाने से चीन और वियतनाम के मध्य टोंकिन की खाड़ी में सीमांकन को लेकर टकराव की स्थिति बन गई है।
- टोंकिन की खाड़ी को चीनी भाषा में 'बेइबू खाड़ी' (Beibu Gulf) के नाम से जाना जाता है।

महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा

- महाराष्ट्र सरकार की राज्य कैबिनेट ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने का फैसला किया है।
 - अहिल्यानगर का नाम अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर रखा गया है। वह 18वीं शताब्दी में मालवा प्रांत की शासिका थीं।
 - अहिल्याबाई का जन्म 31 मई, 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुआ था।
- इसके अलावा वेलहा तहसील का नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया गया है। यह शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी थी।
- महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में आठ उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को भी मंजूरी दे दी।
 1. करी रोड स्टेशन - लालबाग स्टेशन
 2. सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन - डोंगरी स्टेशन
 3. मरीन लाइन्स - मुंबादेवी
 4. चर्नी रोड - गिरगांव रोड
 5. कॉटन ग्रीन - कालाचौकी
 6. डॉकयार्ड- मझगांव
 7. किंग्स सर्कल - तीर्थकर पार्श्वनाथ सर्कल
 8. मुंबई सेंट्रल - नाना जगन्नाथ शंकरशेठ
- **नोट:** समाज सुधारक, शिक्षाविद् और परोपकारी नाना जगन्नाथ शंकरसेठ को मुंबई (तब बॉम्बे) का 'वास्तुकार' माना जाता है।

निम्न-पदम-दारचा

- यह लद्दाख में स्थित रणनीतिक सड़क है।
- इसका अनावरण 25 मार्च, 2024 को किया गया।
- यह सड़क (लंबाई 298 किमी.) कारगिल-लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्नू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी।
- यह सड़क शिंकन ला दर्रे (16,558 फीट) से गुजरती है, जो कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- शिंकन ला सुरंग (Shinkan La tunnel) का निर्माण होने के बाद यह लद्दाख के लिए तीसरी सभी मौसम में खुल रहने वाली धुरी (axis) स्थापित हो जाएगी।

सिलखेड़ा (सीहोर): मध्य भारत में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण (ART-CI)

- मध्य भारत में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण (Atmospheric Research Testbed in Central India: ART-CI) के पहले चरण का उद्घाटन 12 मार्च को, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सिलखेड़ा में किया गया।

- यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES) द्वारा वित्त पोषित है।
- इस फैसिलिटी में मध्य भारत के मानसून कोर जोन (MCZ) पर मानसून से जुड़ी महत्वपूर्ण क्लाउड प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए 25 उच्च-स्तरीय मौसम संबंधी उपकरण लगेंगे।
- ART सिलखेड़ा में एक खुला क्षेत्र, केंद्रित अवलोकन और विश्लेषणात्मक अनुसंधान कार्यक्रम है।
- ART में सेटअप का उपयोग विभिन्न उपग्रह-आधारित अवलोकनों, मौसम की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के हिस्से को कैलिब्रेट करने के लिए भी किया जाएगा।
- सिलखेड़ा ऐसा स्थान है जो प्रमुख वर्षा-वाहक सिनोप्टिक प्रणालियों के पथ के सीधे अनुरूप है। इससे सीधी निगरानी और ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी।

पदमपुर (खरसावां): जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र

- केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में 'जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र' (Centre for Preservation and promotion of Tribal Culture - Heritage) की आधारशिला रखी।
- यह संग्रहालय झारखंड राज्य में आदिवासी समुदाय की समृद्ध विरासत को चित्रित करने और संरक्षित करेगा, साथ ही समृद्ध आदिवासी जीवन शैली और संस्कृति को प्रदर्शित करता है।
- इसके अलावा, यह आदिवासी समुदायों को उनके विकास में सहायता करने के लिए ज्ञान और सूचना केंद्र होगा।

केई पन्योर

- यह हाल ही नवगठित अरुणाचल प्रदेश का 26वां नया जिला है।
- केई पन्योर को निचले सुबनसिरी से क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया है।
- इस जिले का मुख्यालय टेर गैपिन-सैम सार्थ होगा।
- यह नया जिला न्यीशी समुदाय के लोगों की मांग पर बनाया गया है।

अरुणाचल प्रदेश:

- इसका गठन नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) क्षेत्र से हुआ था।
- इसे 20 फरवरी 1987 को इसे एक राज्य घोषित किया गया।
- इसकी राजधानी ईटानगर (राज्य का सबसे बड़ा शहर) है।

अरुणाचल प्रदेश: 'सेला सुरंग' का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग (टनल) का उद्घाटन किया।
- यह दुनिया की सबसे लंबी डबल-लेन सुरंग है।
- इससे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तेजी से सैन्य आवाजाही में मदद मिलेगी।
- इसका उद्देश्य बालीपारा-चारिद्वार-तवांग (BCT) रोड पर सेला दर्रे के पार तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

- सेला सुरंग 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनी है और ये असम तेजपुर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग को जोड़ती है।
- **नोट:** तवांग में वर्ष 2022 में भारतीय जवानों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी।
- इसका डिजाइन और इन्फ्रास्ट्रक्चर भारतीय सेना की स्पेशल विंग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (BRO) ने तैयार किया है।

चर्चित पुस्तकें

- 11 रूल्स फॉर लाइफ: सीक्रेट्स टू लेवल अप (11 Rules For Life: Secrets to Level Up) - चेतन भगत
- द विनर्स माइंडसेट - ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू एवरी गेम एण्ड टू लाइफ (The Winner's Mindset - Bringing the Best Version of You to Every Game and to Life) - शेन वाटसन
- द कॉन्सपिरेसी टू ऑस्ट मी फ्रॉम द प्रेसीडेंसी (The Conspiracy to oust me from the Presidency) - गोटबाया राजपक्षे (श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति)
- स्वाल्लोइंग द सन (Swallowing the Sun) - लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी
यह संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव रह चुकी है।
यह इनका पहला उपन्यास है इस पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कथाएँ हैं।

10

महत्वपूर्ण तथ्य

भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च

- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म, 'सीस्पेस' का उद्घाटन किया।
- यह देश का पहला राज्य सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च है।
- केरल राज्य फिल्म विकास निगम (KSFDC) द्वारा प्रबंधित, सीस्पेस केरल सरकार के सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सहयोग से संचालित होता है।
- इसे ओटीटी क्षेत्र में बढ़ते असंतुलन और विविध चुनौतियों से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है।
- सीस्पेस पर प्रत्येक सबमिशन तीन क्यूरेटर द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरता है जो इसके कलात्मक, सांस्कृतिक और मनोरंजन मूल्य पर विचार करते हैं। केवल स्वीकृत सामग्री ही प्लेटफॉर्म पर आती है।
- सीस्पेस एक Pay-Per-View मॉडल अपनाता है, जो उपयोगकर्ताओं से प्रति मूवी 75 रुपये चार्ज करता है।
- यह मलयालम सिनेमा और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है।
- 60 सदस्यों का एक पैनल इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट का चयन और अनुमोदन करेगा।

भारतीय मानक समय (IST) के प्रसार के लिए नेशनल टाइम प्रोटोकॉल का उद्घाटन

- केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने 15 मार्च 2024 को मुंबई में भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए नेशनल टाइम प्रोटोकॉल (NTP) का उद्घाटन किया।
- इससे मिलीसेकंड सटीकता के साथ एक समान और सटीक समय की जानकारी मिलेगी और साइबर सुरक्षा भी बढ़ेगी।
- इसे time.nplindia.org या time.nplindia.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
- फरीदाबाद और अहमदाबाद में क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला (RRSL) में टाइमिंग बुनियादी ढांचे का भी उद्घाटन किया गया।
- भारत समय वितरण प्रणाली लागू करने वाला

पहला देश है।

- इसके तहत बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और दिल्ली में RRSL में दिसंबर 2024 तक परमाणु घड़ियां लगाई जाएंगी।
- पहले समय ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) से लिया जाता था लेकिन अब इसमें नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NavIC) की मदद से अपना सिस्टम होगा।
- देशभर के सभी मोबाइल ऑपरेटरों को इस सिस्टम के साथ टाइम सिंक करना होगा।

इलेक्टोरल बॉण्ड की जानकारी सार्वजनिक की गई

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तहत निर्वाचन आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा प्रदत्त चुनावी बॉण्ड (Electoral bond) की जानकारी अपनी वेबसाइट पर 14 मार्च, 2024 को अपलोड की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी, 2024 को इलेक्टोरल बॉण्ड को असंवैधानिक घोषित दिया था।

चंदा लेने वाले शीर्ष 3 राजनीतिक दल

- | | |
|-------------------|-------------------|
| • भाजपा | 6,060 करोड़ रुपये |
| • तृणमूल कांग्रेस | 1,609 करोड़ रुपये |
| • कांग्रेस | 1,421 करोड़ रुपये |

चंदा देने वाली शीर्ष 3 कम्पनियाँ

- | | |
|--|-------------------|
| • फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज | 1,368 करोड़ रुपये |
| • मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर | 966 करोड़ रुपये |
| • क्रिक | 410 करोड़ रुपये |

फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स (FTLs)

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग और मेटा ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स (Frontier Technology Labs: FTLs) के लॉन्च की घोषणा की है।
- भारत में अलग-अलग बैकग्राउंड के छात्रों को सीखने और अग्रणी प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु अटल इनोवेशन मिशन और मेटा रणनीतिक महत्व के स्कूलों में FTL स्थापित करने के लिए साझेदारी करेंगे।
- इसका उद्देश्य भविष्य की प्रौद्योगिकियों को लोकतांत्रिक बनाने और युवाओं को इनोवेशन करने के लिए सशक्त बनाना है।

- अब तक, AIM ने भारत के 722 जिलों के स्कूलों में 10,000 अटल टिकरिंग लैब्स (ATLs) स्थापित किए हैं।
- ATL का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन देना और डिजाइन मानसिकता, कम्प्यूटेशनल सोच, फिजिकल कंप्यूटिंग जैसे कौशल विकसित करना है।
- FTL अटल टिकरिंग लैब का एक अपग्रेड वर्जन है जो अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस है, जिसमें टिकरिंग लैब के सभी घटक शामिल हैं।
- ये छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इनोवेशन करने के लिए सशक्त बनाते हैं।

‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन-2024’ अभियान

- केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 9 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में ‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया।
- अभियान का पांचवां संस्करण ‘नारी शक्ति से जल शक्ति’ थीम के तहत शुरू किया गया है।
- यह अभियान 9 मार्च, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक चलेगा।
- इस अभियान में निम्नलिखित बिंदुओं पर फोकस किया गया है-
 - (1) जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन
 - (2) सभी जल निकायों की गणना, भू-टैगिंग एवं सूची तैयार करना; जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाएँ बनाना
 - (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना
 - (4) सघन वनीकरण
 - (5) जागरूकता सृजन
- **नोट:** ‘जल शक्ति अभियान: कैच द रेन’ अभियान 2021 में शुरू किया था।

दिबांग बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजना

- इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 9 मार्च, 2024 को अरुणाचल प्रदेश में रखी गई।
- NHPC लिमिटेड की 2,880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देश्यीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में मुनली गाँव के समीप बनेगी।
- इसका प्रमुख उद्देश्य में विद्युत उत्पादन के अलावा बाढ़ नियंत्रण शामिल है।
- इस परियोजना पर बनने वाला बाँध देश का सबसे ऊँचा बाँध होगा।

- यह बाँध 278 मीटर ऊँचा बाँध है, जो भारत का सबसे ऊँचा कंक्रीट-ग्रेविटी बाँध होगा।
- इस बाँध का निर्माण रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट (RCC) तकनीक से किया जाएगा।
- इस परियोजना की लागत लगभग ₹ 31,875 करोड़ है।
- इस परियोजना से प्रति वर्ष 11,223 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पन्न होगी।
- इस परियोजना को ऊर्जा भंडारण परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है।
- यह परियोजना फरवरी 2032 तक शुरू हो सकती है।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) गोवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनी

- यह छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी है।
- इस खदान की उत्पादन क्षमता मौजूदा 52.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 70 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है।
- गोवरा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की बड़ी परियोजनाओं में से एक है और यह देश की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है।
- इस खदान की स्ट्राइक लेंथ करीब 10 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई चार किलोमीटर है।
- यह खदान सरफेस माइनर, रिपर माइनिंग के रूप में पर्यावरण के अनुकूल ब्लास्ट-मुक्त माइनिंग प्रौद्योगिकी से लैस है।

शेरनी (SheRNI)

- इसका पूरा नाम She Research Network in India- SheRNI है।
- इसे 9 मार्च, 2024 को लॉन्च किया।
- इसका उद्देश्य वैज्ञानिकों और संकाय के बीच लैंगिक समानता स्थापित करना है।
- यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केन्द्र द्वारा लॉन्च किया गया।
- यह पहल विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र

- यह झारखण्ड स्थित हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL) का उर्वरक संयंत्र है, जिसे मार्च, 2024 को राष्ट्र को समर्पित किया।
- इस उर्वरक संयंत्र से देश में प्रति वर्ष लगभग 12.7 LMT स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा।
- यह देश में पुनरुद्धार होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है।

- गोरखपुर (दिसम्बर 2021)
- रामागुंडम (नवम्बर 2022)
- सिंदरी (मार्च,2024)

मेलानोक्लैमिस द्रौपदी (Melanochlamys droupadi)

- यह एक नई समुद्री प्रजाति है, जिसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के नाम पर रखा जाएगा।
- हाल ही में जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) द्वारा ओडिशा और बंगाल के समुद्री तटों पर समुद्री स्लग मोलस्क की एक नई किस्म खोजी गई है।
- यह नई प्रजाति केवल भारत में ही पाई जाती है।
- यह भारत में पाई गई हेड-शील्ड समुद्री स्लग की दूसरी प्रजाति है। पहली प्रजाति पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस (Melanochlamys bengalensis) है।
- यह एक छोटा अकशेरुकी एवं उभयलिङ्गी प्राणी है।
- यह प्रजाति अन्य प्रजातियों से अलग गीले और नरम रेतीले समुद्र तटों पर निवास करती है।

संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल लॉन्च

- केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा 4 मार्च को साइबर धोखाधड़ी की जांच के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु - रिपोर्ट संधिध धोखाधड़ी संचार सुविधा नई दिल्ली में लॉन्च की गई।
- इस डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय बनाना है।
- कोई भी व्यक्ति चक्षु पोर्टल पर धोखाधड़ी कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संधिध संदेशों को रिपोर्ट कर सकता है।
- संचार साथी पोर्टल लॉन्च होने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन रोकें गए हैं।

नीति आयोग का 'नीति फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म लॉन्च

- यह एक क्रॉस-सेक्टरल ज्ञान प्लेटफॉर्म है।
- इसे सुशासन और नीति के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- प्लेटफॉर्म में 7,500 सर्वोत्तम प्रथाओं 5,000 नीतिगत दस्तावेजों और 350 नीतिगत प्रकाशनों का एक बहु-क्षेत्रीय लाइव भंडार शामिल है।
- इस प्लेटफॉर्म पर ज्ञान उत्पादों के 10 क्षेत्र शामिल हैं।
- इन 10 क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, MSME, पर्यटन, शहरी और जल संसाधन शामिल हैं।

- यह जिला कलेक्टरों और ब्लॉक-स्तरीय पदाधिकारियों को विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च

- केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस लॉन्च किया गया है।
- इससे देश में सहकारी समितियों के विस्तार और विकास में मदद मिलेगी।
- भारत में 8 लाख से अधिक पंजीकृत समितियाँ हैं तथा इनसे 30 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं।
- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एक वेब-आधारित डिजिटल डैशबोर्ड है। इसमें 8 लाख सहकारी समितियों की जानकारी है।
- यह डेटाबेस सहकारी समितियों के विस्तार, डिजिटल विकास और डेटाबेस के माध्यम से वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- इसमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को एपेक्स, गांवों को शहरों और मंडियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की क्षमता है।

स्टार्ट-अप महाकुंभ

- इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में 18 मार्च, 2024 को किया गया।
- यह भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्ट-अप आयोजन है।
- इसका आयोजन एसोचौम, नैसकॉम, बूटस्ट्रैप इनक्यूबेशन एण्ड एडवाइजरी फाउंडेशन, TIEE और इंडियन वेंचर एण्ड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
- इस का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को स्टार्ट-अप्स के साथ जोड़ना और उनके लिए कॉर्पोरेट पार्टनर तैयार करना है।

केरल ने 'मानव-वन्यजीव संघर्ष' को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया

- केरल ने 6 मार्च 2024 को मानव-वन्यजीव संघर्ष (Man-Animal Conflict) को राज्य-विशिष्ट आपदा (State-Specific Disaster) घोषित किया।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला केरल देश का पहला राज्य है।
- यदि किसी समस्या को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया जाता है, तो इससे निपटने की जिम्मेदारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (State Disaster Management Authority) पर रहती है।

राज्य-विशिष्ट आपदा

- राज्य स्तर पर, मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और वन विभाग सहित कई विभाग स्टेकहोल्डर होते हैं।
- जिला कलेक्टर जिला आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में स्वयं निर्णय लेने हेतु अधिकृत हैं।
- जब किसी मुद्दे को राज्य-विशिष्ट आपदा या राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाता है, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अन्य सभी मानदंडों को दरकिनार करते हुए त्वरित निर्णय और कार्रवाई कर सकता है।

अहमदाबाद शहर हेतु भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) के बीच ऋण समझौता

- भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच 181 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- यह समझौता अहमदाबाद में शहरीकरण की क्षमता और गतिशीलता में सुधार हेतु किया गया है।
- इस परियोजना का लक्ष्य अहमदाबाद के परि-शहरी क्षेत्रों को रहने योग्य, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और मजबूत भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा विकसित करना है।
- यह परियोजना वित्तीय योजना, राजस्व वृद्धि और बुनियादी ढाँचा परिसंपत्ति संचालन में सरकारी एजेंसियों की क्षमता का भी निर्माण करेगी।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु विशेषज्ञ समिति गठित

- सुप्रीम कोर्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) के संरक्षण हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- यह आदेश कोर्ट द्वारा 21 मार्च, 2024 को पारित किया गया।
- इस समिति में वन्यजीव विशेषज्ञ, संरक्षणवादी और संबंधित मंत्रालयों के सरकारी अधिकारी शामिल किए गए हैं।
- यह समिति राजस्थान और गुजरात में भारतीय वन्य जीवन संस्थान की रिपोर्ट में प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पहचाने गए क्षेत्र में संरक्षण के उपायों के संदर्भ में सुझाव देगी।

यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर (KYC) पर समिति गठित

- यह समिति टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई है।
- यह समिति एक समान केवाईसी तंत्र लागू करने के तरीकों की सिफारिश करेगी।
- वित्त स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) ने वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी प्रक्रिया को डिजिटल

बनाने और सरल बनाने के लिए एक रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया था।

- बजट 2023-24 में, केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने की घोषणा की गई थी।

पीएम-सूरज नेशनल पोर्टल का शुभारंभ

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (PM-SURAJ) नेशनल पोर्टल का शुभारंभ किया।
- इसके तहत 1 लाख से अधिक वंचित वर्ग के लाभार्थियों को राशि स्वीकृत की गई।
- इस पोर्टल से बिना किसी बिचौलिए, कमीशन, कट और सिफारिश के वंचित लोगों के खातों में ऋण की राशि हस्तांतरित होती रहेगी।

डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (CCMS) और 'संकलन' ऐप का उद्घाटन

- केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में नेशनल इनवेस्टिगेटिव एजेंसी (NIA) द्वारा डिजाइन की गई एक यूनिक डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (CCMS) का उद्घाटन किया।
- नई CCMS प्रणाली NIA को आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में बेहतर समन्वय करने में सक्षम होगी जिससे न्याय व्यवस्था में सुधार आएगा।
- इसे NIA ने उपयोग करने वालों के अनुकूल, कस्टमाइज करने योग्य ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर के रूप में विकसित किया है।

मोबाइल ऐप 'संकलन'

- मोबाइल ऐप 'संकलन' राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा नए क्रिमिनल लॉ का एक संग्रह है।
- यह ऐप एक कॉम्प्रिहेन्सिव गाइड के रूप में कार्य करेगा, जो पुराने और नए कानूनी प्रावधानों की विस्तार से तुलना करने में सक्षम है।
- 'संकलन' ऐप को ऑफलाइन मोड में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

चापचर कुट त्यौहार

- यह मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है।
- इस उत्सव में गीतों और सांस्कृतिक नृत्यों के प्रदर्शन के माध्यम से मिजो समुदाय की पारंपरिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन किया जाता है।
- यह त्यौहार हर साल मार्च महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है।

- यह त्यौहार झूम खेती के सबसे कठिन कार्य 'जंगल को साफ करने' के पूरा होने के बाद वर्ष की शुरुआत में, भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है।

गोरसम कोरा महोत्सव

- यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में मनाया जाता है।
- यह त्यौहार भारत और भूटान के बीच स्थायी दोस्ती का प्रतीक है और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को रेखांकित करता है।
- इसे स्थानीय समुदाय के नागरिक अधिकारियों और भारतीय सेना के सहयोग से आयोजित किया जाता है।

पर्यावरण

'भारत में तेंदुओं की स्थिति' रिपोर्ट

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 'भारत में तेंदुओं की स्थिति' रिपोर्ट जारी की गई है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राज्य वन विभागों के सहयोग से तेंदुए की आबादी का अनुमान जारी किया है।
- 2018 से 2022 तक भारत में तेंदुओं की संख्या 1,000 से ज्यादा बढ़ी है।
- देश में तेंदुओं की संख्या 13,874 हो गई है, जबकि 2018 में यह संख्या 12,852 थी।
- तेंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश (3,907) में दर्ज की गई है।
- इसके बाद महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या 1985, कर्नाटक में 1,879 और तमिलनाडु में 1070 है।
- शिवालिक पहाड़ियों और सिंधु-गंगा के मैदानों में तेंदुओं की संख्या 2018 में 1,253 से घटकर 2022 में 1,109 हो गई है।
- शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में प्रति वर्ष 3.4% की गिरावट देखी गई।

ग्रेट बैरियर रीफ में 'मास कोरल ब्लीचिंग'

- ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ (Great Barrier Reef: GBR) पिछले 8 वर्षों में 5वीं बार बड़े स्तर पर कोरल ब्लीचिंग (Mass Coral Bleaching) हो रही है।
- ग्रेट बैरियर रीफ में बड़े स्तर पर कोरल ब्लीचिंग पहली बार 1998 में दर्ज की गयी थी। इसके बाद 2002, 2016, 2017, 2020, 2022 में और अब 2024 में फिर से दर्ज की गई है।
- यह ब्लीचिंग ग्लोबल वार्मिंग और अल नीनो जलवायु पैटर्न के कारण हो रही है।
- वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन ग्रेट बैरियर रीफ सहित दुनिया भर के महासागरों में मूंगे के अन्य चट्टानों यानी कोरल रीफ्स इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा है।

मूंगे/कोरल/प्रवाल

- मूंगे अकशेरुकी (invertebrate) जीव हैं जो कि निडारिया (Cnidaria) नामक रंगीन और आकर्षक जीवों के एक बड़े समूह से संबंधित हैं।
- प्रत्येक कोरल जीव को पॉलीप (polyp) कहा जाता है, और अधिकांश सैकड़ों से हजारों आनुवंशिक रूप से समान पॉलीप्स समूह में रहते हैं और एक 'कॉलोनी' बनाते हैं।
- कठोर मूंगे आसपास के समुद्री जल से प्रचुर मात्रा में कैल्शियम निकालते हैं और इसका उपयोग सुरक्षा और विकास के लिए एक कठोर संरचना बनाने में करते हैं। मूंगे यानी कोरल की इन संरचनाओं को ही मूंगा चट्टान या कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं।
- प्रवाल भित्तियाँ पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित संरचना हैं, और अंतरिक्ष से दिखाई देने वाली एकमात्र संरचना है।

कोरल ब्लीचिंग

- मूंगा यानी कोरल और शैवाल जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। कोरल का जूज़ैन्थिली (zooxanthellae) नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है जो उनके ऊतकों में रहते हैं।
- जब कोरल समुद्र के औसत तापमान से अधिक होने के कारण स्ट्रेस में आ जाते हैं, और अपने अंदर रहने वाले उन शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जो उन्हें अपना पोषक तत्व और अलग-अलग रंग प्रदान करते हैं।
- शैवाल के बिना कोरल अपने भोजन का प्रमुख स्रोत खो देते हैं और ये सफेद या बहुत पीला हो जाते हैं। इससे बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है।

कोरल ब्लीचिंग के कारण

- जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ा हुआ समुद्र का तापमान कोरल ब्लीचिंग का प्रमुख कारण है।

- वर्षा के बाद तटों से होने वाले जल के अपवाह और प्रदूषण महासागरों के जल में प्रवेश करके तटीय मूंगों को ब्लीच कर सकते हैं।
- जब तापमान अधिक होता है, तो उच्च सौर विकिरण उथले पानी के कोरल की ब्लीचिंग में योगदान देता है।

ग्रेट बैरियर रीफ

- ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल सिस्टम है।
- यह लगभग 2,300 किमी लंबा है, इटली के आकार से भी बड़े क्षेत्र को कवर करता है और लगभग 3,000 इंडिविजुअल रीफ से बना है।
- यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

'एथेनॉल 100' (E100) ऑटोमोटिव ईंधन लॉन्च

- केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 15 मार्च को नई दिल्ली में 'एथेनॉल 100' (Ethanol 100) ऑटोमोटिव ईंधन लॉन्च किया।
- इस पहल के तहत इथेनॉल 100 5 राज्यों - महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु में चुनिंदा 183 रिटेल पेट्रोल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा।

इथेनॉल 100

- इथेनॉल 100 गैसोलीन के लिए एक स्वच्छ, हरित विकल्प है।
- E100 ईंधन में 92-94% इथेनॉल, 4-5% मोटर स्पिरिट और 1.5% को-सॉल्वेंट हाइड्रोजन सैचुरेटेड अल्कोहल का मिश्रण होता है।
- यह ग्रीनहाउस गैसों और प्रदूषकों के कम उत्सर्जन करता है तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने और वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- इसमें जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने की क्षमता है।

एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड

- वडोदरा नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन नगर पालिका बॉन्ड जारी किया है।
- इसके तहत 1 अरब रुपये (\$12.07 मिलियन) जुटाए गए हैं।
- इसका उपयोग शहर में अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढाँचे हेतु किया जाएगा।
- इस बॉन्ड को AA+ रेटिंग दी गई है और क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव से हरित सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

पांडवुला गुट्टा

- पांडवुला गुट्टा को आधिकारिक तौर पर जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है। यह तेलंगाना में एकमात्र जियो हेरिटेज साइट है।
- यह हिमालय की पहाड़ियों से भी पुराना एक भू-वैज्ञानिक स्थल है।
- स्थान: जयशंकर भूपालपल्ली जिला (तेलंगाना)।
- इसे पहली बार वर्ष 1990 में खोजा गया था।
- पाण्डवुला गुट्टा अपनी शैल कला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
- रॉक कला चित्रों में बाइसन, मृग, बाघ, तेंदुआ आदि जैसे वन्यजीवों को दर्शाया गया है।
- इन चित्रों में स्वास्तिक चिह्न, वृत्त तथा वर्ग, चित्रित हथियार जैसे- धनुष, बाण, तलवार एवं भाला आदि शामिल हैं।

भू-विरासत स्थल (Geo-heritage sites)

- भू-विरासत स्थल दुर्लभ एवं अद्वितीय भू-वैज्ञानिक तथा भू-आकृति विज्ञान महत्त्व के स्थल हैं, जिनमें भू-आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान, पेट्रोलॉजिकल, जीवाश्म विज्ञान एवं स्ट्रेटिग्राफिक महत्त्व है, जिसमें गुफाएँ, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय रुचि की प्राकृतिक चट्टान-मूर्तियाँ शामिल हैं।
- भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI), भारत में विरासत स्थलों को मान्यता देता है एवं उनका संरक्षण करता है।

पहला स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर

- इसे लार्सन एंड टुब्रो (L&T) द्वारा गुजरात के हजीरा में हरित हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया गया है।
- यह इलेक्ट्रोलाइजर 1 मेगावाट (2 मेगावाट तक विस्तार योग्य) की रेटेड बिजली क्षमता वाला है तथा 200Nm³/घंटा (Normal Meter Cubed per Hour) हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है।
- हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से H₂O (पानी) को दो अणुओं - हाइड्रोजन और ऑक्सीजन - में विभाजित करके बनाया जाता है, जो एक विद्युत प्रक्रिया है।
- इस विधि के लिए एक इलेक्ट्रोलाइजर की आवश्यकता होती है, और यदि यह नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित है, तो बनने वाला उत्पाद हरित हाइड्रोजन है।
- लार्सन एंड टुब्रो की नव निगमित इकाई एलएंडटी इलेक्ट्रोलाइजर्स फ्रांस में मैकफी एनर्जी की तकनीक का उपयोग करके दबावयुक्त क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर्स के निर्माण पर केंद्रित है।

11

रिपोर्ट्स एवं इंडेक्स

मानव विकास सूचकांक (HDI) 2023/24: भारत 134वें स्थान पर

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023/24 प्रकाशित की, जिसका शीर्षक 'ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीडिमेजनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड' है।
- यह रिपोर्ट वर्ष 2022 के लिए जारी की गई है।
- इस सूचकांक में भारत 193 देशों में वर्ष 2022 में 134वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2021 में भारत 135वें स्थान पर था।
- भारत की मानव विकास सूचकांक (HDI) वैल्यू 2021 के 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गई। भारत, भूटान और बांग्लादेश के साथ मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देश में हैं।
- स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है।
- जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा 2021 में 67.2 वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई है।
- स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों (EYS) में समग्र वृद्धि (5.88%) दर्ज की गयी और यह 11.9 वर्ष से 12.6 वर्ष हो गई है, जिससे 18 स्थानों का सुधार हुआ है।
- भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) भी \$6,542 से बढ़कर \$6,951 हो गई।
- HDI एक समग्र सूचकांक है जिसकी गणना तीन मापदंडों के आधार पर की जाती है -
 - जीवन प्रत्याशा
 - स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष
 - औसत आय।
- पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के सहयोग से जारी किया गया था।
- इसके बाद प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा इसे जारी किया जाता है।

लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022

- लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 का भाग है।
- GII 2022 में 0.437 स्कोर के साथ भारत 193 देशों में 108वें स्थान पर है। (GII 2021 में भारत

का स्कोर 0.490 था और 191 देशों में से 122वें स्थान पर था।)

- GII तीन संकेतकों को आधार पर लैंगिक असमानता का मापन करता है।
- ये तीन संकेतक हैं: प्रजनन स्वास्थ्य (reproductive health), सशक्तिकरण और श्रम बाजार।
- GII स्कोर 0 से 1 के बीच दिया जाता है।
- कम GII स्कोर महिलाओं और पुरुषों के बीच कम असमानता को इंगित करता है, और अधिक स्कोर अधिक असमानता को इंगित करता है।
- पिछले 10 वर्षों में जीआईआई में भारत की रैंक में लगातार सुधार हुआ है।
- वर्ष 2014 में भारत की रैंक 127 थी।
- हालाँकि, भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर में सर्वाधिक अंतर है। इसमें महिलाओं (28.3%) और पुरुषों (76.1%) के बीच 47.8% का अंतर है।

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 (World Happiness Report 2024)

- संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क प्रतिवर्ष विश्व खुशहाली रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
- इस रिपोर्ट में 143 देशों में भारत 126वें स्थान पर है।
- फिनलैंड ने लगातार सातवीं बार पहला स्थान हासिल किया है।
- डेनमार्क और आइसलैंड ने क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है।
- अफगानिस्तान इस सूची में अंतिम स्थान पर है।
- भारत के पड़ोसी देशों में चीन 60वें, नेपाल 93वें, म्यांमार 118वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है।
- यह रिपोर्ट 6 कारकों पर आधारित है। ये कारक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, भरोसा, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति हैं।

वीमेन, बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024

- विश्व बैंक द्वारा 10वां संस्करण "वीमेन, बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024, (Women, Business and Law index 2024) जारी किया गया।

- यह पुरुषों और महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों और उनके लागू होने के बीच अंतर को दर्शाता है।
- इस सूचकांक में 190 देशों में से भारत का 113वाँ स्थान है।
- नई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं को पुरुषों को दिए गए 60% कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जो 2024 सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक औसत 64.2% से कम है।
- यह सूचकांक निम्नलिखित 10 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है;
- गतिशीलता (Mobility), कार्यस्थल (Workplace), वेतन (Pay), विवाह (Marriage), पितृत्व (Parenthood), उद्यमिता (Entrepreneurship), संपत्ति (Assets), पेंशन, सुरक्षा (Safety) और बाल देखभाल (Childcare)।
- इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 को अब तक का सबसे गर्म वर्ष बताया गया है।
- इसमें विभिन्न जलवायु संकेतकों का विवरण है, जिसमें ग्रीनहाउस गैस स्तर, सतह का तापमान, महासागर की गर्मी और अम्लता, समुद्र का जल स्तर बढ़ना, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का आवरण और ग्लेशियर का पिघलना शामिल है।
- लू, बाढ़, सूखा, जंगल की आग और तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने लाखों लोगों के रोजमर्रा के जीवन में गंभीर व्यवधान पैदा किया और इसके परिणामस्वरूप अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ।
- विश्व के ग्लेशियरों में 1950 के बाद से मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तरी अमेरिका और यूरोप में गंभीर पिघलाव के कारण बर्फ की सबसे बड़ी क्षति हुई है।
- 2022 में, 3 मुख्य ग्रीनहाउस गैसों - कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड - का स्तर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। यह प्रवृत्ति 2023 में भी जारी रही।

SIPRI रिपोर्ट 2024

- स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) द्वारा वैश्विक हथियारों की खरीद से संबंधित रिपोर्ट 11 मार्च 2024 को जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत पिछले 5 वर्षों (2019-2023) में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है।
- 2019-2023 की अवधि के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 9.8% थी।
- रूस और यूक्रेन की जंग के कारण यूरोप का हथियार आयात 2014-2018 की तुलना में 2019-2023 में दोगुना हो गया।
- दुनिया में हथियारों के 5 सबसे बड़े खरीदार: भारत (9.8%), सऊदी अरब (8.4%), कतर (7.6%), यूक्रेन (4.9%), पाकिस्तान (4.3%)
- हथियार निर्यात के संदर्भ में अमेरिका, फ्रांस और रूस का क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है।
- वर्ष 2014-18 और 2019-23 के बीच भारत का हथियार आयात 4.7% बढ़ा, जबकि 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत के आयात में 11% की गिरावट आई। इसका मुख्य कारण भारत के स्वदेशी हथियारों के उपयोग पर बल देना है।

वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा वैश्विक जलवायु रिपोर्ट 2023 जारी की गई।

विश्व जल विकास रिपोर्ट 2024 (World Water Development Report 2024)

- इस रिपोर्ट को यूएन-वॉटर की ओर से यूनेस्को द्वारा "जल संकट से विश्व शांति को खतरा" (Water crises threatening world peace) शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया।
- इस रिपोर्ट के अनुसार पानी को लेकर तनाव दुनिया भर में संघर्ष बढ़ सकता है।
- इसके अनुसार, आज भी 2.2 अरब लोग सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल तक पहुंच के बिना रहते हैं।
- वर्ष 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती है।
- 2002 और 2021 के बीच सूखे से 1.4 अरब से अधिक लोग प्रभावित हुए।
- 2022 तक, दुनिया की लगभग आधी आबादी ने वर्ष में किसी न किसी समय पानी की गंभीर कमी का सामना किया, जबकि एक चौथाई को अत्यधिक जल संकट का सामना करना पड़ा।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024

- यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) और मानव विकास संस्थान (IHD) द्वारा जारी की गई।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, बेरोजगार कार्यबल में भारत के युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% है।

- कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी 2000 में 35.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है।
- महामारी के दौरान देश के शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का स्तर अधिक था।
- 2000 और 2018 के बीच श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) और बेरोजगारी दर (UR) में गिरावट देखी गई। हालांकि, 2019 के बाद इनमें सुधार हुआ है।
- लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। 2000 के बाद नियमित काम की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी, जबकि 2018 के बाद इसमें गिरावट आई।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कम वेतन वाले अस्थायी आकस्मिक वेतन वाले काम और अनौपचारिक रोजगार में लगे हुए हैं।
- भारत में 2015 से 2022 तक टीबी की घटनाओं में 16% की कमी हुई, जो वैश्विक गिरावट 9% से अधिक है।
- इसके अलावा टीबी के कारण होने वाली मृत्यु दर में 18% की गिरावट हुई है।
- रिपोर्ट के अनुसार, मामलों (प्रत्येक वर्ष सामने आने वाले नए मामले) की दर 2015 में 237 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है।
- भारत में मृत्यु दर 2015 में 28 प्रति लाख जनसंख्या से गिरकर 2022 में 23 प्रति लाख जनसंख्या हो गई है।
- टीबी की गिरावट में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में दर्ज किए गए।
- 2023 में अधिसूचित कुल टीबी मामलों में से 60.7% पुरुष, 39.2% महिलाएं और 0.04% ट्रांसजेंडर थे।
- **नोट:** भारत ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 निर्धारित किया है।

हुरुन रिसर्च की सूची में मुंबई एशिया का नया अरबपति केंद्र बना

- हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार, मुंबई में एशिया के सर्वाधिक अरबपति है।
- मुंबई में अब 92 अरबपति हैं, जो बीजिंग के 91 अरबपतियों से अधिक है।
- चीन में भारत के 271 की तुलना में अधिक 814 अरबपति हैं।
- अरबपतियों के मामले में, मुंबई वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर न्यूयॉर्क (119 अरबपति) और लंदन (97 अरबपति) दूसरे स्थान पर है।

भारत टीबी रिपोर्ट 2024

- यह रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 मार्च को जारी की गई।

तपेदिक (टीबी)

- क्षय रोग या तपेदिक (टीबी) माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है।
- यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है।
- टीबी हवा के माध्यम से फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है।
- इसके सामान्य लक्षणों में लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना और वजन कम होना शामिल हैं।

12

प्रमुख दिवस एवं सप्ताह

विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस (World Civil Defence Day)

- यह प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य आत्म-सुरक्षा उपायों के लिए जनजागरूकता का प्रसार करना और आपात स्थिति में नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है।
- यह दिवस नागरिक सुरक्षा के महत्व और दुर्घटनाओं या आपदाओं की स्थिति से रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने और उसे रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वर्ष 2024 की थीम "नायकों का सम्मान करें और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा दें" ("Honour Heroes and Promote Safety Skills") है।

शून्य भेदभाव दिवस (Zero Discrimination Day)

- यह प्रतिवर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है।
- यह दिवस एचआईवी/एड्स से पीड़ित लोगों के अलावा महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव का मुकाबला करने के लिए मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में कानून के समक्ष और व्यवहार में समानता को बढ़ावा देना है।
- वर्ष 2024 की थीम 'हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना' ("To protect everyone's health, protect everyone's rights") है।
- यह थीम 2030 तक एड्स को खत्म करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानवाधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ संबंध बनाने पर जोर देती है।

विश्व वन्य जीव दिवस (World Wildlife Day)

- यह प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है।
- यह विश्व में तेजी से विलुप्त हो रहे पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
- इसके तहत लोगों को जंगली वनस्पतियों और जीवों (Wild Flora and Fauna) की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के सन्दर्भ में जागरूक किया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम "लोगों और ग्रह को जोड़ना: वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज" ("Connecting People and

Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation") है।

विश्व श्रवण दिवस (World Hearing Day)

- यह प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है
- यह बहरेपन को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में कान और सुनने के सन्दर्भ में देखभाल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम "Changing mindsets: Let's make ear and hearing care a reality for all" है।
- प्रत्येक वर्ष, WHO थीम तय करता है और साक्ष्य-आधारित सामग्री जैसे ब्रोशर, फ्लायर्स, पोस्टर, बैनर और इन्फोग्राफिक्स विकसित करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस

- यह प्रतिवर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम 'ESG उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व (Focus on Safety Leadership For ESG Excellence)' है।

निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- यह प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

- यह प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है।
- यह लैंगिक समानता, समाज में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार, महिलाओं को समान अधिकार के क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम - "Inspire Inclusive" है।
- वर्ष 1975 में, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता प्रदान की और इस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष भी घोषित किया गया।

55वाँ CISF स्थापना दिवस

- यह प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है।
- यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की स्थापना और इसके योगदान को चिह्नित करने के लिए मनाया जाता है।

- यह गृह मंत्रालय के शीर्ष स्तरीय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं।
- इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को भारतीय संसद द्वारा CISF अधिनियम के द्वारा की गई थी।
- CISF भारत की महत्वपूर्ण सरकारी और औद्योगिक भवनों के अलावा एयरपोर्ट्स को सुरक्षा प्रदान करता है।
- CISF की वर्तमान महानिदेशक नीना सिंह (पहली महिला DG) है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस (International Day of Women Judges)

- यह प्रतिवर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य न्यायपालिका में हर स्तर पर महिलाओं को पूर्ण व बराबरी का अवसर और बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों से इसका पालन करने का आह्वान करना है।
- भारत और विश्व में यह पहली बार 10 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहली बार मनाया गया।
- भारत के सर्वोच्च न्यायलय में वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी है।

धूम्रपान निषेध दिवस

- यह प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे बुधवार (इस बार 13 मार्च को) मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम 'बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना' है।

अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस

- यह प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम 'Playing with Math' है।

नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस (International Day of Action for Rivers)

- यह प्रतिवर्ष 14 मार्च को मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम "सभी के लिए जल (Water for All)" है।
- इसका उद्देश्य नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकना, नदियों की रक्षा के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक करना और उनके लिए बनाई गई नीतियों में सुधार करना है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (World Consumer Rights Day)

- यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें अपने अधिकारों की

रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- वर्ष 2024 की थीम 'उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई' ('Fair and responsible AI for consumers') है।

राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (National Vaccination Day)

- यह देश में प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है।
- इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन (Vaccination) के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा डॉक्टरों, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की उपलब्धियों को रेखांकित करना है।
- इस दिवस हेतु वर्ष 2024 की थीम "Vaccines Work for All" है।

वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस

- यह प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस (International Day of Happiness)

- यह प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है।
- यह दिवस खुशी के महत्व को के जीवन में मूलभूत आधार मानता है और व्यक्तियों, समूहों और सरकार को हैप्पीनेस और सकारात्मकता को प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- वर्ष 2024 के लिए थीम "Reconnecting for Happiness: Building Resilient Communities" है।

अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस: 21 मार्च

- अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है।
- इस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में नामित किया।
- अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024 का विषय 'वन और नवाचार: बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान' है।

नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

- यह प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है।
- वर्ष 2024 की थीम 'मान्यता, न्याय और विकास का एक दशक: अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक का क्रियान्वयन' है।

विश्व जल दिवस (World Water Day)

- यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य जल के महत्व और वैश्विक स्तर पर जल संकट के प्रभाव के सन्दर्भ में जागरूकता पैदा करना है।
- वर्ष 2024 की थीम 'शांति के लिए जल का लाभ उठाना' (Leveraging Water for Peace) है।

18वां अर्थ आँवर

- प्रत्येक वर्ष मार्च के चौथे/अंतिम शनिवार (4th Saturday of March) को 'अर्थ आँवर' (Earth Hour) मनाया जाता है।
- इस वर्ष 23 मार्च 2024 को पूरे विश्व में अर्थ आँवर मनाया गया था।
- इसका उद्देश्य ऊर्जा की बचत कर धरती को सुरक्षित रखना है।
- इस अवसर पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों के लोग 8:30 बजे से 9:30 बजे तक अपने घरों की लाइटें बंद करके ऊर्जा की बचत करते हैं।
- अर्थ आँवर 2024 का मुख्य विषय (थीम) 'Green, Low-carbon, High-quality Development' (हरित, निम्न-कार्बन, उच्च गुणवत्ता वाला विकास) है।

'शहीद दिवस'

- यह प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है।
- यह शहीदों के सम्मान और उनके बलिदान की याद में मनाया जाता है।
- इस दिन अर्थात् 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी।

गुड फ्राइडे

- यह इसाई धर्म का प्रमुख पर्व है। इस वर्ष यह 2024 में 29 मार्च को (शुक्रवार के दिन) मनाया जाएगा।
- इस दिन ईसा मसीह (प्रभु यीशु) को सूली में चढ़ाया गया था, इस कारण इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस (International Day of Zero Waste)

- यह प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य सभी प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और अपशिष्ट उत्पादन को कम करना है।
- यह दिवस संयुक्त राष्ट्र मानव बस्ती कार्यक्रम (UN Human Settlements Programme) (UN-Habitat) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme) (UNEP) द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है।

राजस्थान दिवस

- यह प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है।
- 30 मार्च 2024 को राजस्थान का 75वाँ दिवस मनाया गया।
- राजस्थान में एकीकरण के समय 19 रियासतें, नीमराणा, कुशलगढ़ तथा लावा तीन ठिकाने और अजमेर-मेरवाड़ा नामक एक केंद्र शासित प्रदेश था।
- 30 मार्च, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था।
- स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाता था।

13

सार : योजना - कुरुक्षेत्र

डिजिटल युग में पारंपरिक कला के स्वरूप

- किसी भी सभ्यता की कलात्मक परंपराएँ उसके सांस्कृतिक ढाँचे का निर्माण करती हैं। इसकी प्रगतिशील यात्रा विभिन्न कलाओं और उनके उत्कृष्ट रूपों द्वारा प्रदान की गई एक रूपरेखा के साथ बनाई गई है, एक ऐसा तथ्य जो बहुविविधता से जुड़े होने पर भी आज के डिजिटल युग में भी नहीं बदला है। आज की पीढ़ी ने बहुआयामी समीकरणों पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और संभवतः उन्हें हमारी कलात्मक परंपराओं को प्रौद्योगिकी के साथ विलय का रास्ता खोजे बिना संतुष्ट नहीं किया जा सकता है।

कला के डिजिटलीकरण के लाभ

- कलाकार को अत्यधिक विविधता और सहजता प्रदान करता है।
- विजुअलाइजेशन के साथ प्रयोग: यह विभिन्न विषयों के मिश्रण को सक्षम बनाता है, अद्वितीय और कल. पनाशील परिणाम प्राप्त करने के लिए घटकों के साथ अन्वेषण के विविध स्तर प्रदान करता है।
- कला की उत्कृष्ट कृतियों को बनाने और लोकप्रिय बनाने की अथाह गुंजाइश: इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया तत्वों, इंस्टॉलेशन और 2 डी (2 आयामी), 3 डी या 4 आयामी अनुमानों के साथ-साथ आभासी वास्तविकता (VU) या संवर्धित वास्तविकता (AU) जैसी अत्याधुनिक अवधारणाओं के माध्यम से।
- कलाकारों की यात्रा को मानव जाति के साथ समन्वित रखने में सहायक ।

प्रदर्शन कलाओं में उपयोग

- बाहरी भूमिका से परे डिजिटलीकरण अनुपयुक्त: प्रदर्शन की निपुणता जो भौतिक रूप से प्रदर्शित होती है, दर्शकों द्वारा आत्मसात की जाती है; इसलिए प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल प्रचार के लिए ही किया जा सकता है।

इंटरनेट का सकारात्मक उपयोग:

- किसी प्रदर्शन के प्रति बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए कई रास्ते प्रदान करता है
- कला-कलाकार-दर्शक तिकड़ी को करीब लाने के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरण प्रदान करता है।
- सोशल मीडिया और अन्य साइबर प्लेटफार्मों के माध्यम से एक कलात्मक प्रदर्शन को लोकप्रिय बनाने में मदद करता है।

- खत्म होते कला रूपों का पुनरुत्थान: समर्पित डिजिटल मीडिया अभियानों के माध्यम से बहुत से लुप्त हो रहे कला रूपों का पुनरुत्थान देखा गया है।

संरक्षण के लिए डिजिटल आयाम में परिवर्तन के सरोकार

- पारंपरिक लोक कला शैलियों में निहित सूक्ष्म, अमूर्त और सहज तत्वों के कमजोर पड़ने की सम्भावना
- लोक-कला शैलियों की शुद्धता और प्रामाणिकता को संरक्षित करने के महत्व पर जोर
- कला को केवल कम्प्यूटेशनल अल्गोरिद्म या गैर-मानवीय इलेक्ट्रॉनिक संगीत क्षेत्र तक सीमित डिजिटल टेम्पलेट्स तक सीमित करने का जोखिम
- कला शैलियों के लिए अल्गोरिद्म पूर्वाग्रह और बड़े पैमाने पर मानकीकरण का खतरा, जो अनजाने में लोक परंपराओं की स्थानीय विशिष्ट बारीकियों को मिटा सकता है।
- जैसे ही ये कला शैलियाँ डिजिटल क्षेत्र में आती हैं उनके एक सारकृत, उत्पादीकरण या उनकी मूल गहनता और अर्थ से रहित सतही स्वरूप धारण का जोखिम पैदा हो जाता है।
- पारंपरिक लोक कला अपने भीतर इतिहास, प्रती. कवाद और सांस्कृतिक महत्व के तत्वों को समाहित किये हुए हैं। ऐसे तत्व आसानी से बाइनरी भाषा या डिजिटल क्षेत्र के आभासी जगत में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। इन तत्वों की समग्रता को बनाए रखने के लिए नवाचार और संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है।
- डिजिटल अनुकूलन के बीच इन कला शैलियों का सार और मूलभूत तत्व कहीं लुप्त न हो जाए।

आगे की राह

1. जैसे-जैसे हम लोक कला के डिजिटल क्षेत्र में परिवर्तन ओर बढ़ रहे हैं हम उस दौराहे पर चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक विरासत एक दूसरे से मिलती हैं।
2. हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डिजिटल रूप से अनुकूलित कृतियाँ इन कला शैलियों के सांस्कृतिक मूलाधारों और विरासत के प्रति सत्यनिष्ठ बनी रहें।
3. नवाचार और संरक्षण के बीच एक सुविचारित संतुलन बनाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोक कला शैलियाँ अपने सार को खोये बिना डिजिटल युग में फूले फलें ।

भारत में लोकप्रिय संगीत

- लोकप्रिय संगीत एक ऐसी शैली है जो हाल ही में पारंपरिक संगीत से उभरी है। यह एक प्रकार का संगीत है जो जनमानस की इंद्रियों को आनंदित करता है। यह पूरी तरह से नियमों से रहित नहीं है, हालांकि लोकप्रिय संगीत में ये नियम शास्त्रीय संगीत की तुलना में कम कठोर हैं। यह पारंपरिक संगीत से बहुत अलग लगता है फिर भी इसकी जड़ें उस परंपरा में हैं जहाँ से इसका विकास हुआ है। इसके अस्तित्व का प्रमुख कारण वर्तमान संगीत में 'नवीनता' की आवश्यकता है। संगीत की 'ताजगी' या 'नयापन' लोकप्रिय संगीत का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसका उद्देश्य जनता को संतुष्ट करना है। लोकप्रिय संगीत धुन के साथ-साथ शब्दों को भी महत्व देता है, यह मनभावन और मनोरंजक होता है और इसलिए अमूर्त कला से कोसों दूर होता है।

लोकप्रिय संगीत के कुछ परिचित रूप जो वर्तमान में गाए जाते हैं

1. नाट्यसंगीत

- **लोकप्रिय संगीत की विविध प्रकृति:** इसके कई रूप हैं जैसे शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत, बैंड संगीत, भाव संगीत, अभंग, भजन और भक्ति गीत।
- **लोकप्रिय संगीत के उद्भव के कारण:** भारत में राजशाही समाप्त हो गई और शास्त्रीय संगीत और संगीतकारों को कोई संरक्षण नहीं मिला। संगीत और संगीतकार दोनों पूरी तरह से लोगों पर निर्भर हो गए, जिसके परिणामस्वरूप जनता को आकर्षित करने के लिए संगीत के प्रारूप में बदलाव किया गया।
- **थिएटर संगीत/नाट्यसंगीत:** एक पूर्ण ख्याल प्रस्तुति को प्रशंसा और मनोरंजन के लिए कोमल रचनाओं में समाहित किया गया था। इन रचनाओं को पार्ट थिएटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
- **नाट्य गीत:** मराठी पाठों के साथ रागों पर आधारित गीत और आलाप तथा लघु, द्रुत तान से अलंकृत। ताल 'गंधर्व ठेका' संगीत नाटक युग के दौरान एक नया आविष्कार किया गया था जिसका उपयोग नाट्य संगीत की संगत के लिए किया जाता था।
- **संगीत स्वयंवर:** विष्णुदास भावे का एक नाटक, 1843 में सांगली में मंचित होने वाला पहला संगीत नाटक था।

2. फिल्म संगीत

- **आगमन:** 1920 के दशक में पश्चिम से भारत में 'रिकॉर्डिंग तकनीक' के आने के बाद।

विशेषताएँ:

- शब्दों को काफी महत्व दिया जाता है।
- शास्त्रीय रागों पर आधारित। जैसे-बंदिशों
- इसमें मल्टी-ट्रैक रिकॉर्डिंग है जिसमें त्रुटियों की संभावना कम है, साथ ही यह एक समय में एक ट्रैक रिकॉर्ड करने की स्वतंत्रता देता है और ध्वनियों में विविधता को सक्षम बनाता है।

3. बैंड संगीत

- **विकास:** इसने भारत में 1980 के दशक में आकार लेना शुरू हुआ और 1990 के दशक तक पूरी तरह से स्थापित हो गया।

प्रचार और अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है कला

- **अभिव्यक्ति में सहायक :** जब व्यक्ति अपने विचारों को देखने की स्थिति पा लेता है और उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाता है तो उसे ऐसी भावनाओं के स्रोत का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। यह चिकित्सा की दिशा में पहला चरण है।
- **विश्वास जमाना और नियंत्रण प्राप्त करना:** कला कभी 'गलत' नहीं होती। कला के इस स्वाभाविक गुण, स्वभाव से ही कलाकार में स्थिति पर नियंत्रण पा लेने का भाव जगता है और उसमें इच्छित विकल्प चुनने की क्षमता - योग्यता भी आ जाती है।
- **किसी बच्चे की बौद्धिक निपुणता और ग्राह्य क्षमता में सुधार:** कला वास्तव में क्रिया है जिसे भौतिक रूप से किया जाता है। यह संचालन, अर्थात् व्यक्ति का क्रियाकलाप और उसका परिणाम (जो कभी गलत नहीं होता) ही ग्रहण करने की क्षमता और मस्तिष्क संचालन में विकास को जन्म देता है तथा भावनाओं का नियमन भी करता है। फिर, कला में लगने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क शांत और लक्ष्य केंद्रित होना जरूरी है और यही संज्ञान क्षमता के विकास की पूर्व शर्त भी है।
- **सृजनात्मक अभिव्यक्ति:** कला सदा ही रचनात्मक और सकारात्मक होती है तथा विनाश और अडचन / बंधन की विरोधी होती है। यह आत्माभिव्यक्ति जगाकर उसे सहेजती है जो सृजनशीलता को जन्म देती है।

भारत की कलात्मक विरासत का संरक्षण

राष्ट्रीय संग्रहालय: भारत की बहुमुखी विरासत का संरक्षक

- **विवरण:** भारत की कला और कलाकृतियों का प्रमुख भंडार, जिसका इतिहास 5,000 वर्षों से भी अधिक है।

- **महत्व:** मूर्तियों, चित्रों, पांडुलिपियों, सिक्कों, हथियारों और वस्त्रों सहित 210,000 से अधिक वस्तुओं के संग्रह के साथ, यह भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय संग्रहालय में जीर्णोद्धार

- **संरक्षण प्रयोगशाला:** 1950 में संग्रहालय के साथ स्थापित संस्था सावधानीपूर्वक पुनरुद्धार प्रयासों के माध्यम से इन खजानों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- **वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग:** सूक्ष्म अध्ययन और एक्स-रे प्रतिदीप्ति जैसी वैज्ञानिक तकनीक, विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक कलाकृतियों के संरक्षण में सहायता करती हैं।

राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी: समकालीन कलात्मक विरासत का संरक्षक

- **स्थापना:** 1954
- **उद्देश्य:** आधुनिक भारतीय कला को बढ़ावा देने और संरक्षित करना

विशेषताएँ:

- पुनर्स्थापना से पहले और बाद की कलाकृतियों का दस्तावेजीकरण करने वाली तस्वीरें, प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करती हैं; आगे के शोध और भविष्य के संदर्भ के लिए सावधानीपूर्वक बनाए रखी जाती हैं।
- **कार्य:** राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी भारत के कलात्मक खजाने को संरक्षित करने आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी दीर्घायु और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कठोर संरक्षण प्रथाओं को लागू करने की राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभाते हैं।

कुरुक्षेत्र

डिजिटल और नवीन कृषि तकनीकें-

- कृषि क्षेत्र में आई कई क्रांतियों के चलते इस क्षेत्र में दक्षता, उत्पादन और लाभप्रदता अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई है। वर्तमान दशक नवीनतम परिवर्तन के रूप में 'डिजिटल कृषि क्रांति' के उद्भव का गवाह बन रहा है, जो कृषि और खाद्य क्षेत्र की कई चुनौतियों जैसे बढ़ती आबादी के कारण भोजन की मांग में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों जैसे उपजाऊ भूमि और ताजा पानी की सीमित होती उपलब्धता का समाधान करने के लिए तैयार है।
- 2030 तक 'शून्य भूख वाली दुनिया' के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मौजूदा

कृषि खाद्य प्रणाली को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, कुशल और अनुकूल प्रणाली में बदलना होगा। इस हिसाब से, डिजिटल कृषि में कृषि उत्पादन, लागत दक्षता और बाजार की संभावनाओं का विस्तार करके आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता है। यह अधिक संपर्क और समावेशन को प्रोत्साहित करके समाज और संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, डिजिटल कृषि संसाधन उपयोग में सुधार और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बढ़ावा देकर पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है।

नवीन कृषि पद्धतियाँ

1. प्रिसिजन फार्मिंग

- **अर्थ:** प्रबंधन दृष्टिकोण जिसमें अस्थायी, स्थानिक और व्यक्तिगत डेटा का संग्रह, प्रसंस्करण और विश्लेषण शामिल है। कृषि उत्पादन में संसाधन उपयोग दक्षता, उत्पादकता, गुणवत्ता, लाभप्रदता और सततता बढ़ाने के लिए इस डेटा को अनुमानित परिवर्तनशीलता पर आधारित प्रबंधन निर्णयों में सहायता के लिए अन्य जानकारी के साथ एकीकृत किया जाता है।
- **प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ:** ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), सेंसर, ड्रोन और डेटा विश्लेषण
- **लाभ:** प्रिसिजन फार्मिंग में किसान पानी, उर्वरक और कीटनाशकों जैसे इनपुट को सटीक रूप से विनियमित कर सकते हैं जिससे उच्च दक्षता के साथ-साथ बर्बादी भी कम करने में मदद मिलती है।

2. स्मार्ट खेती

- **अर्थ:** IOT, रोबोटिक्स, ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के साथ खेतों का प्रबंधन करने से संबद्ध जिससे उत्पादन के लिए आवश्यक मानव श्रम का अनुकूलन करते हुए उत्पादों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके।

अनुप्रयोग:

- एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के जरिए किसान अपने व्यवसाय के कई हिस्सों की दूर से निगरानी और नियंत्रण कर सकते हैं।
- आधुनिक कृषि तेजी से स्वचालित मशीनरी, जैसे सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर और रोबोटिक हार्वेस्टर पर निर्भर होती जा रही है।
- **लाभ:** ये प्रौद्योगिकियाँ किसानों के शारीरिक श्रम को कम करती हैं जबकि रोपण, कटाई और खरपतवार नियंत्रण जैसे कार्यों में सटीकता और दक्षता बढ़ती है।

3. वर्टिकल फार्मिंग और नियंत्रित पर्यावरण कृषि

- **विवरण:** इन नवीन तरीकों में खड़ी परतों में या ग्रीनहाउस या हाइड्रोपोनिक सिस्टम जैसी विनियमित परिस्थितियों में फसलें उगाना शामिल है।

लाभ:

- पारंपरिक खेती कार्यों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए भूमि उपयोग दक्षता को अधिकतम करती है।
- किसान कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, जलवायु नियंत्रण और उर्वरक समाधानों का उपयोग करके पूरे वर्ष पौधों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियाँ स्थापित कर सकते हैं।
- इससे न केवल कृषि उपज बढ़ती है बल्कि जलवायु की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में फसल उगाने में भी मदद मिलती है।

4. कृषि में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

- **प्रयोग:** किसान, थोक व्यापारी और उपभोक्ता सभी कृषि उत्पाद लेन-देन और गतिविधियों का सुरक्षित और अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग कर सकते हैं।
- **लाभ:** यह खाद्य उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, धोखाधड़ी के खतरे को कम करता है, और उपभोक्ताओं को अपने खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति और गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने की अनुमति देता है।

डिजिटल खेती तकनीक**1. प्रिसिजन फार्मिंग में प्रौद्योगिकियाँ:**

- **GPS तकनीक:** यह किसानों को अपने खेतों की सटीक योजना बनाने में सक्षम बनाता है, जिससे मशीनों के लिए नेविगेट करना और संसाधनों को सही स्थानों पर लागू करना आसान हो जाता है।
- **अतिरिक्त प्रौद्योगिकियाँ:** क्षेत्र आधारित सेंसर के उपयोग से फसल स्वास्थ्य, पोषक तत्व स्तर और मिट्टी की नमी के बारे में जानकारी वास्तविक समय में मिल जाती है।
- **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) उपकरण:** मौसम स्टेशन और पर्यावरण सेंसर

2. ड्रोन

- **खेतों की उच्च - रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरें:** किसान इन हवाई तस्वीरों के माध्यम से कीट संक्रमण, पोषक तत्वों की कमी या पानी के तनाव सहित समस्या क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं।

3. स्वचालित प्रौद्योगिकी

- **GPS और सेंसर तकनीक वाले स्वचालित उपकरण:** यह रोपण, कटाई और जुताई (स्वायत्त ट्रैक्टर और हार्वेस्टर) सहित संचालन कर सकते हैं।
- **लाभ:** यह कृषि कार्यों में सटीकता की गारंटी देता है और साथ ही, श्रम व्यय को भी कम करता है।

4. परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी (VRT)

- **विवरण:** यह एक क्षेत्र में विभिन्न दरों पर पानी, शाकनाशी और उर्वरक जैसे इनपुट के अनुप्रयोग को सक्षम बनाता है।
- **लाभ:** यह विधि सुनिश्चित करती है कि फसल और मिट्टी की स्थितियों की स्थानिक परिवर्तनशीलता पर विचार करके संसाधनों को ठीक उसी जगह और जब जरूरत हो, लागू किया जाए।

5. स्मार्ट सिंचाई प्रणाली

- **सॉयल मॉयस्चर सेंसर:** फसलों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा और समय की गणना करने के लिए
- **लाभ:** ऐसा करने से अत्यधिक सिंचाई से बचा जा सकता है, जल आपूर्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है और फसल के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है।
- स्वचालित सिंचाई प्रणालियों का रिमोट नियंत्रण वेब या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संभव है।

6. डेटा संचालित फार्म प्रबंधन

- **विवरण:** ये प्रौद्योगिकियाँ अक्सर फसल स्वास्थ्य, मिट्टी की स्थिति और मौसम पूर्वानुमान जैसे कई स्रोतों से जानकारी को जोड़ती हैं।
- **लाभ:** फार्म प्रबंधन सॉफ्टवेयर के उपयोग से किसान विश्वास के साथ अपने रोपण, पानी और कटाई कार्यों की योजना बना सकते हैं।

7. कृषि कार्यों के लिए रोबोट

- **लाभ:** ये स्वायत्त वाहन खेतों में जा सकते हैं, प्रभावी ढंग से फसलों की कटाई कर सकते हैं या खरपतवारों का पता लगा सकते हैं और उभार कर सकते हैं।
- रोबोटिक्स दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ शारीरिक श्रम की आवश्यकता को कम करता है।

8. मशीन लर्निंग

- **उद्देश्य:** फसल की पैदावार, बीमारी के प्रकोप और बाजार के रुझान का पूर्वानुमान
- **लाभ:** किसान अब सक्रिय निर्णय ले सकते हैं और इन पूर्वानुमानित विश्लेषणों के माध्यम से पूर्वानुमानित स्थितियों के जवाब में अपनी योजनाओं को संशोधित कर सकते हैं।

9. ब्लॉकचेन

- **लाभ:** एक ब्लॉकचेन कृषि आपूर्ति श्रृंखला के रोपण से लेकर वितरण तक के हर चरण को रिकॉर्ड कर सकता है।
- पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के अलावा, यह कृषि उत्पादों की उत्पत्ति और गुणवत्ता में उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ावा देता है।

10. डिजिटल ट्विन

- **विवरण:** ये भौतिक खेतों की आभासी प्रतिकृतियाँ बनाते हैं।
- **लाभ:** यह किसानों को, वास्तविक दुनिया में परिवर्तन लागू करने से पहले, विभिन्न परिदृश्यों का अनुकरण और अनुकूलन करने की अनुमति देता है।

डिजिटल परिवर्तन के लिए कारक

- 'सक्षमकर्ता' (एनबलर्स) जो प्रौद्योगिकियों को आसानी से अपनाने में योगदान करती हैं।
- डिजिटल कौशल
- कृषि उद्यमशीलता और नवाचार संस्कृति
- प्रतिभा विकास और स्टार्टअप इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर कार्यक्रम
- डिजिटलीकरण
- किसानों के बीच डिजिटल साक्षरता
- डिजिटल पहुँच में लैंगिक असमानता
- स्थानीय संवेदनशीलता को समझना
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना
- बुनियादी ढाँचे में सुधार करने वाले एफपीओ को बढ़ावा देना
- छोटे किसानों के लिए सब्सिडी की पहुँच

आगे की राह

- **राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई रणनीति:** यह प्रौद्योगिकी के आर्थिक और सामाजिक लाभों को अनलॉक करना चाहती है।
- **कृषि 4.0:** इसका मतलब यह है कि कृषि संचालन के सभी पहलुओं में डिजिटल जानकारी होनी चाहिए, आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं जैसे बाहरी पक्षों के साथ इलेक्ट्रॉनिक संपर्क मौजूद होना चाहिए और स्वचालित डेटा स्थानांतरण, प्रसंस्करण और विश्लेषण

प्रक्रियाएँ आदर्श होनी चाहिए।

- **वेब-आधारित टूल:** इस का उपयोग करने से भारी मात्रा में डेटा का प्रबंधन आसान हो सकता है और फार्म तथा बाहरी भागीदारों के बीच संचार में सुधार हो सकता है।
- **कृषि 5.0:** इस की परिकल्पना रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विभिन्न रूपों पर केन्द्रित करने के लिए की गई है।
- **एफपीओ :** एफपीओ प्रौद्योगिकी को अधिक सुलभ और सस्ता बनाते हैं, जिससे इसमें शामिल सभी पक्षों को मदद मिलती है।

बाँस की खेती: उगाने के तरीके और लाभ

- बाँस न केवल कृषकों, शिल्पकारों एवं उद्यमियों के लिए फायदे का सौदा है बल्कि पर्यावरण अनुकूल होने के कारण यह सम्पूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। बाँस एक अद्भुत पौधा है जिसका हर भाग उपयोगी है। यही नहीं बाँस की खेती किसानों के लिए भी लाभ का सौदा है।

जलवायु आवश्यकता

- तापमान सीमा : 7°C - 40°C
- आदर्श वार्षिक वर्षा: 1200 मिमी - 4000 मिमी
- मृदा: अच्छी जल निकासी वाली, मोटी, दानेदार और पथरीली।

विशेषताएं:

- **तापमान-** अनुकूलन योग्य, -5 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान और 45 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों के तापमान के साथ पाले को सहन करता है।
- 750 से 4,000 मिमी तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उग सकता है।
- मृदा का pH- 5.0 से 6.5

अन्य पैरामीटर:

- समृद्ध जैविक पदार्थ
- मध्यम नमी की मात्रा
- मध्यम आर्द्रता
- प्रमुख पोषक तत्व: नाइट्रोजन, P₂O₅, K₂O, CaO और SiO₂

बाँस का उपयोग

- **निर्माण:** ऐसे वस्त्रों के उत्पादन के लिए उपयोग जो ठंडे और सांस लेने योग्य हों।
- **औषधि के रूप में बाँस:** इसका उपयोग सर्दी, फ्लू और अन्य सामान्य बीमारियों जैसे मतली और नाक बंद होने के इलाज में किया जाता है।

- बाँस के पौधे के खाद्य घटकों से मरीजों का इलाज किया जाता है।
- **बाँस के बर्तन:**
उचित मूल्य और लंबे समय तक चलने वाला।
खाना पकाने की पुरानी और पारंपरिक विधि।
डिशवॉशर-सुरक्षित बर्तन
- **संगीत वाद्ययंत्र:** जाइलोफोन, बांसुरी, ड्रम, इत्यादि।

भारत में बाँस का आर्थिक योगदान

- **2020:** औद्योगिक सामान क्षेत्र में बाँस की 35% बाजार हिस्सेदारी थी।
- **2021:** अनुमानित 57.86 बिलियन डॉलर बाँस पर लगाये गए जिससे इसका शेयर बढ़ गया।
- **सबसे बड़ा योगदान:** कुल राजस्व में 75% पर, एशिया-प्रशांत क्षेत्र (भारत, चीन, वियतनाम और म्यांमार) ने सबसे बड़ा योगदान दिया।

पोषण एवं आजीविका सुरक्षा के लिए मधुमक्खी पालन

- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन का प्रचलन बढ़ता जा रहा चूँकि मधुमक्खी पालन मुनाफा देने वाले व्यवसायों में से एक माना जाता है। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज कई किसान खेती के साथ-साथ मधुमक्खी पालन करके फसलों की अच्छी पैदावार के साथ शहद उत्पादन से बेहतर कमाई कर रहे हैं। बदलते परिदृश्य में मधुमक्खी पालन किसानों की आय सृजन का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय हो सकता है।

मधुमक्खी पालन

- **अर्थ:** मधुमक्खियों का विज्ञान और संस्कृति तथा उनका प्रबंधन जिसमें मनुष्यों द्वारा, आमतौर पर छते में, शहद मधुमक्खी कालोनियों के जानबूझकर रखरखाव की प्रथा।
- **उद्देश्य:** शहद, मोम, पराग, प्रोपेलिस, रॉयल जैली व मौनविष प्राप्त करना
- **मधुमक्खी पालन गृह:** वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है।

भारत में मधुमक्खी पालन

- भारत में मधुमक्खी की चार प्रमुख प्रजातियाँ निवास करती हैं:
- 2 पालतू प्रजातियाँ, अर्थात् एपि सेराना (भारतीय या एशियाई शहद मधुमक्खी) और ए मेलिफेरा (यूरोपीय शहद मधुमक्खी)
- 2 जंगली प्रजातियाँ, अर्थात् ए. डोरसाटा (रॉक शहद मधुमक्खी) और ए. फ्लोरिया (बौनी मधुमक्खी)।
- **ए. सेराना:** तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,

तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर पूर्वी राज्यों में इन्हें पाला जाता है, लेकिन इससे शहद उत्पादन भारत में उत्पादित कुल शहद का मुश्किल से 5-10% है।

- **ए. मेलिफेरा लिगस्टिका/इतालवी मधुमक्खी:** सरसों, सूरजमुखी, नीलगिरी, कुसुम आदि समृद्ध वनस्पतियों के कारण उत्तर भारत में अधिक पाई जाती हैं। ये प्रति वर्ष प्रति कॉलोनी 50 से 60 किलोग्राम शहद का उत्पादन करती हैं।
- **प्रमुख उत्पादन:** भारत में उत्पादित शहद का लगभग 70-75% ए मेलिफेरा से होता है।
- **ए. डोरसाटा/रॉक मधुमक्खी:** यह भारत में उत्पादित कुल शहद का लगभग 20% योगदान देती है।

राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM)

- **विवरण:** सरकार ने तीन वर्षों (2020-21 से 2022-23) के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी)

उद्देश्य:

- 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन का समग्र प्रचार और विकास
- कृषि एवं गैर-कृषि परिवारों की आय एवं रोजगार सृजन के लिए मधुमक्खी पालन उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देना
- कृषि/बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना
- एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (IBDC)/COI, शहद परीक्षण प्रयोगशालाएं, मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशालाएं, कस्टम हायरिंग केंद्र, एपी-थेरेपी केंद्र, न्यूक्लियस स्टॉक, मधुमक्खी प्रजनक आदि की स्थापना सहित बुनियादी सुविधाएँ विकसित करना।
- मधुमक्खी पालन के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना
- मिनी मिशन-I के तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी उत्पादों की प्राप्ति के बाद प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- **निर्यात:** भारत दुनिया के प्रमुख शहद निर्यातक देशों में से एक है और वर्ष 2022-23 के दौरान दुनिया को 1,622.77 करोड़ रुपये मूल्य का 79,929.17 मीट्रिक टन प्राकृतिक शहद निर्यात किया है (घरेलू उत्पादन का 50%)।
- **भारतीय शहद के प्रमुख बाजार:** संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, कनाडा, आदि (कुल मिलाकर 83 देशों को निर्यात)।

समस्याएँ

- मधुमक्खी पालकों को शहद के बक्से नहीं मिल पाते; शहद के विपणन की कोई सुविधा नहीं है; और मधुमक्खी पालन प्रबंधन में अपर्याप्त निर्देश।

मधुमक्खी पालन की संभावनाएँ

- **भौगोलिक विविधता:** कृषि क्षेत्रों के अलावा, सदाबहार उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन मधुमक्खियों को भोजन प्रदान करते हैं। यह आज की 3.4 मिलियन मधुमक्खी कॉलोनियों की तुलना में लगभग 200 मिलियन मधुमक्खी कॉलोनियों की क्षमता प्रदान करते हैं।
- **आनुवंशिक विविधता:** दुनिया में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मधुमक्खी की केवल सात प्रजातियाँ हैं, लेकिन उनमें से पाँच भारत में मौजूद हैं। यानि रॉक मधुमक्खी, इंडियन हाइव मधुमक्खी। इसलिए, मधुमक्खी पालन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के प्रति संवेदनशील होता है।
- **कृषि अर्थव्यवस्था:** नई कृषि उत्पादन रणनीति के रूप में मधुमक्खी परागण की भारत जैसे कृषि प्रधान देश में अपार संभावनाएँ हैं। यदि मधुमक्खियों को कृषि में शामिल किया जाए, तो परागण अच्छी तरह से प्रबंधित होता है और फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- **खाद्य प्रसंस्करण पर जोर:** सरकार ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है यानी पीएम संपदा जैसे नीतिगत उपाय। शहद एक उच्च मूल्य वाला उत्पाद है और इसलिए यह सरकारी रणनीतियों के साथ आसानी से जुड़ जाता है।
- **बढ़ती औद्योगिक माँग:** शहद भारत में आयुर्वेद और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों में एक प्रमुख घटक है। ऐसा माना जाता है कि यह कई और विशिष्ट बीमारियों के उपचार में सहायता करता है। इसलिए, आयुष और फार्मास्युटिकल क्षेत्रों की वृद्धि से भारत में औद्योगिक कच्चे माल के रूप में शहद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- **बढ़ता घरेलू बाजार:** खान-पान की बदलती आदतों और स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों तथा कृत्रिम मिठास के स्वस्थ विकल्पों के प्रति उपभोक्ताओं के बढ़ते रुझान के परिणामस्वरूप, आने वाले वर्षों में शहद की मांग बढ़ने की उम्मीद है। कोविड-19 संक्रमण के खतरे ने इसके एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण लोगों को इसका अधिक सेवन करने के लिए प्रेरित किया है।

मधुमक्खी पालन से संभावित उत्पाद (मधुमक्खी फार्म के उप-उत्पाद)

- **शहद:** यह मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से उत्पन्न एक चिपचिपा तरल पदार्थ है। यह शर्करा, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, एसिड और खनिज युक्त एक संपूर्ण भोजन है और इसका उपयोग उच्च ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। यह कई आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के लिए एक उपयोगी वाहक है।
- **रॉयल जेली:** यह मधुमक्खियों से स्रावित होता है और इसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, लोहा, सल्फर, तांबा और सिलिकॉन जैसे खनिज होते हैं। इसका उपयोग एक सामान्य टॉनिक और उत्तेजक के रूप में किया जाता है जो थकान, सीखने की क्षमता और स्मृति, भूख और सामान्य स्वास्थ्य सुधार के प्रतिरोध में सुधार करता है।
- **मधुमोम:** मधुमक्खी का मोम एक तरल पदार्थ के रूप में स्रावित होता है लेकिन हवा के संपर्क में आने पर जम जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः मोमबत्ती उद्योग में किया जाता है। अन्य प्रमुख स्थान जहाँ मधुमक्खी का मोम महत्वपूर्ण है, वे क्रीम, मलहम, कैप्सूल, डिओडोरेंट, वार्निश, जूता पॉलिश आदि बनाने के लिए हैं।
- **प्रोपोलिस:** यह मधुमक्खियों द्वारा पौधों से एकत्र किए गए मोम और रेजिन का मिश्रण है। यह चिपचिपा होता है और इसका उपयोग मलहम तैयार करने के लिए भी किया जाता है जो कटौती, घावों, त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटिक उपचार आदि का इलाज करता है।
- **मधुमक्खी का जहर:** इसमें हिस्टामाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एपामाइन आदि जैसे सक्रिय रसायन होते हैं। इसे गठिया से पीड़ित रोगियों में इंजेक्ट किया जाता है। यह नसों का दर्द, एंडो आर्थराइटिस, नेक्रोसिस आदि को ठीक करने में भी मदद करता है।
- **पराग:** यह फूल पराग, अमृत, एंजाइम, शहद, मोम और मधुमक्खी स्राव का मिश्रण है। यह पोषक तत्वों, अमीनो एसिड, विटामिन, लिपिड और कई सक्रिय पदार्थों से भरा हुआ है। इसलिए, इसे एक औषधि के रूप में पहचाना जाने लगा है।

भारत में फूलों की खेती: आय का नया साधन

- भारत में फूलों की खेती किसानों के लिए आय सृजन के नए आयाम के रूप में उभरी है। देश के पहाड़ी राज्यों में फूलों का बाजार बिखरा हुआ है और व्यवस्थित रूप में नहीं है। फूलों वाली फसलों की निर्यात क्षमता बहुत अधिक है और 70% निर्यात में सूखे फूलों के

उत्पाद शामिल हैं। पैकेजिंग मानकों के साथ फूलों की ग्रेडिंग पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। आजकल ई-कॉमर्स में इस उद्योग के विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है।

भारत में व्यावसायिक सफलता में योगदान देने वाले प्रमुख कारक

- **स्थानीय अनुकूलन और खेती तकनीक:** तापमान, आर्द्रता और प्रकाश के स्तर को अनुकूलित करने में अनुसंधान और प्रयोग ने उन प्रथाओं के विकास को जन्म दिया है जो विशिष्ट आर्किड प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों की नकल करते हैं।
- **सांस्कृतिक महत्व और पारंपरिक उपयोग:** आर्किड, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित हैं, विभिन्न परंपराओं और उत्सवों में महत्वपूर्ण मूल्य रखते हैं। सरकारी पहल और सब्सिडी: वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और बुनियादी ढाँचा विकास इन पहलों के प्रमुख घटक हैं।
- **निर्यात के अवसर:** आर्किड और आर्किड उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा भारत में आर्किड की खेती का विस्तार हुआ है। भारतीय आर्किड की अंतर्राष्ट्रीय अपील ने उत्पादकों के लिए वैश्विक बाजार तलाशने के रास्ते खोल दिए हैं।
- **प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान सहयोग:** ग्रीनहाउस खेती और टिशू कल्चर तकनीकों सहित प्रौद्योगिकी में प्रगति ने भारत में आर्किड खेती की व्यावसायिक सफलता में योगदान दिया है।

भारतीय संदर्भ में चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

- **अवसंरचना एवं प्रौद्योगिकी अंतर:** कई उत्पादकों, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, आधुनिक ग्रीनहाउस सुविधाओं और उन्नत खेती प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का अभाव है।
- **कीट और रोग प्रबंधन:** आर्किड विभिन्न कीटों और बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं जो फसल की उपज और गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ और स्थिरता:** आर्किड फूलों की खेती से जुड़ी गहन खेती प्रथाएँ पर्यावरणीय स्थिरता के बारे में चिंताएँ बढ़ाती हैं। पानी के उपयोग, रासायनिक इनपुट और ऊर्जा खपत जैसे मुद्दों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
- **कौशल विकास और प्रशिक्षण:** आर्किड की खेती की सफलता के लिए अनुभवी उत्पादकों से लेकर उन्नत खेती तकनीकों में कुशल तकनीशियनों तक कुशल जनशक्ति की आवश्यकता होती है।

- **बाजार संतृप्ति और विविधीकरण:** आर्किड उद्योग की तीव्र वृद्धि से बाजार संतृप्ति हो सकती है, जिससे विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया जा सकता है।
- **वैश्विक सहयोग और अनुसंधान:** ज्ञान का आदान-प्रदान, सहयोगात्मक प्रजनन कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच भारतीय आर्किड की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। वैश्विक आर्किड संगठनों और अनुसंधान संस्थानों के साथ संबंध मजबूत करने से वैश्विक स्तर पर उद्योग के विकास में योगदान मिल सकता है।
- **सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना:** सतत और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं पर बढ़ते जोर के साथ, भारत में आर्किड उद्योग को सक्रिय रूप से पर्यावरण के लिए जिम्मेदार खेती के तरीकों को अपनाना और बढ़ावा देना चाहिए।

जैविक खेती: वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएँ

- भारत में कृषि परिदृश्य को बदलने की महत्वपूर्ण क्षमता के साथ, जैविक खेती एक बढ़ते आंदोलन के रूप में विकसित हुई है। पर्यावरणीय स्थिरता, स्वस्थ उपज और मिट्टी के स्वास्थ्य के लाभ जैविक खेती को किसानों और उपभोक्ताओं के लिए एक व्यवहार्य और आकर्षक विकल्प बनाते हैं। प्रौद्योगिकी समावेशन, अनुसंधान, नीति समर्थन और उपभोक्ता जागरूकता देश में जैविक खेती की पूरी क्षमता को साकार करने में सहायक हैं। निसंदेह किसानों, नीति निर्माताओं और जनता के टोस प्रयासों से जैविक खेती भारतीय कृषि के लिए एक हरित और अधिक सतत भविष्य में योगदान दे सकती है।

जैविक खेती

- **विवरण:** इसमें सतत और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियाँ शामिल हैं जो सिंथेटिक कीटनाशकों, उर्वरकों और आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों से बचती हैं।
- **सिद्धांत:** यह प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित किए बिना और खेतों पर काम करने वाले और उपज का उपयोग करने वाले लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य खतरा पैदा किए बिना उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने पर निर्भर रहता है।
- **पर्यावरण- अनुकूल पद्धतियाँ:** रणनीतिक फसल चक्र, ट्रैप फसलें, जैव-कीटनाशकों का उपयोग, कीटों का जैविक नियंत्रण, यांत्रिक ट्रैप आदि।

जैविक खेती की आवश्यकता एवं लाभ

- जैव विविधता को बढ़ावा देता है।
- मिट्टी के स्वास्थ्य का संरक्षण करता है।

- सिंथेटिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग से परहेज करके जल प्रदूषण को कम करता है
- कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है
- एक ओर इनपुट लागत को कम करके और साथ ही दूसरी ओर बेहतर बाजार पहुंच बनाकर किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है।
- रासायनिक खाद पर कम निर्भरता से कृषक समुदाय के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है।
- जैविक उत्पाद रासायनिक अवशेषों से मुक्त होते हैं और उनमें अक्सर उच्च पोषण मूल्य होता है, जो उपभोक्ताओं के बेहतर समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है।
- प्राकृतिक खाद और टिकाऊ तरीकों पर जोर देता है जिसके परिणामस्वरूप पोषक तत्वों से भरपूर फसलें होती हैं।
- जैविक उत्पादों में आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों की अनुपस्थिति प्राकृतिक और असंशोधित खाद्य उत्पादों के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। किसानों और उपभोक्ताओं की भलाई का ध्यान रखता है।
- एक लचीले और सतत कृषि भविष्य का समर्थन करते हुए, भारत के समग्र पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देता है।
- जैविक उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी संभावनाएँ हैं, जिससे देश के कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- भोजन में रासायनिक अवशेषों से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को संबोधित करता है, जिससे संभावित स्वास्थ्य देखभाल लागत में बचत होती है।
- एक समग्र समाधान प्रस्तुत करता है जो पर्यावरण, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य हितों में सामंजस्य स्थापित करता है।

जैविक उत्पादन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPOP)

- **लॉन्च:** 2001
- **महत्व:** इसने देश में जैविक कृषि क्षेत्र के व्यवस्थित विकास की नींव रखी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा।

राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र

- **स्थापना:** 2004
- **परिचय:** देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल संगठन।
- **नाम बदला गया:** मार्च 2022 में राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र (NCONF)

- **उद्देश्य:** जैविक, प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि विधियों सहित रसायन मुक्त टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- **फोकस:** प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ आयोजित करके और सूचना का प्रसार करके हितधारकों की क्षमता निर्माण।

पहले

- **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) (2014-15):** यह जल-उपयोग दक्षता बढ़ाने, जैविक पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने और जलवायु-अनुकूल सतत कृषि प्रथाओं को अपनाने पर केंद्रित है।
- **परम्परागत कृषि विकास योजना (अप्रैल 2015):** यह किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- जैविक फसलों की खेती के लिए किसानों के समूह बनाए जाते हैं और उन्हें इनपुट, बीज और अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- जैविक खेती की ओर परिवर्तन को सुगम बनाता है और सामुदायिक भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ

- जैविक पद्धतियों के बारे में किसानों के बीच सीमित जागरूकता और शिक्षा
- प्रमाणीकरण की उच्च प्रारंभिक लागत
- जैविक उत्पादों के लिए एक सुस्थापित बाजार संरचना का अभाव
- जैविक खेती की संक्रमण अवधि के दौरान, शुरुआत में पैदावार अस्थायी रूप से कम हो सकती है, जो उत्पादकों के लिए वित्तीय चुनौतियाँ पैदा करती है।
- प्राकृतिक तरीकों और पारंपरिक कृषि पद्धतियों का उपयोग करके कीटों और बीमारियों के प्रबंधन में कठिनाइयाँ
- संचालन को बढ़ाने की अनिवार्यता के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन से संबंधित मुद्दे
- कड़े मानकों को कायम रखने से जैविक खेती का परिदृश्य जटिल हो जाता है।

आगे की राह

- **ज्ञान का बेहतर प्रसार:** जैविक खेती की दक्षता और लाभप्रदता में वृद्धि करना
- **प्रौद्योगिकी का एकीकरण:** प्रिसिशन खेती तकनीक, आईटी-आधारित निगरानी प्रणाली और डेटा विश्लेषण संसाधन उपयोग को अनुकूलित कर सकते हैं, किसानों

को समयोचित जानकारी प्रदान कर सकते हैं और फसल की उपज में सुधार कर सकते हैं।

- **अनुसंधान और विकास में निवेश:** लचीली फसल किस्मों का विकास करना, नए जैविक कीट नियंत्रण तरीकों की खोज करना और नवीन तकनीकों के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाना।
- **सरकार से निरंतर नीति समर्थन:** मौजूदा योजनाओं को मजबूत करना, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना।
- **हितधारकों के बीच सहयोग और नेटवर्किंग को प्रोत्साहित करना:** किसान, उपभोक्ता, गैर सरकारी संगठन, शोधकर्ता, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उद्योग
- **अन्य तरीके:** ज्ञान साझा करना, संसाधनों तक पहुंच और सामूहिक विपणन प्रयास
- **जागरूकता फैलाना:** उपभोक्ताओं को जैविक उत्पादों के लाभों के बारे में शिक्षित करना

भारत में डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसर

- पिछले कुछ वर्षों में भारत में डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र केवल जनता के लिए किफायती पोषण के एक सतत आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरे हैं, बल्कि उन्होंने खेत को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। साथ ही, राष्ट्रीय आय और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हाल ही में ये क्षेत्र नए जमाने के उद्यमियों के स्टार्टअप के लिए पसंदीदा विकल्पों में से एक बन गए हैं। इन क्षेत्रों के सतत विकास के लिए आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण इन क्षेत्रों में उभरी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है।

ऑपरेशन फ्लड/श्वेत क्रांति

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत 1970 के दशक में डॉ. वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा की गई थी।
- **उद्देश्य:** दूध की उपलब्धता बढ़ाना।
- **प्रभाव:** प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन 1971-72 में 40.6 किलोग्राम/वर्ष से बढ़कर 1996-97 में 71.5 किलोग्राम/वर्ष और 2021-22 में 154.9 किलोग्राम/वर्ष हो गया।
- **लाभ:** किसानों को बेहतर मोल भाव की शक्ति, उचित मूल्य निर्धारण और आधुनिक डेयरी प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में मदद की।

- विदेशी नस्लों से स्वदेशी नस्लों पर स्थानांतरण से दूध उत्पादन में वृद्धि दर 2005 के बाद तेज हो गई। कई छोटे उद्यमियों को उन्नत डेयरी तकनीक का उपयोग करके, दूध उत्पादों में विविधता लाकर और एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से बाजार का विस्तार करके और उद्योग में हो रहे अनुसंधान और विकास में नई प्रगति का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

नीली क्रांति: मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन

- **लॉन्च:** 2015
- **कार्यान्वयन निकाय:** मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB)
- **प्रभाव:** भारत अब तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान देता है और जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- 2021-22 में मछली उत्पादन 16.24 मिलियन टन रहा, जिसमें समुद्री मछली उत्पादन 4.12 मिलियन टन और एक्वाकल्चर से 12.12 मिलियन टन शामिल है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

- **घोषणा:** 2019
- **उद्देश्य:** नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक क्रांति लाना जिसमें 2020-2025 के दौरान 20,050 करोड़ रुपये (200 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक) के निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत और जिम्मेदार विकास शामिल है।

मत्स्य पालन स्टार्टअप इंडिया

- **विवरण:** भारत सरकार द्वारा देश में मत्स्य पालन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए शुरू की गई एक नई पहल।

उपलब्धियाँ:

- भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में 50 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं।
- मत्स्य पालन विभाग, स्टार्टअप इंडिया के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए जलीय कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में काम करने वाले नवाचारों और स्टार्टअप की पहचान करना और उनका समर्थन करना चाहता है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- **लॉन्च:** 2014
- **फोकस:** चयनात्मक प्रजनन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों का आनुवंशिक सुधार और गोजातीय उत्पादकता में वृद्धि।
- **उद्देश्य:** उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के उपयोग को बढ़ावा देकर और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को मजबूत करके दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि करना।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन

- **विवरण:** यह पशुधन क्षेत्र में उद्यमिता विकास, नवाचार और विस्तार सेवाओं के महत्व को रेखांकित करता है।
- **उद्देश्य:** रोजगार सृजन को बढ़ावा देकर, पशुधन बीमा के माध्यम से जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देकर और अनुसंधान और विकास में निवेश करके उत्पादकता बढ़ाना और अधिक लचीला पशुधन उद्योग बनाना।

पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LHDC)

- **उद्देश्य:** निवारक टीकाकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करके गंभीर बीमारियों का उन्मूलन और नियंत्रण करना।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)

- **उद्देश्य:** भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की 100% आबादी का टीकाकरण करके मुंहपका-खुरपका रोग (FMD) और ब्रुसेल्लोसिस को नियंत्रित करना।

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (DIDF)

- **गठन :** केंद्रीय बजट 2017-18 के तहत
- **प्रबंधन:** राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- **उद्देश्य:** दूध प्रसंस्करण सुविधाओं, उपकरणों का आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार।

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF)

- **स्थापना:** 2020-21
- **उद्देश्य:** व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, MSME किसान उत्पादक संगठनों (FPOS) और धारा 8 कंपनियों सहित विभिन्न संस्थाओं से निवेश को प्रोत्साहित करना।
- **फोकस:** डेयरी और मांस प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना और पशु चारा संयंत्रों के लिए सुविधाएं विकसित करना।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

- **फोकस:** दूध की गुणवत्ता बढ़ाना और संगठित दूध खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- **उद्देश्य:** बाजार संपर्क बनाना, क्षमता निर्माण को मजबूत करना और विशिष्ट क्षेत्रों में डेयरी उत्पादन की समग्र दक्षता को बढ़ावा देना।

डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को समर्थन (SDCFPO)

- **फोकस:** संकट के दौरान वित्तीय सहायता और डेयरी किसानों के लिए स्थिर बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता।
- **उद्देश्य:** सहकारी संघों को सुगम कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके प्रतिकूल बाजार स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना।

चुनौतियां

- आपूर्ति शृंखला में रुकावटें
- जलवायु परिवर्तन
- परिवहन में व्यवधान
- अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ
- वितरण बाधाएँ
- अपर्याप्त लॉजिस्टिक्स और अपर्याप्त प्रसंस्करण सुविधाओं जैसी शृंखला-संबंधी चुनौतियाँ

आगे की राह

- बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी में निवेश करके आपूर्ति शृंखला में अक्षमताओं को संबोधित करना
- जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं का कार्यान्वयन
- नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना

भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती

- हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल खेती शहरी कृषि चुनौतियों का कुशल और टिकाऊ समाधान प्रदान करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करता है, साल भर फसल उत्पादन को सक्षम बनाता है, और पैदावार बढ़ाता है, संभावित रूप से खाद्य खेती, विशेष रूप से पत्तेदार सब्जियों की खेती में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। यह पानी, पोषक तत्वों और स्थान का संरक्षण करके, स्थिरता को बढ़ावा देकर अपशिष्ट को कम करता है। स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और स्वचालन का एकीकरण ऊर्ध्वाधर खेती में कृषि उत्पादकता को बढ़ाता है।

वर्टिकल खेती (VF)

- **विवरण:** संरक्षित इनडोर वातावरण में एक के ऊपर एक परतों में फसल उगाने का एक समकालीन अभ्यास।
- **पद्धति:** यह पारंपरिक मृदा-आधारित खेती और एकल स्तर पर शैतिज फसल विकास से हटकर मृदा रहित बहु-स्तरीय, संरक्षित इनडोर वातावरण को नियोजित करता है।

लाभ -

- यह खाद्य उत्पादन बढ़ा सकता है, गुणवत्ता बनाए रख सकता है और टिकाऊ शहरी खेती में योगदान दे सकता है।
- घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में लाभदायक जहां जगह सीमित है, जिससे उपलब्ध जगह का इष्टतम उपयोग हो सके।
- प्रकाश, तापमान, आर्द्रता और पोषक तत्वों जैसे कारकों को अनुकूलित करता है।

वर्टिकल खेतों में पोषक तत्व प्रदान करने की विधियाँ

- **हाइड्रोपोनिक्स:** इसमें पोषक तत्वों से लगातार सिंचित मृदा रहित पदार्थों पर पौधे उगाना शामिल है। पौधों की जड़ें पोषक तत्वों के घोल में डूबी रहती हैं, और यह प्रणाली पारंपरिक कृषि की तुलना में 60-70% कम पानी का उपयोग करती है, जिससे इसे दुनिया भर में कई ऊर्ध्वाधर खेतों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- **एरोपोनिक्स:** अंतरिक्ष पौधों के विकास के लिए 1990 के दशक में नासा द्वारा विकसित, एरोपोनिक्स मृदा-मुक्त नम वातावरण में खेती की सुविधा प्रदान करता है। जड़ें हवा में लटकी रहती हैं और इसकी जगह पोषक तत्वों से भरपूर धुंध से सिंचाई की जाती है।
- **एक्वापोनिक्स:** इस तकनीक में सब्जी में कीटनाशक, या कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह खुद पानी से अपने जरूरत के हिसाब से पोषण ले लेती हैं। इसमें पौधे लगाने के लिए पहले छोटे ट्रे में पौधा तैयार करना पड़ता है इसके बाद इसे तैरते हुए बोर्ड पर रखा जाता है। मछलियों वाले टैंक में उनके मल से पानी में अमोनिया में वृद्धि होती है। फिर इस टैंक के पानी को सब्जियों वाले टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं।

विभिन्न हाइड्रोपोनिक प्रणालियाँ

- **निष्क्रिय हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम:** इसमें बिना किसी यांत्रिक प्रभाव के कोशिका बल क्रिया का उपयोग करके जड़ों को पोषक तत्व घोल प्रदान किया जाता है। विक हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम इसी श्रेणी में आता है। यह सबसे सीधी हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली है जिसमें पोषक तत्वों के परिवहन के लिए किसी तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। विक हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम एक तेल के दीपक के समान कार्य करता है। जड़ें टैंक से सब्सट्रेट तक जाने वाली कपास या नायलॉन बत्ती की मदद से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं।
- **सक्रिय हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम:** इसमें पोषक तत्व घोल और वातन को प्रसारित करने में मदद करने के लिए कुछ तंत्र प्रभाव लागू किया जाता है। पंप जड़ों को पोषण और वातन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। निम्नांकित हाइड्रोपोनिक्स प्रणालियाँ इस श्रेणी में आती हैं-
 - ◆ **डीप वॉटर हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम:** सबसे आसान और सबसे प्रभावी प्रकार की इस प्रणाली में, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पौधे की जड़ें लगातार पोषक तत्व माध्यम वाले पानी में डूबी रहती हैं। पौधों को आमतौर पर एक मंच पर एकत्र

किया जाता है जो अक्सर फोम प्लास्टिक से बना होता है। यह प्लेटफॉर्म पोषक घोल से भरे टैंक में बहता है। एक विशेष वायु पंप पोषक तत्व के वातन में मदद करता है। चूँकि पौधे की जड़ें 24 घंटे पानी में डूबी रहती हैं, इसलिए फफूंदी और फफूंद के संचय से बचने के लिए घोल को नियमित रूप से बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीप वॉटर हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से छोटे और तेजी से बढ़ने वाले पौधों की खेती के लिए किया जाता है।

- ◆ **फ्लड और ड्रेन प्रणाली:** इस व्यवस्था में पौधों को एक ट्रे में रखा जाता है जिसमें समय-समय पर पोषक तत्वों से भरपूर पानी की आपूर्ति की जाती है। ट्रे के नीचे एक डूबा हुआ पंप लगा होता है, जो ट्रे को पोषक घोल से भर देता है। एक बार जब पानी एक निर्धारित स्तर तक पहुँच जाता है, तो एक अतिप्रवाह पाइप जलाशय में पोषक तत्व के घोल को वापस बहा देता है। पूरे बाढ़ चक्र के दौरान कम ऑक्सीजन वाली हवा को इस प्रणाली से बाहर धकेल दिया जाता है। जब पोषक घोल को वापस लिया जाता है, तो ऑक्सीजन युक्त हवा को बढ़ते हुए माध्यम में खींच लिया जाता है। नतीजतन, जड़ें पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं और अधिक पोषक तत्व ले सकती हैं।
- ◆ **न्यूट्रियंट फिल्म तकनीक:** इस हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में, पौधे पानी की उथली धारा में खड़े होते हैं, जिसमें पौधों के विकास के लिए आवश्यक सभी घुले हुए पोषक तत्व होते हैं। नतीजतन, बढ़ते टैंकों में पौधों की जड़ें लगातार पानी से भर जाती हैं। पौधों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वे जलाशय में मौजूद होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर घोल के संपर्क में आने पर पौधे जड़ युक्तियों के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर घोल गुरुत्वाकर्षण बल के साथ बहता है। घोल का प्रवाह ऑक्सीजन भी प्रदान करता है, जो पौधे की जड़ों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह तकनीक वर्टिकल खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, हल्के वजन वाले, तेजी से बढ़ने वाले पौधों के लिए यह आदर्श तकनीक है।
- ◆ **ड्रिप सिस्टम:** ड्रिप प्रकार की हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली पारंपरिक क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के सिद्धांत के आधार पर की जाती है। ड्रिप सिस्टम

हाइड्रोपोनिक्स प्रत्येक पौधे की जरूरतों के आधार पर पोषक तत्वों से भरे पानी को वतरित करने के लिए पानी के पंप द्वारा संचालित ट्यूबों की एक प्रणाली का उपयोग करता है। पंप आमतौर पर टाइमर से जुड़ा होता है जो सिंचाई कार्यक्रम को स्वचालित करता है। ड्रिप सिस्टम पोषक माध्यम के साथ पानी को सीधे पौधों के आधार तक पहुँचाता है। इसलिए यह पानी के वाष्पीकरण को कम करके पौधों की जड़ों को नम रखने में मदद करता है।

लाभ

- **वर्टिकल खेती के साथ संयोजन में हाइड्रोपोनिक्स** केंद्रित जड़ प्रणाली के कारण पारंपरिक खेती की तुलना में 99% कम भूमि का उपयोग करता है।
- **पारंपरिक कृषि पद्धतियों की तुलना में इसमें कम पानी** की आवश्यकता होती है
- **एक नियंत्रित माइक्रोक्लाइमेट के निर्माण को सक्षम** बनाता है, जिससे क्षेत्रीय या मौसमी फसलों की साल भर इनडोर खेती की अनुमति मिलती है
- **फसलों को मृदा-जनित कीटों और बीमारियों और प्रतिकूल मौसम** की स्थिति से बचाता है, जिससे कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है।
- **परिवहन और गोदाम की लागत को कम** कर आपूर्ति शृंखला को सुव्यवस्थित करते हैं।
- **विश्वसनीय और सतत खाद्य स्रोतों को सुनिश्चित** करते हुए ताजा उपज तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है

- **क्षैतिज हाइड्रोपोनिक विधियों की तुलना में वर्टिकल खेती** प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की उत्पादकता बढ़ाती है।
- **स्वचालित निगरानी और नियंत्रण प्रणालियाँ** उत्पादकों को बढ़ते शेड्यूल को अनुकूलित करने और फसलों के लिए इष्टतम पर्यावरणीय स्थिति प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं।
- **शहरी क्षेत्रों में, वर्टिकल खेती** जैव विविधता और स्थिरता जैसे पर्यावरणीय लाभ और शिक्षा सहित सामाजिक-आर्थिक लाभ दोनों प्रदान करती है।

हानियाँ

- **उच्च अग्रिम अवसंरचना** लागत व्यापक रूप से इस तकनीक को अपनाने में बाधा उत्पन्न करती है।
- **विशेषज्ञता की कमी और नियंत्रित विकास प्रणाली** की आवश्यकता के लिए उच्च शिक्षित कार्यबल की आवश्यकता होती है, जिससे श्रम लागत बढ़ जाती है
- इसके लिए कृत्रिम प्रकाश, तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है।
- **नियंत्रित परिस्थितियों में प्राकृतिक परागणकों की अनुपस्थिति** के परिणामस्वरूप खराब फल लग सकते हैं और छोटे, खराब आकार के फलों का उत्पादन हो सकता है।
- **व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली फसलों की श्रेणी आमतौर पर पत्तेदार सब्जियों और माइक्रोग्रीन्स** तक ही सीमित है।
- **निरंतर ध्यान और देखभाल की आवश्यकता** होती है, पंप और पोषक तत्व वितरण प्रणाली जैसे घटकों को नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है।

14

आलेख

सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.26 लाख करोड़ रुपये की चिप बनाने वाली इकाइयों को मंजूरी दी

- भारत सरकार ने तीन सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी देकर सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 फरवरी को घोषित मंजूरी में 1.26 लाख करोड़ रुपये (15.2 बिलियन डॉलर) का निवेश शामिल है।

भारत सरकार की घोषणाएँ :-

गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर फैब:

- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान के पावरचिप सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कॉर्प द्वारा स्थापित।
- प्रति माह 50,000 वेफर्स का उत्पादन करने का अनुमान, 91,000 करोड़ रुपये का निवेश।
- ईवी, दूरसंचार और रक्षा के लिए 28 एनएम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर चिप्स में विशेषज्ञता।

मोरीगाँव, असम में सेमीकंडक्टर इकाई:

- टाटा सेमीकंडक्टर असंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (TSAT) द्वारा स्थापित।
- ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स का उत्पादन करने के लिए 27,000 करोड़ रुपये का निवेश।

साणंद, गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई:

- सीजी पावर, रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प (जापान) और स्टार्स माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स (थाईलैंड) द्वारा स्थापित।
- 7,600 करोड़ रुपये का निवेश।
- 100 दिनों के भीतर निर्माण शुरू होगा।

इस कदम का महत्व

तकनीकी स्वायत्तता:

- घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमताओं के निर्माण में भारत की तकनीकी स्वायत्तता को बढ़ाती है।
- आयात पर निर्भरता कम करता है, विशेषकर ताइवान जैसे विनिर्माण दिग्गजों से।

सामरिक महत्व:

- रक्षा, ऑटोमोबाइल और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए

सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण हैं।

- घरेलू क्षमताओं के निर्माण से भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होती है।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:

- भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है।
- सेमीकंडक्टर मांग में वैश्विक रुझानों के अनुरूप।

आर्थिक विकास:

- भारत के सेमीकंडक्टर बाजार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसके 2026 तक 63 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करता है और स्थानीय स्तर पर उन्नत पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों का विकास करता है।

रोजगार निर्माण:

- लगभग 20,000 प्रत्यक्ष उन्नत प्रौद्योगिकी नौकरियों और लगभग 60,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन।
- संबंधित क्षेत्रों में विकास को उत्प्रेरित करता है, आर्थिक विकास में योगदान देता है।

भारत के लिए चुनौतियाँ

- **सहयोगियों से प्रतिस्पर्धा:** भारत की चिप प्रोत्साहन योजनाओं को अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे करीबी सहयोगियों द्वारा पेश की जाने वाली अधिक आकर्षक योजनाओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- **तकनीकी अंतराल:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के विपरीत 28nm जैसे पुराने नोड्स पर ध्यान केंद्रित; उदाहरण के लिए, TSMC 3 एनएम के नोड आकार वाले चिप्स का उत्पादन करता है।
- **प्रतिभा की कमी:** हालाँकि भारत में डिजाइन इंजीनियरों का एक बड़ा समूह है, लेकिन निर्माण संयंत्र संचालन के लिए कुशल प्रतिभा सीमित है।
- **मूल अनुसंधान का अभाव:** भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन में मूल अनुसंधान का अभाव है, जो भविष्य के चिप विकास और नवाचार के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** 10,000 करोड़ रुपये के आधुनिकीकरण योजना के साथ मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (SCL) में एक अनुसंधान

एवं विकास प्रयोगशाला की स्थापना, जिसमें भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर भी शामिल है, जो भारत की जरूरतों को पूरा करने वाले चिप्स विकसित करने पर केंद्रित है।

- **चिप प्रोत्साहन योजना:** 2021 में 76,000 करोड़ रुपये की चिप प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सेमीकंडक्टर संयंत्रों के लिए पूंजीगत व्यय लागत के आधे हिस्से को कवर करने वाली सब्सिडी दी जाएगी।
- **उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना:** स्मार्टफोन और लैपटॉप विनिर्माण के लिए पीएलआई जैसी योजनाओं का कार्यान्वयन, कंपनियों को उनके बिक्री बिल के आधार पर सब्सिडी प्रदान करना।

भारत के लिए आगे की राह

- **सरकारी-निजी क्षेत्र सहयोग:** सेमीकंडक्टर निर्माण में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश के साथ-साथ सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।
- **वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करना:** जैसे-जैसे निर्माण आगे बढ़ रहा है और परिचालन क्षमताएँ विकसित हो रही हैं, भारत अपने स्मार्टफोन असेंबली उद्योग में देखी गई सफलता के समान, अधिक वैश्विक खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए तैयार है।

थाईलैंड ने डब्ल्यूटीओ में भारत की कृषि सब्सिडी की आलोचना क्यों की?

- भारत के सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम पर उनकी टिप्पणियों पर भारत द्वारा औपचारिक रूप से विरोध दर्ज कराने के बाद थाईलैंड ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में अपने राजदूत को बदल दिया है।
- थाई राजदूत ने हाल ही में भारत के चावल खरीद कार्यक्रम पर निशाना साधा था और कहा था कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) लोगों के लिए नहीं बल्कि निर्यात बाजार पर कब्जा करने के लिए है।

भारत और थाईलैंड के बीच तनाव

- थाईलैंड भारत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक है।
- भारत और थाईलैंड के बीच तनाव इस हद तक बढ़ गया कि डब्ल्यूटीओ के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय वार्ताकारों ने उस विचार-विमर्श में भाग लेने से इनकार कर दिया, जहां थाई प्रतिनिधि मौजूद थे।

थाईलैंड की चिंताएँ

- **20 देशों के केर्न्स समूह के सदस्य के रूप में थाईलैंड:** इसने डब्ल्यूटीओ में भारत के PSH कार्यक्रम

पर कई बार यह कहते हुए सवाल उठाया है कि यह अत्यधिक सब्सिडी देने वाला कार्यक्रम है और यह वैश्विक खाद्य कीमतों को विकृत कर रहा है और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा को ठेस पहुंचा रहा है।

- **व्यापार विकृति:** ऐसी स्थिति जहां कीमतें और उत्पादन उस स्तर से अधिक या कम होते हैं जो आमतौर पर प्रतिस्पर्धी बाजार में मौजूद होते हैं। सभी घरेलू समर्थन उपायों को व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, लेकिन उन्हें एक निश्चित सीमा तक अनुमति दी जाती है जिसे 'डी मिनिमिस' सीमा कहा जाता है।
- **कृषि पर डब्ल्यूटीओ के समझौते (AoA) के प्रावधान:** उत्पाद-विशिष्ट समर्थन का कुल मूल्य प्रश्न में कृषि उत्पाद के उत्पादन के कुल मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **अपवाद:** भारत जैसे विकासशील देशों के मामले में, न्यूनतम सीमा 10% है।
- **भारत द्वारा उल्लंघन:** भारत ने चावल के मामले में न्यूनतम सीमा का उल्लंघन किया है जिससे थाईलैंड जैसे अन्य निर्यातक नाराज हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय चावल के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है।

भारत की चावल सब्सिडी पर मुद्दा

- **डब्ल्यूटीओ मानदंड:** दिया गया समर्थन 10% न्यूनतम सीमा के भीतर होना चाहिए।
- **भारत का रुख:** 2019-20 में इसके चावल उत्पादन का मूल्य 46.07 अरब डॉलर था जबकि इसने 6.31 अरब डॉलर या 13.7% (10% के मुकाबले) की सब्सिडी दी। भारत का कहना है कि उसकी सब्सिडी की गणना 1986-88 की एक निश्चित और पुरानी कीमत पर की जाती है, जो सब्सिडी को अधिक आंकती है।

WTO में भारत का तर्क और मांग

- **केर्न्स समूह 'शांति खंड' का उल्लंघन कर रहा है:** शांति खंड 2013 में बाली समझौते के तहत विकासशील देशों को सब्सिडी स्तरों के उल्लंघन की चुनौती से बचाने के लिए रखा गया था। हालाँकि, इसकी शर्तें जटिल हैं, जिसमें कई अधिसूचना आवश्यकताएँ भी शामिल हैं, जिससे इसका उपयोग करना कठिन हो जाता है।
- **भारत और अन्य विकासशील देश खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं:** भारत ने तर्क दिया कि यह भारत को कृषि सहायता प्रदान करने में बेहतर लचीलापन देगा और भारत जो सब्सिडी प्रदान करता है वह अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी से बहुत कम है।

केन्स समूह

- **विवरण:** कृषि व्यापार उदारीकरण की पैरवी करने वाले कृषि निर्यातक देशों का एक समूह।
- **स्थापना:** 1986 में उरुग्वे दौर की शुरुआत से ठीक पहले केन्स, ऑस्ट्रेलिया में।
- **सदस्य:** अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, यूक्रेन, उरुग्वे और वियतनाम
- **उद्देश्य:** विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत में अपने सदस्यों को स्थानीय उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली घरेलू कृषि सब्सिडी से छुटकारा दिलाकर उनकी बाजार पहुंच को बढ़ाना।
- **डब्ल्यूटीओ में सभी आयात-प्रतिबंधित उपायों की आलोचना करता है:** यह उन टैरिफ में कमी की मांग करता है जो भारत जैसे देश कृषि उत्पादों के आयात पर लागू करते हैं।

प्लास्टिक से हिमालयी राज्यों पर प्रभाव

- भारतीय हिमालय क्षेत्र उपमहाद्वीप में पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो भारत की कई प्रमुख नदियों को पानी देता है जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ शामिल हैं। अवैज्ञानिक प्लास्टिक निपटान से भारतीय हिमालयी क्षेत्र में मिट्टी और जल प्रदूषण हो रहा है और इसकी जैव विविधता पर असर पड़ रहा है, जिससे ताजे पानी के स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिन पर निचले इलाकों में रहने वाले समुदाय निर्भर हैं।

माइक्रोप्लास्टिक

- **विवरण:** पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं (जिन्हें अक्सर जानबूझकर सौंदर्य प्रसाधन और सफाई एजेंटों जैसे उपभोक्ता उत्पादों में जोड़ा जाता है) के विखंडन और क्षरण और छोटे प्लास्टिक कणों के सीधे निकलने के कारण बनते हैं, ।
- **माइक्रोप्लास्टिक के आकार पर कोई सार्वभौमिक समझौता नहीं:** यूएस एनओए (नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन) और यूरोपीय रासायनिक एजेंसी माइक्रोप्लास्टिक को 5 मिमी से कम लंबाई के रूप में परिभाषित करते हैं।

माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रकार:

प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक्स: सौंदर्य प्रसाधन जैसे व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइन किए गए छोटे कण, साथ ही कपड़ों और मछली पकड़ने के जाल

जैसे अन्य वस्त्रों से निकलने वाले माइक्रोफाइबरा।

- **द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स:** पानी की बोटलों जैसी बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के विघटन का परिणाम होता है, जब बड़े प्लास्टिक, उदाहरण के लिए, तरंग क्रिया, वायु घर्षण, और सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने से अपक्षय से गुजरते हैं।

पर्यावरणीय प्रभाव:

- **बायोडिग्रेडेबल नहीं:** एक बार पर्यावरण में आने पर प्राथमिक और द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक्स जमा हो जाते हैं और इनका क्षरण नहीं होता है।
- **समुद्री जीवों द्वारा अंतर्ग्रहण:** जलीय जीवन और खाद्य श्रृंखला के साथ जैवसंचय को संभावित नुकसान।
- **जहरीले रसायन और प्रदूषक:** जीवों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा करते हैं।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट संकट के कारण

- तीव्र एवं अनियोजित शहरीकरण
- उत्पादन और उपभोग के पैटर्न में बदलाव
- पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल

प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने की दिशा में भारतीय पहल

- **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल:** इसने पर्यटकों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में कचरा डंप करने पर विभिन्न निकायों को नोटिस जारी किया।
- **हिमालयन क्लीन अप (2018-21):** जीरो वेस्ट हिमालय के साथ इंटीग्रेटेड माउंटन इनिशिएटिव और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अपशिष्ट और ब्रांड ऑडिट द्वारा संचालित।
- **हिमालयन क्लीन अप (2022):** 92.7% कचरा प्लास्टिक था, 72% कचरा गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक था।

वर्तमान विधान में मुद्दे

- **स्वच्छ भारत मिशन** द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को मान्यता तो दी जाती है, लेकिन स्थानीय निकायों और उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (PIBO) दोनों के लिए जनादेश बनाते समय इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ने पहाड़ों की विशेष जरूरतों को भी नहीं पहचाना है।
- **स्वच्छ भारत मिशन/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन/विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का सामूहिक**

अधिदेश: इसके लिए स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण की आवश्यकता होती है और न केवल प्लास्टिक को अन्य कचरे से, बल्कि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक से भी अलग करना होता है, लेकिन यह नहीं होता है।

- **प्रभाव:** मिश्रित कचरे से निकलने वाला अपशिष्ट मिट्टी और भूजल प्रदूषण का कारण बनता है जबकि ऐसे मिश्रित कचरे से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे:** अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य स्थानीय निकायों का कर्तव्य है, लेकिन उन्हें शक्ति का आनुपातिक हस्तांतरण अभी भी प्रगति पर है।
- **कोई मॉडल उपनियम नहीं:** बहुत कम स्थानीय निकायों ने स्वयं शासनादेश को क्रियान्वित करने के लिए उपनियम बनाए हैं।
- **स्थानीय निकायों और PIBO (निर्माताओं, आयातकों और ब्रांड मालिकों) के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के अधिदेश के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं।**

प्लास्टिक ओवरशूट दिवस

- **विवरण:** यह एक वर्ष में उस समय को चिह्नित करता है जब उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा उसके उचित प्रबंधन और निपटान की क्षमता से अधिक हो जाती है।
- **महत्व:** यह एक महत्वपूर्ण बिंदु को दर्शाता है जहां दुनिया में कचरा प्रबंधन प्रणालियों द्वारा प्रभावी ढंग से संभाले जा सकने वाले प्लास्टिक कचरे की तुलना में अधिक प्लास्टिक कचरा जमा हो जाता है।
- **पहल :** एनवायरनमेंट एक्शन, एक स्विस् संगठन द्वारा
- **भारत पर प्लास्टिक का बोझ:** भारत दुनिया में (केन्या, नाइजीरिया और मोजाम्बिक के बाद) 98.55% के साथ सबसे अधिक कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक (MWI) (जो अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता और प्लास्टिक की खपत में अंतर है) वाले देशों में से एक है।
- **भारत की प्लास्टिक निपटान क्षमता:** भारत अपने प्लास्टिक कचरे का केवल 12% ही पुनर्चक्रण कर रहा है। इस कचरे का लगभग 20% सह-भस्म, प्लास्टिक से ईंधन और सड़क बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका मतलब है कि हम अपने प्लास्टिक कचरे का 20% जला रहे हैं और अभी भी इसे 'रीसाइक्लिंग' कह रहे हैं और जबकि 68% प्लास्टिक कचरे का कोई हिसाब नहीं है।

अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानूनी अधिदेश

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (SNM) 2016
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम 2016
- विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (EPR) 2022

राज्यवार पहल

- **हिमाचल प्रदेश:** यहां 2019 से गैर-पुनर्चक्रण योग्य और एकल-उपयोग प्लास्टिक कचरे के लिए बाय बैक नीति है, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा फैला हुआ है।
- **सिक्किम:** इसने जनवरी 2022 से पैकेज्ड मिनरल वाटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन प्लास्टिक कचरे को संभालने के लिए उचित बुनियादी ढांचे के अभाव में, राज्य अभी भी इस मुद्दे से जूझ रहा है।
- **मिजोरम:** आइजोल नगर निगम ने 2019 में PWM के तहत उपनियम बनाए।
- **त्रिपुरा:** इसने नगरपालिका उपनियम बनाए और एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने के लिए एक राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स बनाई है, हालांकि परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।

आगे की राह

- जब भारतीय हिमालयी क्षेत्र (पूर्वोत्तर के कई राज्यों में प्रचलित) की बात आती है तो पारंपरिक संस्थानों को स्थानीय निकायों की परिभाषा में शामिल करने की आवश्यकता है।
- भारतीय हिमालय क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता, पारिस्थितिक संवेदनशीलता और सुभेद्यता को ध्यान में रखते हुए और प्रतिबिंबित करते हुए उचित संसाधन आवंटन और समर्थन की आवश्यकता है।
- स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना के निर्माण पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- निरंतर सार्वजनिक शिक्षा अभियानों की सहायता से कचरे का पृथक्करण और लोगों की भागीदारी।
- पर्वतीय क्षेत्र में EPR परिचालन की उच्च लागत पर विचार किया जाना चाहिए।
- भारतीय हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा और गुणवत्ता के संदर्भ में डेटा अंतराल को पाटना।
- SBM, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और वित्त आयोग के अनुदान जैसी मौजूदा योजनाओं में अभिसरण।
- इस उद्देश्य के लिए परोपकारी योगदान और CSR फंड के चैनलाइजेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित स्वच्छ भारत कोष ट्रस्ट का उपयोग।
- वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और भारतीय हिमालयी क्षेत्र के शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मुद्दे पर अटल कार्याकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और स्मार्ट सिटी योजना में अभिसरण।

CAA: नागरिकता अधिनियम को विधिक चुनौती

- संसद द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) पारित करने के चार साल से अधिक समय बाद, गृह मंत्रालय ने हाल ही में कानून को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। CAA को, जिसके कारण 2019-20 में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी चुनौती दी गई है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) 2019

- विवरण:** यह अधिनियम केवल मुसलमानों को छोड़कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन और ईसाई आप्रवासियों के लिए अवैध आप्रवासी की परिभाषा में संशोधन करना चाहता है।
- फास्ट-ट्रैक नागरिकता:** 5 वर्षों में फास्ट-ट्रैक भारतीय नागरिकता प्रदान करता है (पहले 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य)।

पात्रता:

- जिन लोगों ने धार्मिक आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण ली थी।
- नागरिकता के लिए अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2014
- छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और इनर-लाइन परमिट व्यवस्था वाले राज्यों को बाहर रखा गया है।

CAA नियमों की अधिसूचना में देरी

- असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में मुखर विरोध
- 1985 के असम समझौते का उल्लंघन करते हुए असम में राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने का डर।
- सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ।
- अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
- म्यांमार के रोहिंग्या, चीन के तिब्बती बौद्ध और श्रीलंका के तमिलों जैसे कुछ उत्पीड़ित समूहों को बाहर करने में मनमानी की गई।
- सर्वोच्च न्यायालय का रुख:** उसने माना है कि समानता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कानून को दो विधिक बाधाओं को दूर करना होगा।
- व्यक्तियों के समूहों के बीच कोई भी भेदभाव समझदारीपूर्ण अंतर पर आधारित होना चाहिए
- उस अंतर का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध होना चाहिए।
- सरकार का रुख:** मुसलमानों को उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के समूह से बाहर रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं।

नागरिकता संशोधन नियम, 2024

- आवेदन प्रस्तुतीकरण:** योग्य शरणार्थियों को दिए गए बयानों की सटीकता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा , एक भारतीय नागरिक द्वारा उनके चरित्र की पुष्टि करने वाला हलफनामा और संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषा के साथ परिचित होने की घोषणा के साथ एक आवेदन जमा करना होगा।

जिला स्तरीय समिति को ई-आवेदन:

- आवेदन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से सशक्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।
- जिला-स्तरीय समिति दस्तावेजों का सत्यापन करती है और निष्ठा की शपथ दिलाती है।
- अनुपस्थित आवेदकों के लिए प्रक्रिया:** यदि कोई आवेदक अवसरों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला-स्तरीय समिति आवेदन को अस्वीकार करने पर विचार कर सकती है।
- सहायक दस्तावेज:** आवेदकों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान दस्तावेज, भूमि रिकॉर्ड, या वंश साबित करने वाले दस्तावेज सहित सहायक दस्तावेज प्रदान करने होंगे।
- दस्तावेजों की वैधता:** दस्तावेज समाप्ति तिथि के बाद भी वैध रहते हैं।
- प्रवेश तिथि का सत्यापन:**
 - आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश का प्रमाण देना होगा।
 - सहायक दस्तावेजों में बीजा टिकट, पंजीकरण प्रमाणपत्र, जनगणना प्रणालि पर्चियाँ, सरकार द्वारा जारी लाइसेंस, विवाह प्रमाणपत्र आदि शामिल हैं।
- डिजिटल प्रमाणपत्र:**
 - अनुमोदन पर, आवेदकों को एक डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त होता है।

नागरिकता आवेदन प्रक्रिया में बदलाव

- प्राधिकार में परिवर्तन:**
 - पहले, नागरिकता के आवेदन राज्य सरकार के नियंत्रण में जिला कलेक्टर को दिए जाते थे।
 - नए नियम आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए केंद्र द्वारा सशक्त और जिला स्तरीय समितियों की स्थापना करते हैं।
- अधिकार प्राप्त समिति की संरचना:** एक निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति।
- अन्य सदस्यों में शामिल हैं:**
 - सहायक खुफिया ब्यूरो, FRRO के उप सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी,

- » राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
- » राज्य के पोस्टमास्टर जनरल
- **अतिरिक्त आमंत्रित:**
 - » **समिति में दो आमंत्रित सदस्य:** संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के प्रमुख सचिव (गृह) या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के कार्यालय से प्रतिनिधि,
 - » **रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले मंडल रेल प्रबंधक** का प्रतिनिधि।
- **इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतिकरण:** आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने हैं।

वैश्विक जलपरिदृश्य को नेविगेट करना, इसकी चुनौतियाँ

- 22 मार्च, 2024 को 31वाँ विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसका विषय था, 'शांति के लिए जल का लाभ उठाना।' 'विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम' के तहत, यूनेस्को ने प्रमुख संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, "समृद्धि और शांति के लिए जल" के 2024 संस्करण के विकास का नेतृत्व किया। यह संयुक्त राष्ट्र जल (48 अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ 35 संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं का जल और स्वच्छता पर एक अंतर-एजेंसी समन्वय तंत्र) का एक हिस्सा है।

जल संघर्ष का ऐतिहासिक संदर्भ

- **जल का महत्व:** पूरे इतिहास में पानी प्रमुख सभ्यताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति रहा है, जैसे कि सिंधु, नील और टिगरिस-फरात नदियों के किनारे की सभ्यताएँ।
- **प्रचुरता के बीच संघर्ष:** इसके महत्व के बावजूद, पानी ने संघर्षों को भी जन्म दिया है, जैसा कि लगश और उम्मा जैसे मेसोपोटामिया के शहरों के बीच विवादों में देखा गया है।
- **मेसिलिम की संधि:** इन संघर्षों के कारण दुनिया का पहला शांति समझौता हुआ, जिसे मेसिलिम की संधि कहा गया जो मानवता के शुरुआती समझौतों में से एक है।

जल कूटनीति की आवश्यकता

- **सहयोगात्मक शासन:** जल कूटनीति संवाद, सूचना साझाकरण और संयुक्त निर्णय लेने के माध्यम से साझा जल चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक शासन तंत्र की वकालत करती है।
- **न्यायसंगत जल आवंटन:** जल कूटनीति तटवर्ती राज्यों के बीच न्यायसंगत जल आवंटन को बढ़ावा देती है, इसमें शामिल सभी पक्षों की जरूरतों, अधिकारों और

कमजोरियों पर विचार किया जाता है, जिससे जल संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित होता है।

- **क्षेत्रीय स्थिरता और शांति:** प्रभावी जल कूटनीति सहयोग को बढ़ावा देकर, विश्वास का निर्माण करके और पानी से संबंधित विवादों से उत्पन्न तनाव को कम करके क्षेत्रीय स्थिरता और शांति में योगदान करती है, जिससे सुरक्षा बढ़ती है और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा मिलता है।
- **समावेशी दृष्टिकोण:** जल कूटनीति में जल प्रबंधन में सामाजिक समानता, पारदर्शिता और भागीदारी निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी समुदायों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र सहित विभिन्न हितधारक शामिल है।
- **संघर्ष की रोकथाम और समाधान:** जल कूटनीति सक्रिय कूटनीति, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और शांतिपूर्ण विवाद समाधान तंत्र को नियोजित करके संघर्षों को रोकने और हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे हिंसा का जोखिम कम होता है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा मिलता है।

भारत में ग्रामीण जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ

- **अवसंरचना विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कुओं, हैंडपंप, बोरहोल और पाइप जल आपूर्ति प्रणालियों जैसे जल अवसंरचना के निर्माण और रखरखाव में निवेश किया जा सकता है।
- **सामुदायिक भागीदारी:** भागीदारी के माध्यम से जल परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन और प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, उन्हें जल संसाधनों का स्वामित्व लेने, कुशल जल उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने और जल पहुंच पर विवादों को हल करने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है।
- **जल संरक्षण और प्रबंधन:** ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों की दक्षता और स्थिरता को अधिकतम करने के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, वाटरशेड प्रबंधन और मिट्टी की नमी संरक्षण तकनीकों जैसे जल संरक्षण और प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **तकनीकी नवाचार:** ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पहुंच और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता की सामयिक निगरानी के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और मोबाइल-आधारित अनुप्रयोगों जैसे तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाया जा सकता है।

- **सरकारी समर्थन और नीतिगत हस्तक्षेप:** जल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना, समान जल वितरण के लिए नियामक ढांचे को लागू करना, जल संसाधनों की रक्षा के लिए कानून बनाना और पानी, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास के बीच जटिल अंतर्संबंधों को संबोधित करने के लिए सभी क्षेत्रों में नीतिगत सुसंगतता सुनिश्चित करना।

सीमा पार जल प्रशासन का महत्व

- **पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता:** सीमा पार जल संसाधन पारिस्थितिक तंत्र और सीमाओं के पार जैव विविधता को बनाए रखते हैं, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और लचीलेपन में योगदान करते हैं।
- **आजीविका सहायता:** साझा जल निकाय सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मछली पकड़ने, कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं।
- **आर्थिक विकास:** सीमा पार जल संसाधनों तक पहुँच कृषि, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करके क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है।
- **संघर्ष की रोकथाम:** प्रभावी शासन पानी की पहुँच और उपयोग पर संघर्ष को कम करने में मदद करता है, जिससे तटवर्ती राज्यों के बीच शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

प्रभावी सीमा पार जल प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ

- **राजनयिक जुड़ाव:** सहयोग, विश्वास-निर्माण और संघर्ष समाधान को बढ़ावा देने के लिए तटवर्ती राज्यों के बीच राजनयिक प्रयासों और संवाद प्लेटफार्मों को मजबूत करना।
- **क्षमता निर्माण:** संयुक्त रूप से सीमा पार जल संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए तटवर्ती राज्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण, तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने में निवेश किया जा सकता है।
- **विधिक ढाँचा:** मजबूत विधिक ढाँचे, संधियाँ और समझौते विकसित और कार्यान्वित किये जा सकते हैं जो विवाद समाधान के लिए अधिकारों, जिम्मेदारियों और तंत्रों को चित्रित करते हैं, सहकारी प्रबंधन के लिए आधार प्रदान करते हैं।
- **सहभागी दृष्टिकोण:** समावेशी निर्णयन और सतत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सरकारों, स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

- **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन:** जल संसाधन प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों पर विचार करता है, सीमा पार जल प्रणालियों के समग्र और सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है।

राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग

- उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में राज्यसभा चुनावों में विभिन्न दलों के विधायकों द्वारा क्रॉस-वोटिंग (उस पार्टी के लिए मतदान करना जिससे वह संबंधित नहीं है) देखी गई। इससे एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

राज्यसभा चुनाव

- **संवैधानिक प्रावधान**
 - » **अनुच्छेद 80:** राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों को उनकी विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।
 - » **राज्यसभा के लिए मतदान की शर्त:** मतदान की आवश्यकता तभी होगी जब उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक हो।
 - » **1998 तक प्रथा:** राज्यसभा चुनावों का नतीजा आम तौर पर पहले से तय निष्कर्ष होता था। विभिन्न दलों द्वारा विधानसभा में अपनी संख्या के अनुसार नामांकित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो जाते थे।

विधिक प्रावधान

- » **2003 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन:** धारा 59 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया कि राज्यसभा के चुनावों में मतदान खुले मतपत्र के माध्यम से होगा।
- » **विधायकों के लिए निर्देश:** उन्हें अपना मतपत्र अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना होगा।
- » **अयोग्यता:** मतपत्र को अधिकृत एजेंट को न दिखाना या किसी अन्य को दिखाना वोट को अयोग्य घोषित कर देगा।
- » **निर्दलीय विधायकों पर रोक:** किसी को भी अपने मतपत्र दिखाने पर रोक।
- » **52वां संवैधानिक संशोधन, 1985:** दसवीं अनुसूची के माध्यम से दलबदल विरोधी कानून की शुरुआत; पार्टी छोड़ने या पार्टी के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करने पर सदस्यों को अयोग्यता का सामना करना पड़ता है।
- » **चुनाव आयोग ने जुलाई 2017 में स्पष्ट किया:** दसवीं अनुसूची राज्यसभा चुनावों पर लागू नहीं होती है और पार्टियाँ राज्यसभा चुनावों के लिए सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट और 10वीं अनुसूची

- कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ (2006):
 - » सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव के लिए खुले मतदान को सही ठहराया।
 - » तर्कसंगत पारदर्शिता भ्रष्टाचार का मुकाबला कर सकती है।
 - » निर्वाचित विधायक को पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मतदान करने पर दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
 - » पार्टी की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
- रवि एस. नाइक और संजय बांदेकर बनाम भारत संघ (1994):
 - » सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दसवीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना उस पार्टी से इस्तीफा देने के समान नहीं है, जिसका वह सदस्य है।
 - » सदन के अंदर और बाहर सदस्य के आचरण को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता माना जाता है।

आगे की राह

- इस तरह की मतदान प्रथाओं के खिलाफ संविधान या विधियों को मजबूत करने के लिए और संशोधन किए जाने चाहिए क्योंकि सत्तारूढ़ दलों को ऐसी गैर-सैद्धांतिक रणनीति से लाभ होता है।
- न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान ली गई जनहित याचिका।

15

टर्म इन न्यूज़

स्टार प्रचारक

- स्टार प्रचारक वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव अभियानों के दौरान उनका प्रचार करने के लिए चुना जाता है। वे मतदाताओं को प्रभावित करने, पार्टी का प्रचार करने और समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं, जबकि गैर-मान्यता प्राप्त दल केवल 20 प्रचारक रख सकते हैं। स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव की अधिसूचना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग को देनी होती है। ये प्रचारक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से रैलियों, सार्वजनिक बैठकों और अन्य अभियान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

T+0 सेटलमेंट

- भारत शेयर बाजार में T+0 सेटलमेंट नामक निपटान प्रणाली शुरू कर रहा है। इससे पहले, शेयर बाजार में T+1 (व्यापार के एक दिन बाद) सेटलमेंट प्रणाली थी इससे विक्रेताओं को धन प्राप्त करने के लिए एक दिन इंतजार करना पड़ता था और खरीदार शेयरों के लिए इंतजार करते थे। अब, T+0 के साथ, दोनों पक्षों का लेन-देन उसी कारोबारी दिन हो सकेगा (फंड और शेयर ट्रांसफर) जिस दिन कारोबार होता है। इससे नकदी और होल्डिंग्स तक पहुंच में तेजी आती है, तथा बाजार की दक्षता में वृद्धि होती है, हालाँकि नए बदलाव के कारण शुरुआत में ब्रोकर्स और निवेशकों के लिए इसे अपनाने में चुनौती आ सकती है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)

- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) एक ऐसा कर है जो एक व्यवसाय को उस GST के लिए मिलता है जो वह आपूर्ति (जैसे सामग्री) के समय भुगतान करता है। यह कर अंतिम उत्पाद की बिक्री के समय एकत्र किए गए GST से काट लिया जाता है। इसे अग्रिम भुगतान के रूप में माना जाता है जो व्यवसाय में आपूर्ति पर GST का अग्रिम भुगतान करता है, लेकिन बिक्री करने पर उसे वापस मिल जाता है। इससे व्यवसाय पर बकाया अंतिम GST कम हो जाता है, उनका कर बोझ कम हो जाता है और दोहरे कराधान को रोका जा सकता है। हालाँकि, ITC के लिए वैध GST पंजीकरण और खरीद पर भुगतान किए गए GST के प्रमाण की आवश्यकता होती है।

सौर ऊर्जा अपशिष्ट

- सौर ऊर्जा, सामान्यतया स्वच्छ है लेकिन इसके उत्पादन हेतु काम लिए जाने वाले उपकरण अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। इसके उपकरणों के विनिर्माण में सिलिकॉन ऑफकट्स, विषैले रसायनों और हानिकारक सामग्रियों का उत्पादन होता है जिनका उचित निस्तारण करने की आवश्यकता है। सौर पैनल 25-30 वर्षों के बाद बेकार हो जाते हैं, जबकि कुछ सामग्रियों को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, पुराने पैनलों का यदि उचित निस्तारण नहीं किया जाय तो ये जमीन में धंस सकते हैं जो कि हानिकारक हो सकता है इसके अलावा परिचालन सुविधाएं भी अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जैसे क्षतिग्रस्त तार और खराब उपकरण आदि। इन्हें भी उचित निस्तारित करने की आवश्यकता है।

हरित हाइड्रोजन

- हरित हाइड्रोजन, सस्टेनेबल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यह सौर या पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके पानी (H₂O) को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। यह इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन पर निर्भर पारंपरिक तरीकों के बजाय, बिना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से हाइड्रोजन ईंधन बनाती है। इस स्वच्छ हाइड्रोजन गैस का उपयोग वाहनों, इमारतों और या पयूल सेल्स में विद्युत् उत्पादन हेतु किया जा सकता है, इससे पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है।

कोरोनल मास इजेक्शन (CME)

- कोरोनल मास इजेक्शन (CME) सूर्य के बाहरी वातावरण (कोरोना) से हुआ गर्म, चुंबकीय प्लाज्मा का विशाल विस्फोट है। यह अत्यधिक गरम और आवेशित कणों का एक विशाल बुलबुला की तरह है जो प्रस्फुटित हुआ हो। ये CME लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं और एक अरब टन सामग्री ले जा सकते हैं। यदि कोई CME पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराता है, तो यह अरोरा (उत्तरी और दक्षिणी रोशनी) पैदा कर सकता है और संचार प्रणालियों को बाधित कर सकता है। अधिक शक्तिशाली CME विद्युत ग्रिडों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

व्हाइट लेबल एटीएम

- व्हाइट लेबल एटीएम परंपरागत बैंक के अलावा किसी अन्य कंपनी द्वारा संचालित एटीएम हैं। यह एक ऐसी कंपनी की तरह है जो सुविधाजनक स्थानों पर एटीएम

स्थापित करने और प्रबंधन में कुशल होती है। यह कंपनी एक लाइसेंस प्राप्त बैंक (प्रायोजक बैंक) के साथ साझेदारी करती है जो नकदी प्रदान करता है और पृष्ठभूमि में वित्तीय लेनदेन का प्रबंधन करता है। व्हाइट लेबल एटीएम के उपयोग का आभास ग्राहकों को नहीं होता है, इसमें कार्ड बैंक के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। ये एटीएम को उन क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है जहां आम तौर पर बैंक एटीएम नहीं होते हैं, इससे वहां के लोगों के लिए नकदी तक पहुंच बढ़ जाती है।

डिस्कॉम

- यह वितरण कंपनियों का संक्षिप्त नाम है डिस्कॉम, भारत में बिजली वितरण की अंतिम कड़ी हैं। वे बिजली उत्पादन कंपनियों (GENCOs) से बिजली खरीदते हैं और इसे घरों, व्यवसायों और उद्योगों में वितरित करते हैं। डिस्कॉम एक तरह से खुदरा विक्रेताओं की तरह है जो आम आदमी तक बिजली की आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यदि इनमें वित्तीय संकट या अकुशलता जैसी चुनौतियाँ आती हैं, तो इससे बिजली कटौती, ब्लैकआउट और समग्र आर्थिक गतिविधि में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA)

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA) टैरिफ, कोटा और विनियमन जैसी व्यापार बाधाओं को कम करने, वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ावा देने हेतु देशों या क्षेत्रों के बीच एक समझौता है। इसका लक्ष्य खुले, प्रतिस्पर्धी बाजार बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। वे तुलनात्मक लाभ, दक्षता बढ़ाने और उपभोक्ता लाभ के आधार पर विशेषज्ञता को सक्षम बनाते हैं। FTA बौद्धिक संपदा, निवेश और नियामक सहयोग को भी शामिल करता है, जो अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करता है। इनमें घरेलू स्तर पर नौकरियों का विस्थापन, असमानता और घरेलू उद्योग पर संकट जैसी चुनौतियाँ भी पैदा होती हैं। समग्र रूप से, FTA अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए रणनीतिक उपकरण के रूप में हैं।

स्पाइवेयर

- स्पाइवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी डिवाइस में अदृश्य रहता है और निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री और टाइप किए गए कीस्ट्रोक भी चुरा सकता है। यह एक तरह से 'छिपे हुए जासूस' की तरह है इनका उपयोग हैकर्स द्वारा डाटा चुराने दुर्भावनावश किसी की गतिविधि पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। कुछ उदाहरणों में पेगासस (पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को लक्षित करना) और फिनफिशर (सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाने

हेतु) शामिल हैं। इसके लिए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या अज्ञात सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से बचना चाहिए।

पैनी स्टॉक

- पैनी स्टॉक, जिनकी कीमत सामान्यतया केवल कुछ डॉलर (या भारत में रुपये) होती है, ये सीमित ट्रेड रिपोर्ट वाली छोटी और नई कंपनियों के शेयर हैं। इसमें यदि कंपनी को लाभ होता है तो उच्च रिटर्न की संभावना रहती है लेकिन ये स्टॉक जोखिमपूर्ण भी हैं। जैसे एक नई स्थानीय रेस्तरां चैन में शेयर खरीदते हैं तो इसमें अत्यधिक लाभ भी हो सकता है और दिवालिया होने की संभावना है। इसी प्रकार पैनी स्टॉक आकर्षक होने के साथ काफी जोखिमपूर्ण भी होते हैं जिसमें पूरा निवेश भी खो सकते हैं।

सामरिक पेट्रोलियम भण्डार (SPR)

- भारत ग्लोबल तेल आपूर्ति में भू-राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय में सामरिक पेट्रोलियम भण्डार (SPR) रखता है। ये भण्डार देश भर में स्थित हैं (विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश - 1.33 MMT क्षमता, मंगलुरु, कर्नाटक - 1.5 MMT क्षमता, पादुर, कर्नाटक - 2.5 MMT क्षमता)
- इसका उपयोग प्रमुख तेल उत्पादकों से अचानक उत्पादन कटौती या मूल्य वृद्धि होने पर किया जा सकता है। यह परिवहन और बिजली उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए निरंतर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तेल आपूर्ति में वैकल्पिक स्रोतों को खोजने में सहायक है।

लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA)

- लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) एक लड़ाकू विमान है जिसे पारंपरिक भारी लड़ाकू विमानों की तुलना में छोटा, हल्का और अधिक प्रभावी बनाया गया है। यह जमीनी और हवाई हमले व प्रशिक्षण मिशनों के लिए उपयुक्त है। भारत का तेजस किफायती और तेज LCA का एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें सिंगल इंजन, डेल्टा विंग डिजाइन और कई हथियार ले जाने की क्षमता है। इसका उद्देश्य भारतीय वायु सेना को एक आधुनिक और विश्वसनीय LCA प्रदान करना के साथ साथ भारत के अधिक उन्नत स्वदेशी विमानों के विकास में योगदान देना है।

गोल्ड ETF

- गोल्ड ETF एक प्रकार का निवेश करने का तरीका है जो सोने को भौतिक रूप से खरीदने और संग्रहीत करने के बिना, अप्रत्यक्ष रूप से सोने में निवेश करने की अनुमति देता है। वे स्टॉक म्यूचुअल फंड के समान हैं, लेकिन कंपनियों के समूह में निवेश करने के बजाय, गोल्ड ETF सोने की बुलियन में निवेश करते हैं।

- गोल्ड ETF का व्यवसाय भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) जैसे स्टॉक एक्सचेंजों पर किया जाता है। गोल्ड ETF की कीमत सोने की कीमत के आधार पर परिवर्तित होती है। गोल्ड ETF स्टॉक की तरह लाभांश का भुगतान नहीं करते हैं।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)

- इसके तहत, सभी पहाड़ी जनजातियाँ, चाहे वे भारत के नागरिक हों या म्यांमार के, भारत-म्यांमार सीमा (IMB) के दोनों ओर 16 किमी के भीतर यात्रा कर सकते हैं। वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक वर्ष की वैधता वाला सीमा पास प्रस्तुत करके सीमा पार कर सकते हैं और प्रति यात्रा दो सप्ताह तक रह सकते हैं। इसे भारत-म्यांमार सीमा के किनारे रहने वाले लोगों के लिए दोनों देशों की सरकारों द्वारा 2018 में लागू किया गया था।

स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी (SKAO)

- SKAO विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक विज्ञान जानकारियों को हासिल करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण करने वाली एक अत्याधुनिक, मेगा विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सुविधा है। यूके में परिचालन मुख्यालय के साथ ऑस्ट्रेलिया (SKA-Low) और दक्षिण अफ्रीका (SKA-Mid) में स्थित, यह रेडियो खगोल विज्ञान में क्रांति ला सकता है, और नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास सुनिश्चित कर सकता है। परियोजना में शामिल पक्ष ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, इटली, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके हैं।

रिजुपेव टेक्नोलॉजी

- यह भारत के सबसे पुराने और प्रमुख सड़क अनुसंधान संगठन, CSIR-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CSIR-CRRI) द्वारा विकसित है। यह तकनीक शून्य से नीचे के तापमान की स्थिति में अधिक ऊंचाई वाली सड़कों के निर्माण में सहायता करती है। यह बर्फबारी के बीच, आवागमन के दौरान बिटुमिनस मिश्रण में नगण्य तापीय हानि के साथ बिटुमिनस मिश्रण के उत्पादन और रोलिंग तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है।

मनी लॉन्ड्रिंग

- मनी लॉन्ड्रिंग मादक पदार्थों की तस्करी या गबन जैसे अपराधों से अर्जित धन को 'वैध धन' में बदलने की अवैध प्रक्रिया है। इसमें अपराधी अवैध पैसे को स्थानांतरण या नकली व्यवसायों की एक शृंखला के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में इस तरह से प्रवेश कराते

हैं जिससे इसके स्रोत को छुपाया जा सके। यह पैसे को वैधकर देता है जिससे अपराधी इस धन बिना किसी रोक-टोक उपयोग करते हैं।

हाइब्रिड फंड

- हाइब्रिड फंड स्टॉक और बॉन्ड के मिश्रण वाले निवेश पोर्टफोलियो की तरह हैं। यह विशिष्ट जोखिम स्तरों की एक सीरीज के द्वारा बॉन्ड की स्थिरता और शेयरों में वृद्धि को संतुलित करता है। यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो निवेशक कम जोखिम के साथ निवेश करना चाहते हैं तथा स्टॉक फंडों की तुलना में कम जोखिम को प्राथमिकता देते हैं।

व्हाइट गुड्स

- व्हाइट गुड्स में रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे प्रमुख उपकरण आते हैं जो घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति कर जीवन को बेहतर बनाते हैं। व्हाइट गुड्स उद्योग अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख क्षेत्रक है, जो विनिर्माण, खुदरा और वितरण में रोजगार सृजन करता है। यह उपभोक्ता व्यय और आर्थिक वृद्धि के सन्दर्भ में भी महत्वपूर्ण कारक है।

प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO)

- प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के तहत कोई निजी कंपनी पहली बार निवेशकों को अपने शेयर बेचकर पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन जाती है। इससे कंपनी को विकास के लिए धन जुटाने में सहायता मिलती है, जबकि निवेशकों को कंपनी के एक हिस्से का स्वामित्व मिलता है और इसकी भावी सफलता का लाभ मिलता है। इसके तहत कंपनी लोगों को निवेश के द्वारा व्यवसाय में हिस्सा देने के लिए आमंत्रित करती है।

महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals)

- महत्वपूर्ण खनिज ऐसे धातु या अधातु हैं जो आधुनिक प्रौद्योगिकियों, अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इन खनिजों की उपलब्धता में कमी के कारण आपूर्ति शृंखला में बाधा उत्पन्न होती है। ये खनिज स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा प्रणालियों और अन्य उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के उदाहरणों में लिथियम, कोबाल्ट, निकल (बैटरी में प्रयुक्त), रेयर अर्थ एलिमेंट (चुंबक और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त), ग्रेफाइट (बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयुक्त), और प्लैटिनम धातु समूह (विभिन्न उद्योगों के लिए उत्प्रेरक में प्रयुक्त) शामिल हैं।

मॉडल प्रश्न

- हाल ही में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान 'आर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो' से सम्मानित किया गया?
(A) म्यांमार (B) थाईलैंड
(C) इंडोनेशिया (D) भूटान
- भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है?
(A) डॉ. सुखबीर संधू, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव
(B) अरुण मिश्रा, ज्ञानेश कुमार
(C) राजीव कुमार उत्पल कुमार सिंह
(D) ज्ञानेश कुमार, डॉ.सुखबीर संधू
- हाल ही में भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं?
(A) प्रवीण कुमार श्रीवास्तव
(B) हीरालाल सामरिया
(C) अशोक माणिकराव खानविलकर
(D) पिनाकी चंद्र घोष
- हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा समाजसेवा के क्षेत्र से किसे राज्यसभा में मनोनीत किया गया है?
(A) अन्ना हजारे (B) कैलाश सत्यार्थी
(C) सुधा मूर्ति (D) अरुणा रॉय
- हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के चेयरमैन कौन बने हैं?
(A) किशोर मकवाना
(B) हर्ष चौहान
(C) हंसराज गंगाराम अहीर
(D) अजय माणिकराव खानविलकर
- हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है?
(A) मनोज पांडे (B) सदानंद वसंत दाते
(C) प्रवीण सूद (D) अनिल चौहान
- पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
(A) शाहबाज शरीफ
(B) मरियम नवाज
(C) मोहम्मद शहाबुद्दीन
(D) आसिफ अली जरदारी
- हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं?
(A) नवाज शरीफ (B) मरियम नवाज
(C) शहबाज शरीफ (D) सैयद असीम मुनीर
- हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता?
(A) एलेक्सी नेवलनी (B) गेब्रियल एटल
(C) व्लादिमीर पुतिन (D) वोलोदिमीर जेलेन्स्की
- पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है?
(A) शरत कमल (B) पीवी सिंधु
(C) चिराग शेट्टी (D) लवलीना बोरगोहेन
- हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है?
(A) अनिल विज (B) नायब सिंह सैनी
(C) कैप्टन अभिमन्यु (D) भूपेंद्र सिंह हुड्डा
- देश के पहले और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया?
(A) हेमंत सोरेन (B) ममता बनर्जी
(C) अरविंद केजरीवाल (D) भगवंत मान
- गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौनसा बना है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका (B) यूनाइटेड किंगडम
(C) फ्रांस (D) इटली
- हाल ही में चर्चा में रहा छॉपरेशन इंड्रावती किस देश से भारतीयों की सुरक्षित वापसी हेतु चलाया गया?
(A) यमन (B) हैती
(C) रूस (D) सीरिया
- हाल ही में 'सागर प्रोजेक्ट' के तहत भारत द्वारा मॉरीशस के किस द्वीप पर मिलिट्री बेस तैयार किया गया है?
(A) अजम्पशन द्वीप (B) चांगी द्वीप
(C) डुकम द्वीप (D) अगालेगा द्वीप
- हाल ही में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कौन सा बना है?
(A) मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे
(B) आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
(C) पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
(D) द्वारका एक्सप्रेसवे
- भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य कौन बना है?
(A) ओडिशा (B) केरल
(C) गोवा (D) तेलंगाना
- भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है?

- (A) कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
(B) कोच्ची (केरल)
(C) विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)
(D) चेन्नई (तमिलनाडु)
19. भारत का पहला राज्य कौन सा है जो अपने सभी जिलों में कार्बन न्यूट्रल सीड फॉर्म (जीरो कार्बन उत्सर्जन वाले खेत) स्थापित करेगा?
(A) सिक्किम (B) अरुणाचल प्रदेश
(C) तेलंगाना (D) केरल
20. विश्व में दोहरी सड़क वाली सबसे लंबी टनल 'सेला टनल' भारत के किस राज्य में स्थित है?
(A) अरुणाचल प्रदेश (B) हिमाचल प्रदेश
(C) उत्तराखंड (D) सिक्किम
21. संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का कौनसा स्थान है?
(A) 135वाँ (B) 126वाँ
(C) 143वाँ (D) 105वाँ
22. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक (HDI) रिपोर्ट 2022 में भारत का कौनसा स्थान है?
(A) 134वाँ (B) 129वाँ
(C) 125वाँ (D) 135वाँ
23. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) द्वारा किए गए निवेश के आधार पर भारत का वैश्विक स्तर पर कौनसा स्थान है?
(A) दूसरा (B) तीसरा
(C) चौथा (D) पाँचवाँ
24. भारत के किस राज्य से पहली बार खाड़ी देशों हेतु समुद्री मार्ग से यात्रियों के लिए जहाज सुविधा शुरू की जाएगी?
(A) तमिलनाडु (B) महाराष्ट्र
(C) गोवा (D) केरल
25. हाल ही में चर्चा में रहे मंप्स रोग का संक्रमण किससे होता है?
(A) जीवाणु (B) कवक
(C) विषाणु (D) प्रोटोजोआ
26. हाल ही में चर्चा में रहा 'एनास्टो कल्स्टर' किससे संबंधित है?
(A) नासा का सूर्य मिशन
(B) बृहस्पति का नया उपग्रह
(C) नई आकाशगंगा
(D) चीन का मंगल मिशन
27. चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज हेतु मून रोवर 'वाइपर' किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा?
(A) रोसकोस्मोस (B) जाक्सा
(C) नासा (D) इसरो
28. हाल ही में बाघों के संरक्षण व उनकी लगातार निगरानी हेतु टाइगर कंजर्वेशन लैंडस्केप 3.0 (टीसीएल 3.0) किसके द्वारा विकसित किया गया है?
(A) नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, गूगल अर्थ
(B) इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, गूगल अर्थ
(C) इसरो, नासा, गूगल अर्थ
(D) रोसकॉसमॉस, इसरो, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी
29. परमाणु (Atom) के आकार से भी छोटे कणों का निरीक्षण करने और डाटा एकत्र करने हेतु विश्व की पहली न्यूट्रिनो लैब (जूनो) कहाँ स्थापित की जा रही है?
(A) जापान (B) चीन
(C) जर्मनी (D) फ्रांस
30. हाल ही में इगा स्वातेक ने टेनिस में इंडियन वेल्स का खिताब जीता है, यह किस देश से संबंधित है?
(A) इटली (B) पोलैंड
(C) स्विट्जरलैंड (D) फ्रांस
31. हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता?
(A) विदर्भ (B) मुंबई
(C) कर्नाटक (D) मध्य प्रदेश
32. नई दिल्ली में आयोजित पैरा वर्ल्ड कप 2024 में राजस्थान के किस निशानेबाज ने 10 मीटर एयर राइफल SH-1 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता?
(A) अवनी लेखारा (B) मोना अग्रवाल
(C) नेहल सिंह (D) राहुल जाखड़
33. जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा रेसक्यू और रिहैबिलिटेशन सेंटर भारत में कहाँ शुरू किया गया है?
(A) मंगलौर (कर्नाटक)
(B) गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
(C) कटक (ओडिशा)
(D) जामनगर (गुजरात)
34. भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है?
(A) मध्य प्रदेश (B) पश्चिम बंगाल
(C) तमिलनाडु (D) गुजरात
35. एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा?
(A) नई दिल्ली (B) श्रीनगर
(C) पंचकूला (D) गुरुग्राम

36. हाल ही में राजस्थान के रामगढ़ क्रेटर को देश का पहला अधिसूचित भू-विरासत स्थल घोषित किया गया, यह किस जिले में स्थित है?
(A) कोटा (B) बूंदी
(C) बारां (D) झालावाड़
37. जिला अस्पतालों में जिरिएट्रिक वार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौनसा है?
(A) राजस्थान (B) केरल
(C) महाराष्ट्र (D) गुजरात
38. नीति आयोग की तर्ज पर राजस्थान सरकार द्वारा गठित 'राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन' (रीति) का अध्यक्ष कौन है?
(A) मुख्य सचिव (B) राज्यपाल
(C) मुख्यमंत्री (D) वित्त मंत्री
39. भारत में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की जाएगी?
(A) बीकानेर (B) पठानकोट
(C) जोधपुर (D) जम्मू
40. राजस्थान में देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड कहाँ विकसित हो रहा है?
(A) किशनगढ़ (B) बालोतरा
(C) नीम का थाना (D) राजसमंद
41. हाल ही में राजस्थान के किस कवि को उनकी कृति 'पलकती प्रीत' के लिए राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
(A) कमल रंगा (B) नीलम शरण गौड़
(C) गजेसिंह राजपुरोहित (D) संजीव
42. शहरों को गारबेज फ्री (कचरा मुक्त) करने और कचरे का बेहतर ट्रांसपोर्टेशन करने हेतु केंद्र सरकार की सिटीज 2.0 योजना में राजस्थान के किन दो शहरों का चयन किया गया है?
(A) जयपुर, जोधपुर (B) अजमेर, जयपुर
(C) जोधपुर, अजमेर (D) जयपुर, उदयपुर
43. केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत विकसित राजस्थान के 3 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौनसा विकल्प शामिल नहीं है?
(A) मंडफिया (चित्तौड़गढ़)
(B) देशनोक (बीकानेर)
(C) केशोरायपाटन (बूंदी)
(D) पुष्कर (अजमेर)
44. वर्ष 2022-23 हेतु संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के कलाकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?
(A) गफरुद्दीन खान (B) वसंत काबरा
(C) दौलत राम (D) लक्ष्मण भट्ट तेलंग
45. राजस्थान में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा कहाँ स्थापित की जाएगी?
(A) जोधपुर (B) जयपुर
(C) अजमेर (D) कोटा
46. हाल ही में पोंकरण (जैसलमेर) में आयोजित भारत की तीनों सेनाओं द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास का क्या नाम है?
(A) हिंद शक्ति युद्धाभ्यास
(B) अदम्य शक्ति युद्धाभ्यास
(C) हिन्द शौर्य युद्धाभ्यास
(D) भारत शक्ति युद्धाभ्यास
47. राजस्थान का पहला टर्सरी कैंसर केयर सेंटर (TCCC) कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
(A) बीकानेर (B) जोधपुर
(C) जयपुर (D) अजमेर
48. भारत के विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) की 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार देश के तीन सबसे प्रदूषित शहरों में राजस्थान का कौनसा शहर शामिल है?
(A) हनुमानगढ़ (B) जयपुर
(C) जोधपुर (D) भिवाड़ी
49. पीएम कुसुम सी योजना के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन करने में कौनसी डिस्कॉम कंपनी देश में पहले स्थान पर रही है?
(A) जोधपुर डिस्कॉम (B) जयपुर डिस्कॉम
(C) अजमेर डिस्कॉम (D) उत्तर बिहार डिस्कॉम
50. भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्डियन' का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया?
(A) जैसलमेर (B) बाड़मेर
(C) बीकानेर (D) जोधपुर

Answer Key (March 2024)

1.	D	11.	B	21.	B	31.	B	41.	C
2.	D	12.	C	22.	A	32.	B	42.	D
3.	C	13.	C	23.	B	33.	D	43.	D
4.	C	14.	B	24.	D	34.	A	44.	A
5.	A	15.	D	25.	C	35.	B	45.	B
6.	B	16.	D	26.	C	36.	C	46.	D
7.	D	17.	B	27.	C	37.	A	47.	A
8.	C	18.	A	28.	A	38.	C	48.	A
9.	C	19.	D	29.	B	39.	C	49.	A
10.	A	20.	A	30.	B	40.	A	50.	C

Samyak

An Institute For Civil Services

संमेलन

OFFLINE व LIVE FROM CLASSROOM

RAS

FOUNDATION

05 मई (रविवार) | प्रातः 10 बजे



DISCUSSION WITH
TOPPERS & EXPERTS



PYQ'S
DISCUSSION



PRE & MAINS
SYLLABUS DISCUSSION



CUT-OFF
ANALYSIS

EXCLUSIVE BATCH FOR ENGLISH & HINDI MEDIUM

06 मई (सोमवार)
से बैच प्रारम्भ

NEAR RIDDHI
SIDDHI, JAIPUR

Contact Number
9875170111